Sitok IAS

Less Noise.
More Retention.

सप्ताह 09

25 – 31
जुलाई 2026

PIB

साप्ताहिक संक्षेप

गतिमान भारत

प्रेरणा देती विरासत। परिवर्तन लाता नवाचार। सतत प्रगति की ओर भारत।

सरनाथ
भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल

समुद्र मंथन
अपतटीय अन्वेषण से ऊर्जा सुरक्षा

स्वदेशी टर्बोजेट इंजन
आत्मनिर्भर एयरोस्पेस की बड़ी छलांग

ड्रेनवेक्स
स्वदेशी डेंगू वैक्सीन भारत की उपलब्धि

भारत 6G गठबंधन
डिजिटल नेतृत्व की ओर कदम

कुशा & AEW&C Mk-II
रक्षा क्षमताओं को मजबूती

ऊर्जा, अवसंरचना और सतत भविष्य
भारत की आशा, विश्व का विश्वास

· Less Noise. More Retention. ·

यूपीएससी मुख्य परीक्षा | लक्ष्य 2027

Table of Contents

SARNATH — INSCRIBED ON UNESCO WORLD HERITAGE LIST 5

सरल व्याख्या 6
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 6
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 7

SAMUDRA MANTHAN — RS 84,084 CRORE NATIONAL OFFSHORE EXPLORATION SCHEME 7

सरल व्याख्या 7
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 8
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 8

PM SURYA SAROVAR YOJANA — FLOATING SOLAR + STORAGE ON RESERVOIRS 9

सरल व्याख्या 9
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 10
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 10

PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) AMENDMENT BILL 2026 11

सरल व्याख्या 11
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 11
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 12

INDIA'S EXPORTS REACH RECORD $863.1 BILLION IN FY2025-26 13

सरल व्याख्या 13
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 13
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 14

INDIA RISES FROM 82ND TO 57TH IN GLOBAL PRO-COMPETITIVE REFORMS RANKING 14

सरल व्याख्या 14
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 15
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 15

MAHANADI WATER DISPUTE — CHHATTISGARH-ODISHA SETTLEMENT FACILITATED 16

सरल व्याख्या 16
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 16
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 17

INS NIPUN — SECOND INDIGENOUS DIVING SUPPORT VESSEL DELIVERED 18

सरल व्याख्या 18
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 18

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 19

INS MACHILIPATNAM — 7TH MAHE-CLASS ASW SHALLOW WATER CRAFT LAUNCHED 19

सरल व्याख्या 19
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 20
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 20

FAVARA-UPI CROSS-BORDER PAYMENT CORRIDOR — MALDIVES AND INDIA 21

सरल व्याख्या 21
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 21
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 22

SINTERED RARE EARTH PERMANENT MAGNET (REPM) SCHEME — CRITICAL MINERALS + EV MOTORS 23

सरल व्याख्या 23
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 23
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 24

LEGRAA — AI-BASED LEGAL RESEARCH ASSISTANT FOR INDIA'S COURTS 24

सरल व्याख्या 24
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 25
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 26

DAANVEER — DIGITAL INFRASTRUCTURE INITIATIVE FOR INDIA'S GRAM PANCHAYATS 26

सरल व्याख्या 26
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 26
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 27

SAF + CORSIA — INDIA'S AVIATION DECARBONISATION STRATEGY 28

सरल व्याख्या 28
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 28
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 29

ATMANIRBHAR PANCHAYAT PROGRAMME + SAMARTH PORTAL — FISCAL EMPOWERMENT OF PRIS 30

सरल व्याख्या 30
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 30
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 31

SOWA-RIGPA — SIXTH SCHEDULE AREAS, AYUSH, AND TRADITIONAL TIBETAN MEDICINE 32

सरल व्याख्या 32
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 32

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 33

BHARAT MARITIME INSURANCE POOL (BMIP) — P&I INSURANCE PRODUCT LAUNCHED 34

सरल व्याख्या 34
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 34
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 35

NBA ACCESS AND BENEFIT SHARING — RS 24 LAKH TO COTTON FARMERS AND BIODIVERSITY BOARDS 36

सरल व्याख्या 36
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 36
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 37

VANDE BHARAT TRANSPORTS DONOR HEART — SURAT TO AHMEDABAD IN 26 MINUTES 38

सरल व्याख्या 38
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 38
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 39

TOY SECTOR TASK FORCE — 5% GLOBAL MARKET SHARE BY 2032 40

सरल व्याख्या 40
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 40
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 41

INDIA'S FIGHT TO COMBAT HEPATITIS — PIB BACKGROUNDER, NVHCP 8 YEARS 42

सरल व्याख्या 42
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 42
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 43

INDIA LEADS THE WILDERNESS — TIGER CONSERVATION PIB BACKGROUNDER, GLOBAL TIGER DAY 44

सरल व्याख्या 44
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 44
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 45

INDIA AS A TOURISM HUB — PIB BACKGROUNDER 46

सरल व्याख्या 46
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 46
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 47

PM VIDYALAXMI SCHEME — COLLATERAL-FREE HIGHER EDUCATION LOANS 48

सरल व्याख्या 48
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 48

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 49

START-UP VILLAGE ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME (SVEP) — RURAL MICRO-ENTERPRISE SUPPORT 50

सरल व्याख्या 50
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 50
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 51

THE MAKING OF A SPORTING NATION — PIB BACKGROUNDER, CWG 2026 CONTEXT 52

सरल व्याख्या 52
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 52
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 53

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR (AMENDMENT) BILL 2026 54

सरल व्याख्या 54
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 54
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 55

KALPASAR PROJECT — GUJARAT'S ESTUARY DAM, TIDAL POWER, AND FRESHWATER RESERVOIR 56

सरल व्याख्या 56
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 56
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 57

GREEN HYDROGEN MISSION — 12 PILOT PROJECTS, 70 HYDROGEN VEHICLES ACROSS 21 ROUTES 58

सरल व्याख्या 58
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 58
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 59

VIKSIT VIBRANT VILLAGE PROGRAMME 2026 — BORDER VILLAGE DEVELOPMENT 60

सरल व्याख्या 60
महत्त्वपूर्ण शब्दावली: 60
UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु: 61

अभ्यास प्रश्न 62

10 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न—UPSC प्रारूप 62
आदर्श उत्तरों सहित 2 मुख्य परीक्षा प्रश्न 65
प्रारंभिक परीक्षा—उत्तर एवं व्याख्या 66

SARNATH — INSCRIBED ON UNESCO WORLD HERITAGE LIST

मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय / भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

PIB तिथि: 25 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लगभग 10 किमी मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह सरनाथ है - वह जगह जहां सिद्धार्थ गौतम, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आया और पांच शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। वह पहला उपदेश - जिसे धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त अर्थात धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है - बौद्ध धर्म की मूलभूत घटना है। इस क्षण से, बौद्ध धर्म दुनिया के महान धर्मों में से एक में बढ़ गया, अंततः एशिया भर में फैल गया और अरबों लोगों के जीवन को छू गया। सरनाथ में धामेक स्तूपा (500 सीई में बनाया गया था, जो धर्म के सटीक स्थान को चिह्नित करता है), धर्मराजिका स्तूपा के खंडहर, अशोका स्तंभ (मूल, जिसका शेर कैपिटल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है), मुलागंध कुटी विहार, और एक असाधारण समृद्ध संग्रहालय दुनिया में मौर्य कला का बेहतरीन संग्रह है। पीएम मोदी ने भारत के 43 वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शिलालेख के रूप में प्रसन्नता व्यक्त की - सरनाथ भारत की प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए जिसमें ताज महल, अजन्ता-एलोरा गुफाएं, हम्पी और अन्य शामिल हैं। शिलालेख यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन (1972) की सांस्कृतिक श्रेणी में है, जो विश्व सभ्यता के लिए असाधारण महत्व की साइट के रूप में सरनाथ के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को पहचानने में मदद करता है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 (UNESCO World Heritage Convention 1972)	सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि; भारत ने 1977 की पुष्टि की; अंकित साइटों को कम से कम 10 मानदंडों (C1-C6 सांस्कृतिक, N7-N10 प्राकृतिक) से मिलना चाहिए।
उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (Outstanding Universal Value—OUV)	यूनेस्को की मुख्य अवधारणा - एक साइट में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या प्राकृतिक महत्व होना चाहिए जो राष्ट्रीय सीमाओं का अनुवाद करता है; 10 मानदंड OUV को परिभाषित करते हैं
धमेक स्तूप (Dhamek Stupa)	सरनाथ में बेलनाकार स्तूप; 500 सीई; बुद्ध के प्रथम उपदेश के सटीक स्थान को चिह्नित करता है; 43.6 मीटर लंबा; आधार पर 28 मीटर व्यास; बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र संरचनाओं में से एक
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त (Dhammacakkappavattana Sutta)	मोशन में धर्म का पहिया स्थापित करना - सरनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश; पंचावगी (पांच शिष्यों) को दिया गया; चार नोबल ट्रुथ और आठ गुना पथ स्थापित किया।
अशोक का सिंहशीर्ष (Lion Capital of Ashoka)	सरनाथ में अशोक के स्तंभ की मूल राजधानी; चार शेर वापस-टू-बैक; 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया; इसके आधार से अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर है।
भारत की विश्व धरोहर स्थल (India's World Heritage Sites)	भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं - 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 2 मिश्रित; इटली (58), चीन (57), जर्मनी (52) के बाद दुनिया में 4th सबसे ज्यादा

सरनाथ संग्रहालय (Sarnath Museum)	सरनाथ में पुरातात्विक संग्रहालय; 1910 की स्थापना हुई; लायन कैपिटल (मूल), गुप्ता-era बुद्ध मूर्तियों, अशोका स्तंभ टुकड़े; भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक संग्रहालयों में से एक

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सरनाथ चार सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है: Lumbini (birth), Bodh Gaya (enlightenment), Sarnath (first sermon), Kushinagar (death/parinirvana) - भारत में चार चार तीर्थ स्थलों में से तीन हैं।
- सरनाथ के लिए यूनेस्को शिलालेख मानदंड: सांस्कृतिक मानदंड (i) मानव रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, (ii) समय भर मानव मूल्यों का महत्त्वपूर्ण आदान-प्रदान, (vi) सीधे उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व की घटनाओं से जुड़े - बुद्ध का पहला उपदेश
- Dhamek Stupa निर्माण: Mauryan अवधि (मूल), पुनर्निर्माण गुप्त अवधि (500 सीई); बेलनाकार आकार असामान्य - अधिकांश stupas hemispherical हैं; देर से गुप्त शैली में पुष्प डिजाइन और मानव आंकड़ों के साथ नक्काशी
- सरनाथ में अशोक स्तंभ: सम्राट अशोका (304-232 बीसीई) ने अपने साम्राज्य में धम्म को फैलाने के लिए स्तंभों का निर्माण किया; सरनाथ स्तंभ बेहतरीन है; अब सरनाथ संग्रहालय में राजधानी; शाफ्ट अभी भी साइट पर दिखाई दे रहा है।
- राष्ट्रीय प्रतीक कनेक्शन: भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सरनाथ से शेर कैपिटल है; 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया; देवनगरी शिलालेख Satyameva जयते (Truth Alone Triumphs) Mundaka Upanishad से है, बौद्ध नहीं — Emblem में जोड़ा गया।
- भारत की 43 वां विश्व विरासत स्थल: पिछले स्थलों में ताज महल (1983), अजंता गुफाएं (1983), एलोरा गुफाएं (1983), कुतुब मीनार (1993), हुमायून का मकबरा (1993), सन टेम्पल कोनार्क (1984), ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (2014), ढोलवीरा (2021), होयसाला मंदिर (2023) शामिल हैं।
- बौद्ध सर्किट पर्यटन: सारनाथ का शिलालेख भारत के बौद्ध सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देता है (Lumbini-Bodh Gaya-Sarnath-Kushinagar गलियारा); थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, वियतनाम से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थयात्रियों पर लक्षित
- एएसआई क्षेत्राधिकार: सरनाथ एएसआई के तहत केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक है; यूनेस्को शिलालेख अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय जांच दायित्व बनाता है - बफर ज़ोन के भीतर किसी भी विकास के लिए यूनेस्को अधिसूचना की आवश्यकता होती है।

SAMUDRA MANTHAN — Rs 84,084 CRORE NATIONAL OFFSHORE EXPLORATION SCHEME

मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

नाम पूरी तरह से चुना जाता है। समुद्र मंथन - समुद्र मंथन - प्राचीन हिंदू मिथक है जहां देवताओं और राक्षसों ने अमृत (अमरता का रस) और गहरे से अन्य खजाने निकालने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन किया। 31 जुलाई को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित भारत की 84,084 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के नीचे स्थित खजाने के लिए भारत के गहरे समुद्र में वास्तविक मंथन जैसा एक अन्वेषण अभियान है। भारत में EEZ का 2.02 मिलियन वर्ग किमी है - दुनिया के सबसे बड़े में से एक - लेकिन अपने अपतटीय अवसादी

बेसिन के केवल 10% की खोज की है। भारत के अधिकांश अपतटीय अन्वेषण को मुंबई हाई में केंद्रित किया गया है (जो 1974 में तेल की खोज की थी और 1976 के बाद से उत्पादन किया गया है) और कृष्ण-Godavari बेसिन (KG-D6, Reliance क्षेत्र जो 2002 में बड़े पैमाने पर गैस भंडार पाया गया था)। लेकिन भारत के पश्चिमी गहरे पानी के बेसिन (कुच, सौराष्ट्र), अंडमान-निकोबार ऑफशोर, केरल-कोंकण बेसिन, और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों को समाप्त कर दिया गया। समुद्र मंथन ने इसे भूकंपीय सर्वेक्षणों, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग और 26 अंडर-एक्सप्लोर्ड ऑफशोर बेसिनों में डेटा अधिग्रहण के लिए 10 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपये प्रदान करके बदल दिया; एक नया नियामक ढांचा तेजी से अनुमोदन को सक्षम बनाता है; गहरे पानी और अति गहरे पानी के अन्वेषण (3,000+ मीटर गहराई) के लिए विशेष प्रोत्साहन जहां जोखिम उच्चतम है लेकिन संभावित पुरस्कार सबसे बड़ा हैं।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
समुद्र मंथन (समुद्र मंथन)	राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना; 84,084 करोड़ रुपये; कैबिनेट ने 31 जुलाई को मंजूरी दे दी; भारत के 26 अंडर-एक्सप्लोर्ड बेसिनों में अपतटीय तेल / गैस अन्वेषण के लिए 10 साल का कार्यक्रम
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone—EEZ)	क्षेत्र भारत के तटरेखा से 200 समुद्री मील का विस्तार; भारत ने अपने ईईजेड के भीतर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और उसका शोषण करने के अधिकार को संप्रभु बना दिया है; 2.02 मिलियन वर्ग किमी
मुंबई हाई (Mumbai High)	भारत का सबसे बड़ा ऑफशोर ऑयलफील्ड; 1974 की खोज की; महाराष्ट्र का पश्चिमी तट; ओएनजीसी द्वारा संचालित; ~ 300,000 बैरल / दिन पैदा करता है; उम्र के कारण उत्पादन में गिरावट
KG-D6 बेसिन (KG-D6 Basin)	कृष्णा-Godavari डीप-वाटर ब्लॉक D6; रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित; बंगाल की खाड़ी; 2002 में दुनिया की सबसे बड़ी गैस खोज की; उत्पादन में काफी उतारा गया है
अवसादी बेसिन (Sedimentary Basin)	भूवैज्ञानिक गठन जहां जैविक सामग्री को लाखों वर्षों में तेल/गैस में जमा, दफनाया गया और परिवर्तित किया गया था; भारत में 26 सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान की गई है; केवल 7 पर्याप्त रूप से जांच की गई थी।
खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (Open Acreage Licensing Policy—OALP)	भारत की वर्तमान नीति जहां कंपनियां सरकारी घोषित राउंड की प्रतीक्षा के बजाय किसी भी ऑफशोर ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती हैं; समुद्र मंथन ओएएलपी के तहत ब्लॉक लाइसेंसिंग में तेजी लाते हैं।
मीथेन हाइड्रेट्स (Methane Hydrates)	आइस-जैसे क्रिस्टलीय संरचनाएं गहरे समुद्र तल में मीथेन गैस को फँसाती हैं; भारत का ईईजेड 1,894 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर - कई बार वैश्विक पारंपरिक गैस भंडार रखने का अनुमान है; अभी तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत की आयात निर्भरता: भारत 87% कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 50% आयात करता है; वार्षिक आयात बिल 10-12 लाख करोड़ रुपये; आयात में हर 10% की कमी = 1-1.2 लाख करोड़ रुपये बचाया - समुद्र मंथान का रणनीतिक तर्क

- 26 बेसिन: भारत में 26 सेडिमेंटरी बेसिन हैं - 7 पर्याप्त रूप से पता लगाया गया (मुंबई हाई, केजी बेसिन, असम शेल्फ आदि); 7 आंशिक रूप से पता लगाया गया; 12 unexplored - समुद्र मंथन लक्ष्य 19 inadequately पता लगाया गया।
- दीप जल क्षमता: भारत के गहरे पानी के ब्लॉकों में तेल और गैस के बराबर अनुमानित 20-30 बिलियन बैरल होते हैं; इन की खोज करने के लिए विशेषीकृत रिग (सेमी-सबर्सिबल्स, ड्रिलशिप) की आवश्यकता होती है जिसकी लागत $300,000-500,000/day है - सरकार ने समुद्र मंथन के माध्यम से इस जोखिम को साझा किया है।
- ओएनजीसी + निजी क्षेत्र: ओएनजीसी सरकारी स्थान पर ब्लॉकों में अन्वेषण का नेतृत्व करेगा; संयुक्त उद्यम के लिए आमंत्रित निजी कंपनियों (रिलायंस, ओएनजीसी विदेश, विदेशी कंपनियों) को आमंत्रित किया जाता है; समुद्र मंथन उन भूकंपीय डेटा को प्रदान करता है जो निजी निवेश को जोखिम में डालती हैं।
- मीथेन हाइड्रेट: भारत दुनिया के नेताओं में से एक है मीथेन हाइड्रेट अनुसंधान (ओएनजीसी का एनजीएचपी कार्यक्रम); यदि 2040-50 तक व्यावसायीकरण किया जाता है, तो भारत में मीथेन हाइड्रेट भारत को शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बना सकता है - समुद्र मंथन फंड ने अनुसंधान जारी रखा
- 84,084 करोड़ रुपये संरचना: लगभग 10 साल से अधिक 8,400 करोड़ रुपये; भूकंपीय सर्वेक्षणों (40%), एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग (45%), डेटा प्रोसेसिंग और प्रौद्योगिकी (15%) के बीच विभाजित; ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और डीजीएच एजेंसियों को लागू कर रहे हैं
- तुलना: ब्राजील के पूर्व-नमक अपतटीय अन्वेषण (2006 को उजागर किया गया, अब 3 मिलियन बैरल / दिन का उत्पादन करता है) ने ब्राजील को 20 वर्षों में निर्यातक करने के लिए तेल आयातक से बदल दिया - समुद्र मंथन भारत का समकक्ष प्रयास है।

PM SURYA SAROVAR YOJANA — FLOATING SOLAR + STORAGE ON RESERVOIRS

मंत्रालय: नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत में 5,264 बड़े बांध और हजारों छोटे जलाशय हैं - सिंचाई और जल प्रबंधन निवेश के 75 साल की विरासत। ये जलाशय पानी के भंडारण के अपने प्राथमिक उद्देश्य की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी विशाल पानी की सतहें काफी हद तक ऊर्जा परिप्रेक्ष्य से निष्क्रिय होती हैं। फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक (FPV) प्रौद्योगिकी पानी की सतह पर तैरने वाले पोंटूनों पर सौर पैनलों को रखता है, जो किसी भी अतिरिक्त भूमि का उपभोग किए बिना बिजली उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना (PM-SSY) ने 31 जुलाई को कैबिनेट द्वारा 5,070 करोड़ रुपये के आउटले के साथ मंजूरी दे दी, भारत का केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाले जलाशयों पर ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ संयुक्त फ्लोटिंग सोलर के लिए पहला समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह अन्य सौर कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह एक साथ दो समस्याओं को संबोधित करता है: सौर क्षमता के लिए भारत की बढ़ती आवश्यकता (500 GW लक्ष्य 2030) और ग्रिड स्तर के भंडारण के लिए भारत की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता (भंडारण के बिना सौर ऊर्जा केवल 8-10 घंटे / दिन उपलब्ध है; बैटरी या पंप हाइड्रो के साथ मिलकर, यह 24 घंटे तक प्रेषण योग्य हो जाता है)। यह योजना विशेष रूप से केंद्रीय एजेंसियों (एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी) के स्वामित्व वाले जलाशयों को लक्षित करती है जहां सरकार को अनुमतियों के लिए राज्य जल विभागों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक परियोजना में जलाशय की सतह पर तैरने वाले सौर पैनल होंगे, जलाशय बैंकों पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) और ग्रिड कनेक्टिविटी को पीक मांग घंटों के दौरान राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली खिलाना होगा।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
प्रधानमंत्री सूर्या सरोवर योजना (PM-SSY) (PM Surya Sarovar Yojana (PM-SSY))	5,070 करोड़ रुपये; कैबिनेट ने 31 जुलाई को मंजूरी दे दी; केंद्रीय सरकारी जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर + बैटरी स्टोरेज; पहली राष्ट्रीय फ्लोटिंग सोलर स्कीम
फ्लोटिंग सोलर पीवी (FPV) (Floating Solar PV (FPV))	सौर पैनल पानी की सतहों पर तैरने वाले pontoons पर चढ़कर; फायदे: कोई भूमि का उपयोग नहीं, जल वाष्पीकरण में कमी (10-15%), उच्च पैनल दक्षता (पानी शीतलन), कोई छाया अवरोध नहीं
BESS (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली) (BESS (Battery Energy Storage System))	बड़े पैमाने पर बैटरी बैंक जो दिन के दौरान सौर ऊर्जा को स्टोर करते हैं और पीक शाम की मांग के दौरान निर्वहन करते हैं; लिथियम आयन या लिथियम आयरन फॉस्फेट प्रौद्योगिकी; 24 घंटे तक चलने योग्य सौर ऊर्जा को सक्षम बनाता है।
जल वाष्पीकरण की बचत (Water evaporation saving)	FPV पैनल पानी की सतह को छाया देते हैं, 10-15% तक वाष्पीकरण को कम करते हैं; जल-स्कार इंडिया में महत्त्वपूर्ण पानी की बचत; बिजली उत्पादन + जल संरक्षण का दोहरे लाभ
डिस्पैचेबल पावर (Dispatchable power)	शक्ति जिसे मांग पर / बंद स्विच किया जा सकता है; भंडारण के बिना सौर गैर-डिस्पैचेबल है (केवल सूर्य चमक पर उपलब्ध); सौर + BESS = डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी - जैसा कि कोयला संयंत्र के रूप में विश्वसनीय है)
एनएचपीसी / एनटीपीसी / एनएलसी / एसजेवीएन (NHPC / NTPC / NLC / SJVN)	सेंट्रल पीएसयू ऑपरेटिंग हाइड्रोपावर, थर्मल और लिग्नाइट प्लांट; उनके पास बड़े जलाशय भी हैं; पीएम-एसएसवाई फ्लोटिंग सौर तैनाती के लिए इन मौजूदा जलाशयों का उपयोग करता है
केरल का बनासुर सागर (Kerala's Banasura Sagar)	भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट (500 किलोवाट, 2017); PM-SSY ने इसे सभी केंद्रीय जलाशयों में GW स्तर तक पहुंचाया।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का जलाशय सतह क्षेत्र: 5,264 बड़े बांधों में पानी की सतह के ~3.5 मिलियन हेक्टेयर होते हैं; यहां तक कि 1 मेगावाट / हेक्टेयर = 350 जीडब्ल्यू क्षमता पर फ्लोटिंग सोलर के लिए 10% (350,000 हेक्टेयर) का उपयोग भी किया जाता है - भारत की पूरी वर्तमान सौर क्षमता से अधिक
- जल संरक्षण: भारत गर्म राज्यों में सालाना वाष्पीकरण के लिए जलाशय जल का 20-40% खो देता है; फ्लोटिंग सोलर पैनल सतह को छाया देते हैं, वाष्पीकरण को कम करते हैं; राजस्थान और गुजरात जलाशयों को लाभ होगा
- PM-SSY लक्ष्य: 5,070 करोड़ रुपये 20-25 केंद्रीय जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर + BESS विकसित करेंगे; अनुमानित 2-3 GW फ्लोटिंग सौर क्षमता; 1-2 GWh बैटरी भंडारण; बहुत बड़े राष्ट्रीय रोलआउट के लिए पायलट

- भंडारण आयाम: भंडारण के बिना, सौर ऊर्जा शाम की चोटी की मांग (6-10 PM) की सेवा नहीं कर सकती है जब घरों और उद्योग को सबसे अधिक बिजली की आवश्यकता होती है; PM-SSY की BESS यह सुनिश्चित करता है कि जब इसकी आवश्यकता होती है तो सौर बिजली उपलब्ध हो जाती है, न केवल जब यह उत्पन्न होती है, तब भी नहीं।
- ग्रिड स्थिरता: बड़े BESS प्रणाली ग्रिड के लिए सहायक सेवाएं (आवृत्ति विनियमन, वोल्टेज समर्थन) प्रदान कर सकती है - ग्रिड को अक्षय प्रवेश के रूप में अधिक स्थिर बनाती है।
- लागत प्रक्षेपवक्र: फ्लोटिंग सौर लागत 5 वर्षों में 60% गिर गई है (8 करोड़ रुपये / मेगावाट से 3.5 करोड़ रुपये / मेगावाट तक); BESS लागत 20% / वर्ष गिरती है; PM-SSY को अपनी परियोजना जीवनकाल के भीतर कोयला शक्ति के साथ लागत-प्रतियोगिता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) AMENDMENT BILL 2026

मंत्रालय: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

PIB तिथि: 29th-30th जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत की परीक्षा प्रणाली को एक आवर्ती संकट: कागज लीक द्वारा plagued किया गया है। 2024 में नीट यूजी (मेडिकल प्रवेश परीक्षा) पेपर परीक्षा से पहले लीक हो गया, जो 24 लाख छात्रों को प्रभावित करता है जिन्होंने साल की तैयारी की थी। यूजीसी-नेट पेपर उसी वर्ष लीक हो गया, जिससे परीक्षा रद्द हो गई। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा ने बार-बार दुर्व्यवहार आरोपों को खारिज कर दिया है। ये मामूली असुविधा नहीं हैं - वे अपराध हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से लाखों छात्रों से अवसर चुराते हैं जो वर्षों तक ईमानदारी से अध्ययन करते हैं, जबकि उम्मीदवार जो लीक किए गए कागजात खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं उन्हें अनुचित लाभ मिलता है। सार्वजनिक परीक्षा (Unfair Means) अधिनियम, 2024 परीक्षा कदाचार के खिलाफ भारत का पहला समर्पित कानून था - यह 3-10 साल की कैद की सजा के साथ पेपर लीक को अपराधी ठहराया गया और संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क के लिए 1-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। सार्वजनिक परीक्षा (Unfair Means) संशोधन विधेयक, 2026 - 30 जुलाई को लोकसभा द्वारा पारित और 30 जुलाई को राज्यसभा - इस कानून को चार तरीके से मजबूत बनाता है: (1) यह अपने महत्व के तहत सभी राज्य सरकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को लाता है; (2) यह बढ़ी हुई सजा के साथ एक विशिष्ट अपराध को प्रतिरूपित करता है; (3) यह 24 घंटे के भीतर उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए परीक्षा अधिकारियों के लिए एक दायित्व बनाता है; और (4) यह एक स्थायी निरीक्षण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता बोर्ड (NEIB) की स्थापना करता है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 (Public Examinations Act 2024)	मूल कानून आपराधिक कागज लीक; 3-10 साल का कैद; 1-10 करोड़ रुपये जुर्माना; कवर यूपीएससी, एसएससी, एनटीए परीक्षा; 2026 संशोधन विस्तार और इस मजबूत
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) (National Testing Agency (NTA))	NEET-UG, JEE, UGC-NET, CUET का संचालन करता है; 1,000+ करोड़ रुपये वार्षिक बजट; 30 मिलियन + टेस्ट लेने वाले / वर्ष; NEET-UG 2024 पेपर लीक ने मूल 2024 अधिनियम को शुरू किया और अब 2026 संशोधन

एनईआईबी (राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता बोर्ड) (NEIB (National Examination Integrity Board))	2026 संशोधन द्वारा बनाई गई नई स्थायी निकाय; सभी सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा की निगरानी; डिजिटल निगरानी, बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण और ओएमआर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानकीकृत करता है।
प्रतिरूपण अपराध (किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देना; Impersonation offence)	किसी और के नाम में परीक्षा के लिए प्रकट होना; संगठित प्रतिव्यक्तित्व के छल्ले मौजूद हैं; 2026 संशोधन इस एक विशिष्ट, अलग-अलग दंडनीय अपराध बनाता है।
राज्य परीक्षाओं में शामिल (State examinations included)	2024 अधिनियम केवल केंद्रीय परीक्षाओं को कवर किया गया; 2026 संशोधन सभी राज्य सरकार प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बढ़ा देता है - राज्य पीएससी, राज्य भर्ती बोर्ड अब कवर कर रहे हैं
24 घंटे रिपोर्टिंग दायित्व (24-hour reporting obligation)	परीक्षा अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर NEIB को किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करनी चाहिए; रिपोर्टिंग में देरी यह थी कि कैसे NEET-UG 2024 लीक एक संकट बन गया
NEET-UG 2024 प्रभाव (NEET-UG 2024 impact)	24 लाख छात्रों को प्रभावित; 1,563 छात्रों को सही 720/720 स्कोर (statistically anomalous); सीबीआई जांच; कागज Hazaribagh, झारखंड के लिए पता चला; एकाधिक गिरफ्तारी; ट्रिगर राजनीतिक संकट

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- विधान इतिहास: भारत के पास 2024 से पहले कोई समर्पित परीक्षा अखंडता कानून नहीं था; कदाचार आईपीसी अनुभागों (चेटिंग, फोरगरी) के तहत मुकदमा चलाया गया था; ये आयोजन अपराध नेटवर्क ऑपरेटिंग पेपर लीक सिंडिकेट के लिए अपर्याप्त थे।
- ऑर्गनाइज़्ड अपराध आयाम: भारत में पेपर लीक में नेटवर्क का आयोजन किया जाता है - प्रिंटर के कर्मचारी पेपर चोरी करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी प्रश्न सेट बेचते हैं, व्हाट्सएप आधारित वितरण; 100-200 करोड़ रुपये उद्योग; उम्मीदवारों ने कागजात के लिए 10-30 लाख रुपये का भुगतान किया
- NEIB संरचना: कार्मिक मंत्रालय के तहत स्थायी शरीर; सचिव रैंक के अध्यक्ष; साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, पूर्व शिक्षा सचिव, कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं; परीक्षा अधिकारियों की जांच के लिए सुओ मोटू शक्ति है
- राज्य परीक्षाओं का महत्व: भारत में अधिकांश प्रतियोगी नौकरियां राज्य सरकार की परीक्षा के माध्यम से हैं; उन्हें NEIB ओवरसाइट के तहत लाने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के 90% तक कानून की पहुंच को बढ़ाता है।
- डिजिटल परीक्षा पुश: NEIB 2028 तक सभी प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाओं के लिए डिजिटल परीक्षा (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) को जनादेश देगा; कागज आधारित परीक्षाओं को समाप्त करता है जहां भौतिक पेपर चोरी संभव है।
- पीएम की कार्यबल: संशोधन विधेयक से अलग; परीक्षा सुधारों पर उच्च शक्ति वाले कार्य बल एनटीए की संरचना की समीक्षा करेंगे, सुझाव दें कि नीट यूजी को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए या नहीं, और दीर्घकालिक परिवर्तन की सिफारिश करें।
- अनुच्छेद 16 कनेक्शन: सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार (आर्किल 16) सीधे कागजी लीक से कम हो जाता है - संशोधन विधेयक एक संवैधानिक दायित्व है, न केवल एक नीति विकल्प

INDIA'S EXPORTS REACH RECORD $863.1 BILLION IN FY2025-26

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / डीजीसीआई और एस

PIB तिथि: 28 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत का कुल निर्यात - व्यापार (अच्छा) प्लस सेवाएं - FY2025-26 में एक रिकॉर्ड $863.1 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के $ 770 बिलियन से लगभग 12% बढ़ गया। यह मील का पत्थर भारत को दृढ़ता से 2030 तक अपने $ 2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य की ओर एक बेदखलदारी पर रखता है। $ 863.1 बिलियन आंकड़े: व्यापारिक निर्यात लगभग $ 442 बिलियन (इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन, फार्मा, वस्त्र, रत्न और आभूषण, कृषि उत्पाद); सेवाएं निर्यात लगभग $ 421.3 बिलियन (आईटी / बीपीओ, वित्तीय सेवाएं, पेशेवर सेवाएं) थे - पहली बार $ 421 बिलियन को पार करना। सेवाएं अब लगभग व्यापारिक निर्यात के बराबर हैं, जो भारत के परिवर्तन को एक महत्त्वपूर्ण ज्ञान अर्थव्यवस्था निर्यातक में दर्शाते हैं। इस साल प्रमुख ड्राइवर: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 35 बिलियन डॉलर (मोबाइल फोन निर्यात - एप्पल आईफोन, सैमसंग द्वारा संचालित); फार्मा $ 27 बिलियन में मजबूत निर्यात करता है; इंजीनियरिंग सामान $110 बिलियन तक बढ़ गया; आईटी सेवा $200+ बिलियन। तीन सबसे बड़े निर्यात गंतव्य - संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया - विविधीकरण रणनीति और व्यापार समझौतों को दर्शाता है (UK के साथ CETA ने 2022 से ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA के साथ संयुक्त अरब अमीरात के साथ 15 जुलाई, CEPA में प्रवेश किया)।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
$863.1 बिलियन कुल निर्यात ($863.1 billion total exports)	FY2025-26 रिकॉर्ड; merchandise $442 बिलियन + सेवाएं $421 बिलियन; 12% विकास योय; 2030 लक्ष्य तक $ 2 ट्रिलियन के लिए ट्रैक पर
मर्चेंडाइज निर्यात (Merchandise exports)	भौतिक वस्तुओं का निर्यात: इंजीनियरिंग ($110B), इलेक्ट्रॉनिक्स ($35B), रसायन ($32B), फार्मा ($27B), रत्न / आभूषण ($38B), कपड़ा ($38B), कृषि ($55B)
सेवाएं निर्यात (Services exports)	FY2025-26 में $ 421.3 बिलियन; आईटी / बीपीओ सेवाएं प्रमुख ($200B +); व्यापार सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल पर्यटन में बढ़ रहा है; भारत 4 सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक है
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S)	वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी निदेशालय - कोलकाता; भारत के व्यापार सांख्यिकी को संकलित करता है; मासिक निर्यात आयात डेटा प्रकाशित करता है
निर्यात करने के लिए PLI योगदान (PLI contribution to exports)	PLI योजनाओं को मोबाइल फोन ($23B निर्यात), फार्मा एपीआई, विशेषता रसायनों के लिए श्रेय दिया जाता है - कुल PLI धन के निर्यात में योगदान का अनुमान 1.5 लाख करोड़ रुपये है।
$ 2 ट्रिलियन लक्ष्य 2030 तक ($2 trillion target by 2030)	भारत का व्यापार + सेवाएं निर्यात लक्ष्य; वर्तमान आधार से 15-16% वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता है; यदि FTA गति, PLI, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्जन्म जारी रहता है, तो प्राप्त करने योग्य

व्यापार घाटा (Trade deficit)	भारत का आयात भी बड़ा ($700 + अरब) है; व्यापार घाटा महत्त्वपूर्ण है; सेवाओं के अधिशेष आंशिक रूप से व्यापार घाटा

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- मीलस्टोन संदर्भ: 2014-15 में भारत का निर्यात $300 बिलियन था; $863 बिलियन 2025-26 में = 11 वर्षों में लगभग 3x; निर्यात संचालित विकास मॉडल के लिए घरेलू धारणा से संचालित आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है
- सेवाएं समानता: सेवा निर्यात ($ 421B) पहली बार के लिए लगभग व्यापारिक निर्यात ($ 442B) के बराबर है; भारत वैश्विक स्तर पर असामान्य है - अधिकांश बड़े निर्यातक व्यापारिक-भारी हैं; भारत की सेवाओं की ताकत एक प्रतिस्पर्धी लाभ है
- शीर्ष 3 गंतव्य: संयुक्त अरब अमीरात (2022) के बाद से CEPA, ब्रिटेन (जुलाई 2026) से CETA, ऑस्ट्रेलिया (2022) - सभी तीन FTA पार्टनर हैं; निर्यात भूगोल पर FTA प्रभाव प्रदर्शित करता है
- इलेक्ट्रॉनिक्स सफलता: $ 35 बिलियन इलेक्ट्रानिक्स निर्यात मोबाइल फोन द्वारा प्रभुत्व; 2020 में, भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स में $ 5 बिलियन का निर्यात किया - PLI का रूपांतरण यहां दिखाई देता है
- चीन की तुलना: चीन सालाना 3.5 ट्रिलियन डॉलर निर्यात करता है; भारत में 863 बिलियन डॉलर चीन का 25% है; हालांकि भारत की सेवाओं का निर्यात किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहा है; 2035 तक भारत अकेले सेवाओं में 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।
- भुगतान का संतुलन प्रभाव: मजबूत निर्यात प्रदर्शन रुपये को स्थिर करने में मदद करता है और बाह्य संतुलन के लिए पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह पर निर्भरता को कम करता है।

INDIA RISES FROM 82ND TO 57TH IN GLOBAL PRO-COMPETITIVE REFORMS RANKING

मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / डीपीआईआईटी

PIB तिथि: 30 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

Competere Foundation - एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान संगठन - ने अपने ग्लोबल प्रो-प्रतियोगी सुधार सूचकांक को इस सप्ताह जारी किया, जिससे भारत 82 वें से 57 वें रैंक तक पहुंच गया। एक वर्ष में 25 रैंक में सुधार किसी भी वैश्विक सूचकांक में असाधारण रूप से दुर्लभ है और भारत के नियामक वातावरण में वास्तविक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। इंडेक्स यह बताता है कि कैसे प्रभावी ढंग से एक देश प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाओं को हटा रहा है - क्या नए व्यवसाय आसानी से बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वह प्रमुख incumbents प्रभावी विनियमन का सामना करते हैं, क्या उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी कीमतों तक पहुंच सकते हैं। भारत के विशिष्ट सुधार जो कूदते हैं: प्रतियोगिता संशोधन अधिनियम 2023 (जो सीसीआई की शक्तियों को मजबूत करता है, ने विलय अधिसूचनाओं के लिए सौदा मूल्य सीमा शुरू की, और डिजिटल बाजारों के लिए विरोधी ट्रस्ट प्रावधानों को जोड़ा); दूरसंचार अधिनियम 2023 (जो नए दूरसंचार प्रवेशकर्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन और कम बाधाओं को खोलता है); जन विश्व अधिनियम 2023 (जो 42 अधिनियमों में 183 मामूली अपराधों को कम करता है); और डिजिटल वाणिज्य (ONDC) के लिए भारत का विकसित ओपन नेटवर्क जो किसी भी विक्रेता और खरीदार को एक सामान्य डिजिटल प्रोटोकॉल में लेनदेन करने में सक्षम करके ई-कॉमर्स मोनोपोलिस को तोड़ रहा है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
कॉम्पीटियर फाउंडेशन सूचकांक (Competere Foundation Index)	ग्लोबल प्रो-कॉम्पिटिटिव रिफॉर्म इंडेक्स; प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाओं को मापता है, बाज़ार प्रवेश में आसानी, विरोधी-विश्वास विनियमन की प्रभावशीलता, उपभोक्ता संरक्षण; भारत 82nd to 57th
प्रतियोगिता संशोधन अधिनियम 2023 (Competition Amendment Act 2023)	CCI शक्तियों को मजबूत करना; सौदा मूल्य सीमा शुरू की (Rs 2,000 करोड़ सौदा मूल्य ट्रिगर विलय अधिसूचना भले ही टर्नओवर थ्रेसहोल्ड पूरा नहीं हुआ); डिजिटल बाजार प्रावधान जोड़ा गया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India—CCI)	भारत के विरोधी ट्रस्ट नियामक; विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं, विलय की जांच; प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के तहत गठित; डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन में बढ़ती महत्व हासिल करना
जन विश्व अधिनियम 2023 (Jan Vishwas Act 2023)	42 अधिनियमों में 183 मामूली अपराधों को अस्वीकार करना; तकनीकी नियामक उल्लंघन के लिए दंड के लिए जेल की शर्तों को परिवर्तित करना; छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को काफी कम करना
ONDC (डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क) (ONDC (Open Network for Digital Commerce))	डिजिटल वाणिज्य के लिए भारत का खुला प्रोटोकॉल; फ्लिपकार्ट / अमेज़न का एकाधिकार तोड़ता है; कोई भी विक्रेता किसी भी खरीदार-फेसिंग ऐप पर सूचीबद्ध हो सकता है; भुगतान में यूपीआई की सफलता पर मॉडलिंग किया गया
सौदा मूल्य सीमा (Deal value threshold)	जब सौदा मूल्य 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो CCI विलय अधिसूचना शुरू हो जाती है; विशेष रूप से बड़े डिजिटल अधिग्रहण पर कब्जा करने के लिए डिज़ाइन किया गया जो पहले विरोधी ट्रस्ट समीक्षा से बच गए थे।
बाजार प्रतियोगिता (Market contestability)	आर्थिक अवधारणा: क्या बाजारों में आसानी से प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं; भारत की रैंकिंग में सुधार नियामक सुधारों के माध्यम से उच्च प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- प्रतियोगिता अधिनियम 2002: भारत का प्राथमिक विरोधी ट्रस्ट कानून; यूरोपीय संघ प्रतियोगिता कानून मॉडल के आधार पर; CCI ने 2009 का गठन किया; कार्टेलाइज़ेशन, प्रभुत्व के दुरुपयोग, विरोधी प्रतिस्पर्धी विलय को प्रतिबंधित करता है।
- डिजिटल बाजार विनियमन: प्रतियोगिता संशोधन अधिनियम 2023 ने 'सही डिजिटल उद्यमों' के लिए प्रावधानों को जोड़ा - बड़े उपयोगकर्ता बेस या नेटवर्क प्रभाव वाली कंपनियां; पहली बार भारत की प्रतियोगिता कानून स्पष्ट रूप से डिजिटल मोनोपोलिस को संबोधित करती है।
- जन विश्व अधिनियम श्रेणियां: खाद्य व्यवधान (खनिज मामले), पर्यावरण अनुपालन (प्रक्रियात्मक), श्रम कानून (खनिज उल्लंघन), पेटेंट पंजीकरण देरी में अपराधों को अस्वीकार करना - व्यवसाय अब कागजी कार्रवाई त्रुटियों के लिए आपराधिक अभियोजन का डर नहीं है

- ONDC प्रभाव: अमेज़ॅन / फ्लिपकार्ट के प्रभुत्व को तोड़कर, ONDC ई-कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है; छोटे व्यापारी अब किसी भी ऐप (Paytm, PhonePe, Meesho) के माध्यम से बेच सकते हैं न केवल अमेज़न / फ्लिपकार्ट
- 82th to 57th: 25 रैंकों की कूद वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे बड़ा एकल वर्ष सुधारों में से एक है; इस साल G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा
- निवेश कनेक्शन: प्रो-प्रतियोगी सुधार → प्रविष्टि के लिए कम बाधाएं → अधिक व्यापार निवेश → अधिक नौकरियां → अधिक निर्यात; $863 बिलियन निर्यात रिकॉर्ड और इस रैंकिंग में सुधार को कसकर जुड़े हुए हैं।

MAHANADI WATER DISPUTE — CHHATTISGARH-ODISHA SETTLEMENT FACILITATED

मंत्रालय: गृह मंत्रालय / जल शक्ति मंत्रालय

PIB तिथि: 30 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

महानादी ओडिशा की जीवन रेखा है। नदी छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों में पैदा हुई, 858 किमी बहती है, और समुद्र तक पहुंचने से पहले ओडिशा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बहती है - हिराकुद बांध से गुजरती है। ओडिशा ने महानादी के आसपास अपनी पूरी कृषि अर्थव्यवस्था बनाई है: हिराकुद जलाशय पश्चिमी ओडिशा में 1.2 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई करता है, नदी लाखों मछुआरों का समर्थन करती है, और डेल्टा भारत के सबसे उत्पादक चावल उगाने वाले क्षेत्रों में से एक है। विवाद: छत्तीसगढ़ ने 2000 के बाद ऊपरी महानादी पर कई बार और बांध बनाए - अपने किसानों को सिंचाई करने के लिए पानी की कटाई संरचना। ओडिशा ने शिकायत की कि इन अपस्ट्रीम संरचनाओं को हिराकुद तक पहुंचने वाले प्रवाह को कम कर दिया गया था। विवाद को महानादी जल विवादों से पहले लंबित किया गया था (इंटर-स्टेट रिवर वाटर विवाद अधिनियम 1956 के तहत 2018 का गठन) बिना संकल्प के। इस सप्ताह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रीों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और एक प्रारंभिक निपटान ढांचे को सुविधाजनक बनाया - दोनों राज्यों ने सहमति व्यक्त की: एक आम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वास्तविक समय में नदी प्रवाह डेटा साझा करें; छत्तीसगढ़ निर्दिष्ट निगरानी स्टेशनों पर न्यूनतम प्रवाह बनाए रखेगा; एक संयुक्त तकनीकी समिति मौजूदा संरचनाओं का आकलन करेगी; और दोनों राज्यों को किसी भी नए जल भंडारण निर्माण से पहले परामर्श मिलेगा।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
महानदी नदी (Mahanadi River)	858 किमी; शुरू हुआ सिहावा, छत्तीसगढ़; ओडिशा के माध्यम से बहती है; पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में बहती है; हिराकुद बांध इसका सबसे बड़ा जलाशय है; पूर्वी भारत की प्रमुख नदी
हिराकुद बांध (Hirakud Dam)	सम्बलपुर, ओडिशा; 1957 का निर्माण; दुनिया में सबसे लंबे समय तक मिट्टी के बांध (26 किमी) जिसमें डाइक शामिल हैं); जलाशय 5.8 बिलियन घन मीटर की दुकानों को स्टोर करता है; 347.5 मेगावाट उत्पन्न करता है; 1.2 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई करता है।

महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल (Mahanadi Water Disputes Tribunal)	अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित 2018; कार्यवाही धीमी हो गई है; इस सप्ताह की सुविधाजनक रूपरेखा तत्काल राहत उपायों के लिए न्यायाधिकरण को बायपास करती है
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 (Inter-State River Water Disputes Act 1956)	न्यायाधिकरण के लिए राज्यों के बीच नदी के जल विवादों को रोकने के लिए प्रदान करता है; अनुच्छेद 262 बार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र; न्यायाधिकरण दशकों ले जा सकते हैं (Cauvery Tribunal 17 साल ले लिया)
न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (Minimum environmental flow)	न्यूनतम जल प्रवाह जिसे अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए हर समय नदी में बनाए रखा जाना चाहिए; निपटान ढांचे के हिस्से के रूप में सीजी और ओडिशा के बीच सहमति व्यक्त की गई।
संविधान का अनुच्छेद 262 (Article 262 of Constitution)	संसद अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को निंदा कर सकती है; सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है; यही कारण है कि अंतरराज्यीय नदी विवाद न्यायाधिकरण के लिए जाते हैं, अदालत नहीं
रीयल-टाइम डेटा साझा करना (Real-time data sharing)	प्रमुख निपटान तत्व; ओडिशा के साथ लाइव फ्लो डेटा साझा करने के लिए छत्तीसगढ़ में निगरानी स्टेशनों पर नदी पर आईओटी सेंसर; इस बारे में विवादों को रोकता है कि क्या छत्तीसगढ़ पानी को अलग कर रहा है?

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- महानादी विवाद समयरेखा: ओडिशा ने शिकायत 2016 दायर की; महानादी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने 2018 का गठन किया; कार्यवाही चल रही है; इस सप्ताह के मंत्रिस्तरीय सुविधा न्यायाधिकरण के बाहर है लेकिन इसे प्रतिस्थापित नहीं करती है।
- हिराकुद बांध महत्व: निर्मित 1957; 17 मिलियन लोग सिंचाई और पीने के पानी के लिए इस पर निर्भर करते हैं; हिराकुद जलाशय भी एक प्रमुख मत्स्य संसाधन है; 2 लाख+ मछुआरे इस पर निर्भर करते हैं।
- अनुच्छेद 262: संसद अंतरराज्यीय नदी जल विवादों को निंदा कर सकती है; सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाहर कर सकती है; स्मारक के लिए अद्वितीय संवैधानिक प्रावधान
- छत्तीसगढ़ की स्थिति: छत्तीसगढ़ का तर्क है कि डाउनस्ट्रीम प्रवाह करने से पहले अपने क्षेत्र में वर्षा जल का उपयोग करने का अधिकार है; महाराष्ट्र की कैचमेंट का 80%+ छत्तीसगढ़ में है; अपस्ट्रीम अधिकार बनाम डाउनस्ट्रीम की जरूरत है कोर तनाव है।
- ओडिशा की स्थिति: पूर्व अनुमान के अंतर्राष्ट्रीय जल कानून सिद्धांत - हिराकुद पहले (1957) का निर्माण किया गया था और ओडिशा ने उम्मीद नदी के प्रवाह के आसपास अपनी कृषि प्रणाली को डिजाइन किया; इन प्रवाहों को कम करने वाले अपस्ट्रीम परिवर्तन अयोग्य हैं।
- दोनों भाजपा राज्यों: छत्तीसगढ़ और ओडिशा भाजपा के नियम हैं; सहभागी राज्यों के बीच केंद्र-सफल निपटान राजनीतिक रूप से आसान है; Narmada और Kishau बस्तियों के अनुरूप पैटर्न
- कावेरी के साथ तुलना: कावेरी विवाद (कर्नाटक-तमिलनाडु) ने अदालत और न्यायाधिकरण में दशकों का समय लिया; यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, कार्यान्वयन विवाद जारी रहे; महानादी की सुविधा से निपटारे का दृष्टिकोण तेजी से साबित हो सकता है लेकिन राजनीतिक सद्भाव पर निर्भर करता है।

INS NIPUN — SECOND INDIGENOUS DIVING SUPPORT VESSEL DELIVERED

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय नौसेना

PIB तिथि: 30 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

महासागर का फर्श युद्ध और अर्थशास्त्र दोनों के लिए तेजी से महत्त्वपूर्ण है। अंडरसी केबल दुनिया के इंटरनेट और वित्तीय डेटा का 95% ले जाते हैं। अंडरसी पाइपलाइनों में तेल और गैस होती है। सबमरीन केबलों को खुफिया के लिए टैप किया जा सकता है। अंडरवाटर माइन्स, अनपेक्षित आयुध, और दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी को पुनर्प्राप्त या तटस्थ करने की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों को विशेष जहाजों की आवश्यकता होती है जो गहरे समुद्र के संचालन में मानव गोताखोरों और पानी के नीचे दूरस्थ रूप से संचालित वाहनों (ROVs) का समर्थन कर सकते हैं। आईएनएस निप्पन - भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसलों (DSVs) का दूसरा हिस्सा इस सप्ताह भारतीय नौसेना को दिया गया। पहला डीएसवी आईएनएस नीस्टार था, जिसे 2023 में वितरित किया गया था। साथ में, आईएनएस नीस्टार और आईएनएस निप्पन भारत को एक दोहरी पोत गहरी समुद्र डाइविंग क्षमता देते हैं जो पहले एक एकल उम्र बढ़ने वाले पोत तक ही सीमित थे। आईएनएस निप्पन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा बनाया गया है और संतृप्ति डाइविंग ऑपरेशन (जहां विस्तारित अवधि के लिए 300 मीटर तक की गहराई पर रहते हैं और काम करते हैं) का समर्थन कर सकते हैं, पानी के नीचे निरीक्षण और बचाव के लिए ROVs को तैनात करते हैं, और पनडुब्बी आपात स्थिति के लिए खोज और बचाव समर्थन प्रदान करते हैं। आईएनएस सिंधुराक्षक त्रासदी (2013, जहां 18 नाविकों को पनडुब्बी विस्फोट में मृत्यु हो गई) के दौरान तेजी से पानी के नीचे बचाव को माउंट करने में भारत की अक्षमता को उजागर किया गया - आईएनएस निप्पन सीधे इस अंतर को संबोधित करते हैं।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
आईएनएस निपुण (INS Nipun)	दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल; कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया; संतृप्ति डाइविंग (300 मीटर गहराई), आरओवी तैनाती, पनडुब्बी बचाव का समर्थन करता है; जुलाई 2026 को वितरित किया गया
डीएसवी (डिविंग सपोर्ट वेसल) (DSV (Diving Support Vessel))	विशेषीकृत जहाज गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए जीवन समर्थन, उपकरण और विघटन की सुविधा प्रदान करता है; 200-300 मीटर गहराई पर संतृप्ति डाइविंग और पानी के नीचे के संचालन को सक्षम बनाता है।
संतृप्ति गोताखोरी (Saturation Diving)	डाइविंग तकनीक जहां गोताखोर सतह पर एक दबाव वाले आवास में रहते हैं, हीलियम-ऑक्सीजन मिश्रण को सांस लेते हैं, और बार-बार विघटन के बिना विस्तारित अवधि (दिन / सप्ताह) के लिए गहराई पर काम करते हैं।
आरओवी (रिमोटली ऑपरेटेड वाहन) (ROV (Remotely Operated Vehicle))	मानव रहित अंडरवाटर वाहन सतह जहाज के लिए tethered; कैमरों, मैनिपुलेटर हथियारों, सेंसरों से लैस; निरीक्षण, बचाव, खान निकासी, और केबल / पाइपलाइन रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है
DSRV (डीप सबमरीन बचाव वाहन) (DSRV (Deep Submarine Rescue Vehicle))	विशेष बचाव पनडुब्बी जो समुद्र तल पर एक विकलांग पनडुब्बी के साथ मिल सकती है और सुरक्षा के लिए चालक दल को स्थानांतरित कर सकती है; भारत 1 DSRV (UK, 2018 से प्राप्त); आईएनएस निप्पन DSRV तैनाती का समर्थन करता है

समुद्रतलीय केबल (Undersea cables)	200+ अंडरसी केबल्स भारत को दुनिया से जोड़ते हैं; भारत केबल तोड़फोड़ के प्रति संवेदनशील है; DSV केबल क्षति का निरीक्षण और मरम्मत कर सकता है।
सीएसएल (कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड) (CSL (Cochin Shipyard Limited))	भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शिपयार्ड; आईएनएस विक्रांत (एयरक्राफ्ट कैरियर, 2022) भी बनाया गया; आईएनएस निस्टार और निप्पन शो सीएसएल की क्षमता विशेष जहाजों के लिए सतह के जहाजों से परे फैली हुई है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का पनडुब्बी बेड़े: 15-16 परिचालन पनडुब्बी; परियोजना 75I के तहत 2030 तक 24 पनडुब्बी तक बढ़ रहा है; DSV इस विस्तारित बेड़े के लिए आवश्यक समर्थन करता है
- आईएनएस सिंधुराक्षक त्रासदी (2013): डीजल पनडुब्बी ने मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में आग और सैंक को पकड़ लिया; 18 नाविकों की मृत्यु हो गई; पर्याप्त DSV और DSRV क्षमता की कमी का मतलब कोई बचाव संभव नहीं था; आईएनएस निपुन सीधे इस अंतर को संबोधित करता है
- निस्टार बनाम निप्पन: आईएनएस नीस्टार (DSV 1) ने 2023 को दिया; आईएनएस निप्पन (DSV 2) ने जुलाई 2026 को दिया; दो DSV - पश्चिमी तट के लिए एक, बंगाल के पूर्वी / बे के लिए एक
- दीप-सी खनन: भारत के ईईजेड में 4,000-6,000 मीटर गहराई पर पर्याप्त पॉलीमेटलिक नोड्यूल (कॉपर, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज युक्त) होता है; डीएसवी इन संसाधनों के अन्वेषण और अंतिम खनन का समर्थन करता है
- अंडरसी केबल सुरक्षा: रेड सी हौथी हमलों में अंडरसी इंटरनेट केबल्स (2024) काटने शामिल थे; मुंबई, चेन्नई, कोच्चि में भारत के प्रमुख अंडरसी केबल लैंडिंग स्टेशन हैं; आईएनएस निप्पन भारतीय जल में केबलों की मरम्मत का निरीक्षण और समर्थन कर सकते हैं।
- परियोजना 75I: भारत की अगली पीढ़ी के पनडुब्बी अधिग्रहण (6 उन्नत वायु-स्वतंत्र प्रस्ताव के साथ पारंपरिक पनडुब्बी); 2030 तक कुल 24-पनडुब्बियों का लक्ष्य; आईएनएस निप्पन इस विस्तार बेड़े के लिए पर्याप्त समर्थन बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करता है

INS MACHILIPATNAM — 7TH MAHE-CLASS ASW SHALLOW WATER CRAFT LAUNCHED

मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय / भारतीय नौसेना / एल एंड टी जहाज निर्माण

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

हम आईएनएस Agray (5th, week 4) और आईएनएस मालवान (6th, week 8) को अर्नाला / Mahe-class Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft series के कवर किया। इस सप्ताह, आईएनएस Machilipatnam - इस वर्ग के 7 वें पोत - शुरू किया गया था (अब तक कमीशन नहीं किया गया); 'लॉन्ड' का मतलब है कि hull पहली बार पानी में प्रवेश करता है; समुद्री परीक्षणों और फिटिंग के बाद कमीशनिंग का अनुसरण करता है)। आईएनएस Machilipatnam का नाम आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है - भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक, Qutb Shahi का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र और बाद में ब्रिटिश युग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना पहला भारतीय कारखाना यहां था (1605)। इस वर्ग के लिए नामकरण सम्मेलन - अर्नाला, Agray, Malvan, Machilipatnam - भारत के 7,500 किमी तटरेखा के साथ भारत के तटीय समुद्री विरासत को दर्शाता है, ऐतिहासिक बंदरगाहों, द्वीपों और नौसेना स्टेशनों का सम्मान करता है। इस

वर्ग के लिए कमीशनिंग पाइपलाइन भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे तेजी से है: सभी 8 जहाजों को 2019 में अनुबंधित किया गया था, निर्माण 2021 में शुरू हुआ था, और सभी 8 को 2027 तक कमीशन करने की उम्मीद है। अब 8 जहाजों में से 7 के साथ लॉन्च या कमीशन किया गया है, भारत निर्माण कर रहा है कि भारत के तटीय और निकटवर्ती अंडरसी डोमेन पर हावी करने के लिए एक जानबूझकर रणनीतिक विकल्प है, जो विशेषीकृत विरोधी पनडुब्बी उथले जल शिल्प का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़े होगा।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
आईएनएस मछलीपट्टनम (INS Machilipatnam)	7th Mahe-class (Arnala-class) ASW Shallow Water Craft; जुलाई 2026 शुरू किया; L&T जहाज निर्माण, Kattupalli, Tamil Nadu; ऐतिहासिक AP बंदरगाह शहर के नाम पर
लॉन्च बनाम कमीशनिंग (Launch vs Commissioning)	लॉन्च: पहली बार hull तैरना; पोत अभी तक परिचालन नहीं; कमीशनिंग: पोत को औपचारिक रूप से फिटिंग, समुद्री परीक्षणों और चालक दल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नौसेना में शामिल किया गया।
माहे-श्रेणी नामकरण (Mahe-class nomenclature)	वर्ग को अर्नाला (महाराष्ट्र द्वीप) और मह (केरल तटीय शहर) दोनों के नाम पर रखा गया है; 8 जहाजों का कुल नाम ऐतिहासिक भारतीय तटीय स्थानों के नाम पर रखा गया है।
एल एंड टी जहाज निर्माण (L&T Shipbuilding)	लार्सेन एंड टुब्रो के रक्षा जहाज निर्माण विभाग; कटुपल्ली पोर्ट, तमिलनाडु; 4 में से 8 अर्नाला-क्लास (GRSE कोलकाता दूसरी इमारत) का निर्माण किया; भारत में सबसे बड़ा निजी रक्षा जहाज बिल्डर
मछलीपट्टनम/मसूलीपट्टनम (Machilipatnam/Masulipatnam)	ऐतिहासिक बंदरगाह शहर, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश; भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक; डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना पहला भारतीय कारखाना यहां था (1605); Machilipatnam Kalamkari कपड़ा कला के लिए प्रसिद्ध
ASW SWC क्षमता (ASW SWC capability)	एंटी-सबमरीन वारफेयर शालो वाटर क्राफ्ट; पानी में पनडुब्बियों का शिकार <200 मीटर गहराई; उथले ऑपरेशन के लिए वाटरजेट प्रणोदन; डंकिंग सोनार, टारपीडो, एंटी-सब रॉकेट; 750 टन विस्थापन
8-vessel कार्यक्रम समयरेखा (8-vessel programme timeline)	अनुबंधित 2019; निर्माण 2021; प्रक्षेपण / कमीशन 2024-2027; 6 साल के तहत सभी 8 जहाजों - विशेष नौसैनिक जहाजों के लिए असाधारण निष्पादन गति

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- नामकरण महत्व: मचिलिपत्तनम डच औपनिवेशिक व्यापार (1605) के साथ भारत के पहले मुठभेड़ की साइट थी; इसकी नौसेना विरासत इसे भारत के तटीय संप्रभुता की रक्षा के लिए एक युद्धपोत नाम बनाती है।
- 8-vessel तर्क: भारत में 7,500 किमी तटरेखा + 1,382 द्वीप हैं; 2 प्रमुख नौसेना कमांड (पश्चिमी: मुंबई, पूर्वी: विशाखापत्तनम) + दक्षिणी कमांड (कोच्चि); 8 ASW SWCs 3-4 प्रति कमांड प्लस रोटेशनल रखरखाव / रिफिट सुनिश्चित करता है।

- Waterjet propulsion: ASW SWCs propellers के बजाय वाटरजेट का उपयोग करते हैं; वॉटरजेट पानी में 1-2 मीटर के रूप में काम कर सकते हैं; पोत को बहुत उथले बंदरगाह, estuaries, और तटीय पानी में प्रवेश करने की अनुमति देता है जहां पनडुब्बी भारत के बंदरगाहों के पास घूम सकती है।
- पाकिस्तान की पनडुब्बी खतरे: पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों को अभ्यास के दौरान भारतीय तटीय जल में प्रवेश करने का प्रयास किया गया है; अर्नाला वर्ग एसडब्ल्यूसी ने उथले पानी के दृष्टिकोण में उनका पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया है।
- श्रृंखला कमीशन वेग: आईएनएस अग्रे (जून 2026) + आईएनएस मालवान (जुलाई 2026) + आईएनएस मैचिलिपत्तनम लॉन्च (जुलाई 2026) - भारत ने 2026 में लगभग हर किले नाइट में नौसैनिक पोत को कमीशन या लॉन्च किया
- कलामकरी कनेक्शन: मचिलिपत्तनम कलामकरी के लिए भी प्रसिद्ध है - पारंपरिक हाथ से पेंट / ब्लॉक मुद्रित कपास कपड़ा कला; एक भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त; शहर की समुद्री और सांस्कृतिक विरासत इसे प्रतीकात्मक रूप से समृद्ध बनाती है।

FAVARA-UPI CROSS-BORDER PAYMENT CORRIDOR — MALDIVES AND INDIA

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय / एनपीसीआई अंतर्राष्ट्रीय / भारतीय रिजर्व बैंक

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से भारतीय पर्यटकों और भारतीय वस्तुओं पर बनाई गई है। इस सप्ताह से पहले, एक मालदीव व्यवसाय के मालिक को एक भारतीय पर्यटक से भुगतान प्राप्त करने के लिए महंगे अंतरराष्ट्रीय तार अंतरण, क्रेडिट कार्ड भुगतान (2-3% व्यापारी शुल्क के साथ) या नकदी का उपयोग करना पड़ा। फवारा - एक मालदीव फिनटेक कंपनी जो देश के घरेलू भुगतान अवसंरचना का संचालन करती है - 31 जुलाई को प्रत्यक्ष यूपीआई-टू-फावारा क्रॉस-बॉर्डर भुगतान गलियारा के साथ रहते थे। इसका मतलब है: एक भारतीय पर्यटक अपने BHIM, Google पे या PhonePe ऐप को खोल सकता है, मालदीव रिसॉर्ट या दुकान पर एक क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है, और रुपये में भुगतान कर सकता है - सिस्टम स्वचालित रूप से मालदीव Rufiyaa को अंतर बैंक दर पर भुगतान में परिवर्तित कर देता है और व्यापारी के Favara खाते को श्रेय देता है। कोई मुद्रा विनिमय नहीं, कोई छिपी हुई फीस नहीं, कोई 2-3 दिन का निपटान इंतजार नहीं। यह एक सुविधा कहानी से अधिक है। इंडिया-मालदीव FTA (पहले दौर सप्ताह में संपन्न हुआ 7) के लिए व्यापार को सक्षम करने के लिए भुगतान अवसंरचना की आवश्यकता होती है; यूपीआई-फावारा भुगतान अवसंरचना है। मालदीव के साथ भारत का राजनयिक रीसेट एक आर्थिक एंकर की जरूरत है; यूपीआई एकीकरण एक बनाता है - मालदीव के कारोबार में अब भारत के साथ चिकनी संबंधों को बनाए रखने में एक भौतिक वित्तीय रुचि है। भारत के लिए, यह 11वां देश है जहां यूपीआई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है, जो भारत की भुगतान प्रौद्योगिकी का एक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में निरंतर विस्तार जारी रखता है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
फवारा भुगतान प्रणाली (Favara)	मालदीव फिनटेक कंपनी; मालदीव के घरेलू भुगतान अवसंरचना को संचालित करती है; यूपीआई-फावारा क्रॉस-बॉर्डर कॉरिडोर के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ भागीदारी की।

यूपीआई-फावारा कॉरिडोर (UPI-Favara corridor)	डायरेक्ट क्रॉस-बॉर्डर भुगतान: इंडियन यूपीआई ऐप → स्कैन मालदीव व्यापारी का क्यूआर कोड → भुगतान ऑटो-कन्वर्ट्ड रुपया से Rufiaa → व्यापारी के Favara खाते में श्रेय दिया गया; रीयल-टाइम निपटान
मालदीवी रुफिया (Rufiyaa—MVR)	मालदीव Rufiyaa - आधिकारिक मुद्रा; विनिमय दर लगभग 5.2 रुपए प्रति Rufiyaa; पहले भारत-मालदीव भुगतान के लिए अमेरिकी डॉलर के अंतर की आवश्यकता; अब प्रत्यक्ष रुपया-Rufiyaa
एनपीसीआई इंटरनेशनल (NPCI International)	अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई तैनाती के लिए एनपीसीआई की सहायक कंपनी; विदेशी भुगतान प्रणालियों के साथ साझेदारी; संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, मालदीव आदि में द्विपक्षीय भुगतान गलियारों का प्रबंधन करता है।
भारत-मालदीव व्यापार (India-Maldives trade)	$ 400 मिलियन द्विपक्षीय व्यापार; भारत मालदीव का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; मालदीव के खाद्य आयात का 60% + भारत से आता है; यूपीआई एकीकरण इस व्यापार के लिए घर्षण को कम करता है
मालदीव के लिए भारतीय पर्यटक (Indian tourists to Maldives)	भारत लगातार मालदीव का #1 पर्यटन स्रोत देश है; सालाना 2+ लाख भारतीय पर्यटक; यूपीआई भुगतान रिसोर्ट में मुद्रा विनिमय की आवश्यकता को हटा दें
रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण (Rupee internationalisation)	भारत का व्यापक लक्ष्य व्यापार निपटान के लिए रुपया एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए; यूपीआई कॉरिडोर नरम रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण बनाते हैं - अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता के बिना सीधे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में उपयोग किए जाने वाले रुपया

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 11 यूपीआई देश: संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरीशस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, ब्रिटेन, मलेशिया, ग्रीस (Week 8), और अब मालदीव - प्रत्येक नया देश नेटवर्क प्रभाव को जोड़ता है; अधिक देश = भारतीय यात्रियों और डायस्पोरा के लिए अधिक उपयोगी हैं।
- रुपया-Rufiyaa प्रत्यक्ष निपटान: पहले भारत-मालदीव भुगतान रुपए → अमेरिकी डॉलर → Rufiaa (दो मुद्रा रूपांतरण, दो सेट फीस); अब रुपए → Rufiyaa सीधे; लगभग 3-5% लेनदेन लागत बचत
- राजनयिक समय: भारत-Maldives FTA पहले दौर का समापन हुआ (Week 7); Favara-UPI जीना (इस सप्ताह); राजनयिक सामान्यीकरण आर्थिक एकीकरण द्वारा समर्थित - हिंद महासागर के पड़ोसियों के साथ भारत की लगातार प्लेबुक
- मालदीव आर्थिक लाभ: मालदीव पर्यटन जीडीपी अपनी अर्थव्यवस्था का 80%+ है; भारतीय पर्यटक सबसे बड़ा स्रोत हैं; यूपीआई एकीकरण भारत के आर्थिक लाभ को स्थायी और डिजिटल बनाता है
- फिनटेक कूटनीति: पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-यूएई वास्तविक समय भुगतान लिंक; फ्रांस दौरे पर भारत-फ्रांस यूपीआई लॉन्च किया गया; भारत-मालदीव फवारा-UPI एक ही पैटर्न का अनुसरण करता है - डिजिटल भुगतान एकीकरण एक राजनयिक प्रसव योग्य के रूप में
- आरबीआई ओवरसाइट: क्रॉस-बॉर्डर यूपीआई लेनदेन अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के लिए आरबीआई के कानूनी ढांचे के माध्यम से जाते हैं; आरबीआई और मालदीव दोनों मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) ने गलियारे को मंजूरी दी

SINTERED RARE EARTH PERMANENT MAGNET (REPM) SCHEME — CRITICAL MINERALS + EV MOTORS

मंत्रालय: भारी उद्योग मंत्रालय

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन में मोटर होती है। सबसे कुशल ईवी मोटर्स - टेस्ला, BYD, हुंडई, टाटा नेक्सॉन ईवी में उपयोग किया जाता है, और अधिकांश आधुनिक ईवी - नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और प्रियोडिमियम - दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM) का उपयोग करते हैं। ये चुंबक समान वजन के लिए पारंपरिक लौह मैग्नेट की तुलना में 5-10 गुना अधिक शक्तिशाली हैं, यही कारण है कि वे उच्च टोक़, हल्के, कुशल ईवी मोटर्स को सक्षम करते हैं। समस्या: चीन दुनिया के प्रसंस्कृत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का 85-90% और दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक का 70%+ उत्पादन करता है। भारत में हर ईवी मोटर - चाहे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, या बजाज द्वारा बनाई गई हो - चीनी मैग्नेट का उपयोग करती है। यह निश्चित रूप से आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता की तरह है जिसे हथियारीकृत किया जा सकता है: एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान 2010 में जापान को दुर्लभ पृथ्वी निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे वैश्विक आतंक पैदा हो गया। इस सप्ताह भारी उद्योग मंत्रालय ने सिंटर्ड दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (REPM योजना) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत वैश्विक निविदा के लिए बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी। REPM योजना उन कंपनियों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है जो भारत में sintered NdFeB (Neodymium Iron Boron) मैग्नेट का निर्माण करती हैं; वैश्विक चुंबक निर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा; और घरेलू कच्चे सामग्री सोर्सिंग के लिए मंत्रालय के महत्त्वपूर्ण खनिज ढांचे तक पहुंच।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
सिन्टर्ड दुर्लभ-मृदा स्थायी चुंबक (Sintered REPM)	Sintered दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक; Neodymium (Nd), आयरन (Fe), बोरॉन (B) - NdFeB चुंबक से बनाया गया; sintering (संपीड़न और हीटिंग दुर्लभ पृथ्वी पाउडर) द्वारा उत्पादित; सबसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक प्रकार
NdFeB चुम्बक (NdFeB magnet)	Neodymium आयरन बोरॉन चुंबक; 1982 की खोज की; स्थायी चुंबक का सबसे मजबूत प्रकार; कॉम्पैक्ट, हल्के, उच्च टोक़ ईवी मोटर्स सक्षम बनाता है
दुर्लभ-मृदा तत्व (Rare Earth Elements—REE)	17 तत्वों सहित neodymium, dysprosium, praseodymium, cerium; चीन वैश्विक REE प्रसंस्करण का 85% नियंत्रित करता है; भारत में महत्त्वपूर्ण भंडार (6th वैश्विक स्तर पर) लेकिन सीमित प्रसंस्करण है
चीन की 2010 REE निर्यात प्रतिबंध (China's 2010 REE export restriction)	2010 सेंककू द्वीप विवाद के दौरान चीन ने जापान को 40% तक दुर्लभ पृथ्वी निर्यात में कटौती की; जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो उद्योग ने गंभीर रूप से बाधित किया; सीधे वैश्विक आरईईई आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण को प्रेरित किया

EV मोटर प्रकार (EV motor types)	दो मुख्य प्रकार: स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर (PMSM) - REPM, सबसे कुशल का उपयोग करता है; प्रेरण मोटर (IM) - कोई चुंबक नहीं, कम कुशल; अधिकांश भारतीय EVs PMSM का उपयोग करते हैं
रक्षा चुम्बक (Defence magnets)	REPM रक्षा में महत्त्वपूर्ण हैं: मिसाइलों (अकाश, कुशा), रडार मोटर्स, सोनार ट्रांसड्यूसर, ड्रोन मोटर्स के लिए मार्गदर्शन प्रणाली; REPM के लिए चीन पर रक्षा निर्भरता एक प्रत्यक्ष रणनीतिक भेद्यता है।
REPM योजना (REPM scheme)	घरेलू NdFeB चुंबक विनिर्माण के लिए PLI-type प्रोत्साहन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा; विस्तारित बोली समयरेखा वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी निविदा डिजाइन करने का सुझाव देता है

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का REE रिजर्व: भारत में 6.9 मिलियन टन REE आरक्षित (6th वैश्विक स्तर पर); मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश (monazite-bearing beach sand), राजस्थान (Bastnaesite जमा); REPM योजना डाउनस्ट्रीम को संबोधित करती है जबकि क्रिटिकल मिनरल नीलामी अपस्ट्रीम को संबोधित करती है।
- ईवी मोटर की मांग: भारत का 2030 ईवी लक्ष्य = 3 करोड़ ईवी / वर्ष; प्रत्येक ईवी मोटर 1-3 किलोग्राम एनडीएफईबी चुंबक का उपयोग करता है; 3 करोड़ ईवी = 30,000-90,000 टन आरईपीएम की मांग सालाना; वर्तमान में भारत चीन से 100% आयात करता है
- रक्षा महत्त्वपूर्ण आयाम: कुशा LRSAM (Week 8) साधक REPM का उपयोग करता है; क्योंकि भारत स्वदेशी मिसाइलों का निर्माण करता है, चीनी REPM पर निर्भरता एक रणनीतिक भेद्यता है - REPM योजना इस पते को संबोधित करती है।
- जापान का अनुभव: चीन के 2010 प्रतिबंध के बाद, जापान ने REE रीसाइक्लिंग, वैकल्पिक चुंबक अनुसंधान और विदेशी REE खनन में बड़े पैमाने पर निवेश किया; REPM योजना भारत का समकक्ष पहला कदम है।
- PLI-type प्रोत्साहन: REPM योजना PLI पर मॉडलिंग; 5 वर्षों में प्रदर्शन-लिंक्ड भुगतान; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा जापानी कंपनियों (TDK, Shin-Etsu), जर्मन (वैक्यूमस्सेल्ज़), या अमेरिकी निर्माताओं के साथ जुड़ती है।
- पुनर्चक्रण क्षमता: एंड ऑफ लाइफ ईवी मोटर्स, हार्ड ड्राइव, पवन टरबाइन जेनरेटर में आरईपीएम होते हैं जिन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है; भारत का बढ़ता ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स स्क्रैप घरेलू आरईई रीसाइक्लिंग उद्योग का निर्माण करेगा।

LegRAA — AI-BASED LEGAL RESEARCH ASSISTANT FOR INDIA'S COURTS

मंत्रालय: कानून और न्याय मंत्रालय / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत की अदालतों में 5 करोड़ लंबित मामले हैं। न्यायाधीश एक मामले पर सुनवाई करते हैं, कहते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक संपत्ति विवाद को जानने की आवश्यकता हो सकती है: प्रतिकूल कब्जे पर सभी प्रासंगिक फैसले क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति मामलों में सीमा अवधि के बारे में क्या कहा है? इन सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए वर्तमान में हजारों मामले रिपोर्टों के माध्यम से मैनुअल खोज की आवश्यकता होती

है - एक कार्य जो घंटों या दिनों का होता है। LegRAA (Legal Research Analysis assistant) - eCourts के लिए उत्कृष्टता केंद्र के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवीजन द्वारा विकसित - भारत के कोर्ट सिस्टम के भीतर तैनात एक एआई संचालित कानूनी अनुसंधान उपकरण है। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित एक बड़ी भाषा मॉडल पर बनाया गया है: (1) सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के फैसले (सभी डेटाबेस दशकों वापस जा रहा है); (2) सभी केंद्रीय अधिनियमों और नियमों का पाठ नंगे; (3) भारत का संविधान और इसकी व्याख्या। एक न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी एक प्राकृतिक भाषा क्वेरी का प्रकार है - 'आर्थिक अपराधों के लिए प्रत्याशा जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या है?' - और LegRAA ने निर्णयों के विशिष्ट पैराग्राफों का हवाला देते हुए, सबसे प्रासंगिक मामला कानून का विश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण किया। यह सिर्फ एक खोज इंजन नहीं है - यह तर्क संश्लेषण करता है और न्यायिक पदों को विकसित करने की पहचान करता है। वर्तमान में LegRAA को न्यायाधीशों और उनके शोध सहायकों के लिए एक आंतरिक उपकरण के रूप में तैनात किया गया है; यह अभी तक litigants या जनता के लिए उपलब्ध नहीं है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
एआई-आधारित विधिक अनुसंधान सहायक (LegRAA)	कानूनी अनुसंधान विश्लेषण सहायक; एनआईसी द्वारा निर्मित एआई उपकरण; एससी / एचसी निर्णयों, अधिनियमों, संविधान पर प्रशिक्षित; प्राकृतिक भाषा प्रश्नों के माध्यम से शोध निर्णयों का न्याय करने में मदद करता है; कोर्ट सिस्टम के भीतर तैनात
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC (National Informatics Centre))	भारत सरकार की आईटी शाखा; MeitY के तहत; CPGRAMS, NeSDA, eCourts portal, PFMS सहित भारत के प्रमुख ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों को विकसित किया; AI डिवीजन ने LegRAA विकसित किया
eCourts मिशन मोड परियोजना (eCourts Mission Mode Project)	भारत के न्यायालयों (चरण I 2007, फेज II 2015, फेज III 2023-27) की डिगिटिसेशन ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जिस पर LegRAA संचालित होता है।
बड़ी भाषा मॉडल (LLM) (Large Language Model (LLM))	एआई मॉडल विशाल टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित; प्राकृतिक भाषा को समझ सकता है और उत्पन्न कर सकता है; LegRAA भारतीय कानूनी ग्रंथों पर विशेष रूप से ठीक-ट्यून का उपयोग करता है - चैटजीपीटी जैसे सामान्य एलएलएम से अलग
5 करोड़ लंबित मामले (5 crore pending cases)	भारत के न्यायिक बैकलॉग: 5 करोड़+ मामले सभी अदालतों में लंबित; सुप्रीम कोर्ट: 80,000+; उच्च न्यायालय: 60 लाख+; जिला न्यायालय: 4.4 करोड़+; LegRAA अनुसंधान में तेजी लाती है, संभावित रूप से प्रति मामले में समय कम हो जाती है।
न्यायालय दक्षता में सहायता हेतु सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल (SUPACE)	सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी - SC का अपना AI पोर्टल; LegRAA उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को AI अनुसंधान सहायता प्रदान करके SUPACE का पूरक करता है।
न्यायिक पूर्व-निर्णय अनुसंधान (Judicial precedent research)	भारतीय कानून बहुत पहले आधारित है (सितारा decisis); एक न्यायाधीश को कानून के प्रत्येक बिंदु पर पूर्व निर्णयों को जानना चाहिए; हजारों निर्णयों के माध्यम से मैनुअल रिसर्च एक प्रमुख bottleneck है; LegRAA इस बात को स्वचालित करता है

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- SUPACE बनाम LegRAA: SUPACE (Supreme Court) मामले प्रबंधन और दस्तावेज़ प्रसंस्करण पर केंद्रित है; LegRAA (NIC, अदालतों में) विशेष रूप से कानूनी अनुसंधान और पूर्ववर्ती पहचान पर केंद्रित है - पूरक, प्रतिस्पर्धा नहीं करना
- न्याय आयाम तक पहुंच: शुरू में केवल न्यायाधीशों के लिए कानूनी सहायता वकीलों (Tele-Law, DISHA 2.0 कवरेज) के लिए भविष्य के संस्करणों की योजना बनाई ताकि उन्हें गरीब ग्राहकों के लिए अनुसंधान मामलों में मदद मिल सके - मुफ्त कानूनी सहायता की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।
- ECourts Phase III: Rs 7,000 करोड़ outlay (2023-2027); LegRAA एक चरण III पहल है; चरण III भी शामिल है AI-powered मामले scheduling, आभासी अदालतों विस्तार, और litigant क्षुधा
- भाषा अवरोध: भारतीय अदालतें अंग्रेजी का उपयोग करती हैं लेकिन अधिकांश litigant क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं; भविष्य में LegRAA संस्करण (BHASHINI का उपयोग करके) न्यायाधीशों को हिंदी, तमिल, तेलुगू आदि में क्वेरी करने में सक्षम होगा - बहुभाषी न्यायिक एआई
- गोपनीयता: LegRAA केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और अधिनियमों पर काम करता है - कोई गोपनीय मामला विवरण संसाधित नहीं किया जाता है; गोपनीयता चिंताओं को इस डिजाइन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है
- वैश्विक तुलना: संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्टला और LexisNexis वाणिज्यिक एआई कानूनी अनुसंधान उपकरण हैं; भारत का LegRAA सरकारी रूप से बनाया गया है, अदालतों से मुक्त है, और विशेष रूप से भारतीय कानूनी प्रणाली पर प्रशिक्षित - भारतीय न्यायिक उद्देश्यों के लिए बेहतर

DAANVEER — DIGITAL INFRASTRUCTURE INITIATIVE FOR INDIA'S GRAM PANCHAYATS

मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें (GP) हैं - ग्रामीण स्वशासन की सबसे बुनियादी इकाई, जिसमें 6 लाख गांव और 80+ करोड़ ग्रामीण नागरिक शामिल हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन (1992) ने पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की और उन्हें स्वयं सरकार के संस्थानों के रूप में कार्य करने का आदेश दिया। लेकिन अभ्यास में, अधिकांश जीपी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में गंभीर रूप से आउटसोर्स रहते हैं: अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, कोई समर्पित सर्वर या क्लाउड एक्सेस, न्यूनतम कंप्यूटिंग डिवाइस और सीमित डिजिटल साक्षरता वाले कर्मचारी। इसका मतलब यह है कि जीपी प्रभावी रूप से उनके लिए उपलब्ध डिजिटल उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते हैं - ई-ग्रैमस्वराज, SVAMITVA मैप्स, SAMARTH पोर्टल और विभिन्न डीबीटी सिस्टम जिनके माध्यम से केंद्रीय सरकारी धन प्रवाह होता है। डैनवीर - डिजिटल एक्सेस और नए आयु गांव सगाई और पुनरुत्थान के लिए सहायता - इस सप्ताह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इस डिजिटल बुनियादी ढांचे के अंतर को बंद करने के लिए एक अभियान मोड पहल है। यह एक अद्वितीय नागरिक समाज + कॉर्पोरेट सीएसआर मॉडल के माध्यम से काम करता है: कंपनियां और व्यक्ति डिजिटल अवसंरचना (लैपटॉप्स, कनेक्टिविटी डिवाइस, सोलर पावर्ड यूपीएस यूनिट्स, टैबलेट) को सीधे DAANVEER पोर्टल के माध्यम से जीपी को दान कर सकते हैं, मंत्रालय के साथ खरीद और तैनाती। नाम को जानबूझकर चुना जाता है - 'डानवीर' (जो लोग उदार रूप से देते हैं) - भारतीय धर्मार्थ देने की परंपरा (दाना) पर ड्राइंग और इसे राष्ट्रीय शासन अवसंरचना की ओर निर्देशित करते हैं।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
डैनवीर (DAANVEER)	न्यू-एज गांव सगाई और पुनरुत्थान के लिए डिजिटल एक्सेस और सहायता; मोपीआर पहल; सीएसआर + व्यक्तिगत दान पोर्टल डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए ग्राम पंचायतों के लिए
73वां संविधान संशोधन (1992) (73rd Constitutional Amendment (1992))	पंचायती राज संस्थानों के लिए Gave संवैधानिक स्थिति; सम्मिलित भाग IX (Articles 243-243O) और 11 वीं अनुसूची (29 विषय); जनादेशित राज्य वित्त आयोग
ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj)	जीपी प्लानिंग, बजट और फंड मैनेजमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म; 2.5 लाख जीपी ऑनलाइन हैं; जीपी व्यय, योजनाओं और परिसंपत्तियों को ट्रैक करता है; डैनवीर इस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हार्डवेयर प्रदान करता है
अपना स्रोत राजस्व (OSR) (Own Source Revenue (OSR))	अपने स्वयं के स्रोतों से जीपी द्वारा एकत्रित राजस्व - संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, शुल्क; भारत के जीपी केवल 15,000-20,000 करोड़ रुपये एकत्र करते हैं OSR/year बनाम 3 लाख करोड़ रुपये सेंटर से प्राप्त होते हैं।
संविधान की 11 वीं अनुसूची (11th Schedule of Constitution)	उन 29 कार्यों की सूची जिन्हें पंचायतों में स्थानांतरित किया जा सकता है; इसमें कृषि, भूमि सुधार, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, सड़कों, पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य — वास्तविक स्थानांतरण राज्य द्वारा भिन्न होता है।
डीबीटी (Direct Benefit Transfer) (DBT (Direct Benefit Transfer))	केंद्रीय सरकार के हस्तांतरण योजना लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों के लिए; जीपी को लाभार्थियों को सत्यापित करने और गांव के स्तर पर डीबीटी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) (CSR (Corporate Social Responsibility))	टर्नओवर वाली कंपनियां > 1,000 करोड़ रुपये या शुद्ध लाभ > 5 करोड़ रुपये को सीएसआर (धारा 135, कंपनियों अधिनियम 2013) पर औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना चाहिए; डैनवीर जीपी डिजिटल बुनियादी ढांचे की ओर सीएसआर चैनल

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- जीपी स्तर पर डिजिटल विभाजन: ग्रामीण भारत के भीतर, ब्लॉक मुख्यालय (इंटरनेट, कंप्यूटरों के साथ) और गांव स्तर के जीपी के बीच एक और अंतर मौजूद है (अक्सर एक सरकारी कंप्यूटर के साथ, अविश्वसनीय शक्ति, कोई ब्रॉडबैंड नहीं); डैनवीर इस अंतिम मील का अंतर को लक्षित करता है।
- SAMARTH पोर्टल: एक ही सप्ताह को डैनवीर के रूप में लॉन्च किया गया; GPs को डिजिटल रूप से अपने स्रोत राजस्व (संपत्ति कर, जल प्रभार) एकत्र करने में सक्षम बनाता है; मॉडल OSR नियमों को जारी किया गया; बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे (DAANVEER से) के साथ जीपी SAMARTH का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।
- वित्त आयोग अनुदान: 15 वें वित्त आयोग ने पीआरआई (2021-26) को 4.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया; जीपी के लिए 2.36 लाख करोड़ रुपये; लेकिन absorptive क्षमता कम है क्योंकि जीपी में बुनियादी ढांचे की कमी है; डैनवीर इस absorptive क्षमता अंतर को संबोधित करता है

- सौर यूपीएस आयाम: कई जीपी में बिजली कनेक्शन होते हैं लेकिन अक्सर बिजली कटौती होती है; डैनवीर में सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस इकाइयां शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल उपकरण आउटेज के दौरान भी काम कर रहे हैं।
- PESA Act 1996: अनुसूचित क्षेत्रों में, जीपी की अतिरिक्त शक्तियां होती हैं; आदिवासी जीपी (DAANVEER के माध्यम से) में डिजिटल अवसंरचना बेहतर PESA कार्यान्वयन - वन अधिकार, MGNREGA परिसंपत्तियों और आदिवासी कल्याण योजनाओं को ट्रैक करने में सक्षम होगी।
- सामुदायिक मॉडल: पिछली सरकार आईटी योजनाओं के विपरीत (जहां उपकरण केंद्रीय रूप से और वितरित किए गए थे), डैनवीर जीपी को यह निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है कि उन्हें क्या चाहिए और लक्षित दान प्राप्त करना है - मांग संचालित दृष्टिकोण

SAF + CORSIA — INDIA'S AVIATION DECARBONISATION STRATEGY

मंत्रालय: नागर विमानन मंत्रालय / डीजीसीए

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

एविएशन सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है जो डिकार्बोनाइज़ करने के लिए है। आप आज की बैटरी प्रौद्योगिकी (बैटरी बहुत भारी हैं) के साथ एक लंबे समय तक विमान को विद्युतीकृत नहीं कर सकते हैं, और हाइड्रोजन विमान वाणिज्यिक तैनाती से दशकों दूर हैं। विमानन उद्योग के निकट अवधि के decarbonization का जवाब दो गुना है: सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) और CORSIA। सतत विमानन ईंधन गैर जीवाश्म स्रोतों से बना जेट ईंधन है - कृषि अवशेष (गेहूं स्ट्रॉ, गन्ना bagasse), नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, शैवाल, या यहां तक कि वायुमंडलीय CO2। एसएएफ एक 'ड्रॉप-इन' ईंधन है - यह संशोधन के बिना मौजूदा जेट इंजन में काम करता है और इसे 50% तक के अनुपात में पारंपरिक जेट ईंधन के साथ मिश्रित किया जा सकता है। जब उपयोग किया जाता है, तो SAF पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 50-80% तक जीवन चक्र कार्बन उत्सर्जन को कम करता है क्योंकि दहन के दौरान जारी CO2 हाल ही में वायुमंडल से अवशोषित हो गया था, बल्कि लाखों वर्षों तक कार्बन संग्रहीत भूमिगत होने के बजाय (जैसा कि जीवाश्म ईंधन में)। CORSIA (कार्बन ऑफ़सेटिंग और इंटरनेशनल एविएशन के लिए कमी योजना) आईसीएओ की वैश्विक कार्बन तंत्र है: एयरलाइन्स उड़ान अंतरराष्ट्रीय मार्गों को ऑफसेट परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट खरीदकर 2019 बेसलाइन स्तर से अधिक CO2 उत्सर्जन में किसी भी वृद्धि को ऑफसेट करना चाहिए। इस सप्ताह भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने SAF अपनाने और CORSIA अनुपालन दोनों के लिए भारत की तैयारी की समीक्षा की - जो 2027 से सभी आईसीएओ सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य हो जाता है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
सतत विमानन ईंधन (Sustainable Aviation Fuel—SAF)	गैर जीवाश्म स्रोतों से जेट ईंधन (कृषि अपशिष्ट, MSW, शैवाल, ई-ईंधन); 50-80% तक जीवन चक्र CO2 को कम करता है; ड्रॉप-इन ईंधन (संशोधन के बिना मौजूदा विमानों में काम करता है)
अंतरराष्ट्रीय विमानन हेतु कार्बन ऑफसेटिंग एवं न्यूनीकरण योजना (CORSIA)	अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और कमी योजना; आईसीएओ तंत्र; एयरलाइनों को कार्बन क्रेडिट खरीदकर 2019 बेसलाइन से ऊपर उत्सर्जन वृद्धि को ऑफसेट करना चाहिए; 2027 से अनिवार्य

आईसीएओ (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) (ICAO (International Civil Aviation Organisation))	नागरिक विमानन के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी; मॉन्ट्रियल; हवाई नेविगेशन, सुरक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण के लिए वैश्विक मानकों को निर्धारित करता है; भारत एक संस्थापक सदस्य है; CORSIA ICAO की प्राथमिक जलवायु तंत्र है।
ड्रॉप-इन ईंधन (Drop-in fuel)	ईंधन जो संशोधन के बिना मौजूदा विमान इंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है; SAF पारंपरिक जेट ईंधन के साथ 50% तक मिश्रित होने पर एक ड्रॉप-इन ईंधन है; आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है
जीवन चक्र उत्सर्जन (Life-cycle emissions)	कुल CO2 एक ईंधन के उत्पादन, परिवहन और दहन से उत्सर्जित होता है; SAF का जीवन चक्र उत्सर्जन पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 50-80% कम होता है, भले ही दहन समान CO2 जारी करता है।
कार्बन क्रेडिट (Carbon credit)	1 टन CO2 का प्रतिनिधित्व करने योग्य प्रमाण पत्र कम या अनुक्रमित; एयरलाइन्स CORSIA के तहत अपने अतिरिक्त उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए क्रेडिट खरीदते हैं; भारत वन संरक्षण से क्रेडिट बेचने की क्षमता रखता है
EU SAF जनादेश (EU SAF mandate)	RefuelEU विमानन विनियमन अनिवार्य एसएएफ सम्मिश्रण: 2025 से 2%, 2030 से 6%, 2035 से 20%, 2050 से 70%; यूरोपीय संघ के हवाई अड्डों से / तक सभी उड़ानों को एसएएफ का उपयोग करना चाहिए; यूरोप में उड़ान भरने वाले भारतीय वाहकों का पालन करना चाहिए।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का विमानन संदर्भ: भारत का घरेलू विमानन बाजार (एशिया में दूसरा सबसे बड़ा, 15% / वर्ष का बढ़ रहा है) वर्तमान में सालाना 8-9 मिलियन टन जेट ईंधन का उपयोग करता है; अंतरराष्ट्रीय मार्गों में से सभी को 2025-2050 से अधिक SAF में संक्रमण होना चाहिए।
- CORSIA 2027 से अनिवार्य: CORSIA-participating राज्यों से एयरलाइनों को अपने अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन की गणना करनी चाहिए, 2019 बेसलाइन से तुलना करना चाहिए, और किसी भी अतिरिक्त के लिए क्रेडिट खरीदना; भारत की एयरलाइन्स (एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट अंतर्राष्ट्रीय मार्ग) को अनुपालन करना होगा।
- भारत में SAF का उत्पादन: भारत में भारी बायोमास क्षमता है - गन्ना bagasse (350 मिलियन टन / वर्ष), चावल के पुआल (100 मिलियन टन / वर्ष), नगरपालिका ठोस अपशिष्ट; MNRE और MoCA संयुक्त रूप से एक SAF उत्पादन समर्थन योजना विकसित करना
- कॉस्ट प्रीमियम: एसएएफ वर्तमान में पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में 3-5x अधिक लागत रखता है; सरकारी समर्थन (उत्पादन प्रोत्साहन, सम्मिश्रण जनादेश) को लागत अंतर को पुल करने की आवश्यकता होती है; उत्पादन पैमाने के रूप में, लागत प्रीमियम 2035 तक 1.5-2x तक गिरने की उम्मीद है।
- भारत का ऑफसेट क्रेडिट अवसर: CORSIA के तहत, एयरलाइन विकासशील देशों में परियोजनाओं से ऑफसेट खरीदते हैं; भारत का बड़ा वन क्षेत्र, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और cookstove परियोजनाओं CORSIA-eligible क्रेडिट उत्पन्न करता है - भारत एक नेट विक्रेता हो सकता है।

- UDAN + SAF: छोटे टर्बोप्रोप विमानों का उपयोग करके क्षेत्रीय मार्ग (UDAN योजना) SAF अपनाने के लिए सबसे अधिक लाभदायक हैं; हाइड्रोजन संचालित क्षेत्रीय विमान अंततः लघु मार्गों पर टर्बोप्रोप को प्रतिस्थापित करेगा।

ATMANIRBHAR PANCHAYAT PROGRAMME + SAMARTH PORTAL — FISCAL EMPOWERMENT OF PRIs

मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय

PIB तिथि: 27 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतें वार्षिक रूप से 15,000-20,000 करोड़ रुपये की एक संयुक्त स्रोत राजस्व (OSR) एकत्र करती हैं - वे जो खर्च करते हैं उसका एक छोटा अंश (Rs 3+ लाख करोड़) वित्त आयोग अनुदान + राज्य विकास + केंद्रीय योजनाओं से GPs को बहती है)। इसका मतलब यह है कि जीपी लगभग पूरी तरह से पैसे के लिए ऊपरी सरकारों पर निर्भर हैं, जिसका मतलब है कि वे अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए ऊपरी सरकारों पर भी निर्भर हैं। यह भारत की विकेन्द्रीकरण वास्तुकला में मूलभूत कमजोरी है: संवैधानिक विकेंद्रीकरण (73वां संशोधन, 11 वीं अनुसूची) को वित्तीय विकेंद्रीकरण से मिलान नहीं किया गया है। इस सप्ताह मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा शुरू किया गया अटमानिरभार पंचायत कार्यक्रम, प्रोत्साहन संरचना में परिवर्तन करता है: जीपी जो अपने स्वयं के स्रोत राजस्व को बढ़ाने वाले केंद्र से उनके OSR सुधार के अनुपात में अतिरिक्त विवेकात्मक धन प्राप्त करते हैं। SAMARTH पोर्टल के साथ (Mobilising, Assessing और रिपोर्टिंग टैक्स / टैक्स और घरेलू रसीद के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण) जीपी के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करता है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में सभी कर योग्य संपत्तियों की पहचान की जा सके (SVAMITVA ड्रोन डेटा बेस के रूप में उपयोग), अंक मांग डिजिटल रूप से नोटिस करता है, क्यूआर कोड / यूपीएआई के माध्यम से संपत्ति कर एकत्र करता है, और संग्रह दक्षता को ट्रैक करता है। मॉडल OSR नियम भी जारी किए गए थे - ऐसे टेम्पलेट जो राज्य जीपी संपत्ति कराधान, पानी/सैनिटेशन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क और बाज़ार और मेलों से शुल्क संग्रह के लिए कानूनी आधार को मानकीकृत करने के लिए अपना सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व (Own Source Revenue—OSR)	राजस्व जीपी खुद को इकट्ठा करते हैं - संपत्ति कर, जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क, बाजार शुल्क; वर्तमान में केवल 15,000-20,000 करोड़ रुपये / वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर; अटमानिरभर पंचायत लक्ष्य इसे 2030 तक दोगुना कर देते हैं।
SAMARTH पोर्टल (SAMARTH Portal)	मोबिलाइजिंग, आकलन और रिपोर्टिंग टैक्स / टैक्स और घरेलू रसीद के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण; जीपी संपत्ति कर पहचान, मांग, संग्रह और रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल उपकरण
73वां संविधान संशोधन 1992 (73rd Constitutional Amendment 1992)	संवैधानिक पंचायत; सम्मिलित भाग IX; 29 विषयों के साथ 11 वीं अनुसूची बनाई; अधिदेशित राज्य वित्त आयोग; PR में सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया

11 वीं अनुसूची (11th Schedule)	सूची 29 कार्य जिन्हें कृषि, भूमि सुधार, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, सड़कों, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा सहित पंचायतों में स्थानांतरित किया जा सकता है - वास्तविक स्थानांतरण राज्य द्वारा भिन्न होता है
राज्य वित्त आयोग (SFC) (State Finance Commission (SFC))	प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर 5 साल का गठन; सिफारिश करता है कि राज्य और PRI के बीच कर और अनुदान कैसे वितरित किया जाना चाहिए; राज्यों में व्यापक रूप से भिन्न होता है।
जीपी राजस्व के रूप में संपत्ति कर (Property tax as GP revenue)	ग्रामीण क्षेत्रों में इमारतों पर संपत्ति कर GPs का सबसे बड़ा संभावित OSR स्रोत है; अधिकांश GPs ने संपत्ति रजिस्टर किया है; SVAMITVA ड्रोन सर्वेक्षण उचित संपत्ति कर मूल्यांकन के लिए आवश्यक अद्यतन डेटा प्रदान करते हैं।
OSR नियम (Model OSR Rules)	राज्यों के लिए MoPR द्वारा जारी टेम्पलेट कानूनी ढांचे जीपी कराधान शक्तियों को मानकीकृत करने के लिए; संपत्ति कर, पानी शुल्क, ठोस अपशिष्ट उपयोगकर्ता शुल्क, बाजार शुल्क को शामिल करता है - राज्यों को अनुकूलित और अपनाने कर सकते हैं

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- राजकोषीय विकेंद्रीकरण अंतर: 73वां संशोधन ने जीपी संवैधानिक स्थिति और कार्यात्मक जिम्मेदारियों को (11 वीं अनुसूची); लेकिन वास्तविक कर शक्तियां राज्यों के साथ रहती हैं; अधिकांश जीपी केवल संपत्ति कर और शुल्क एकत्र कर सकते हैं - यह मौलिक सीमा है SAMARTH काम करता है।
- SVAMITVA + SAMARTH synergy: SVAMITVA ड्रोन सर्वेक्षणों ने 3.17 लाख गांवों में हर संपत्ति का मानचित्रण किया; SAMARTH संपत्ति कर मांग उत्पन्न करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है; पहले जीपी ने पुरानी, अपूर्ण संपत्ति रजिस्टरों का इस्तेमाल किया - SVAMITVA सटीक आधार डेटा प्रदान करता है SAMARTH की जरूरत है
- आनुपातिक प्रोत्साहन डिजाइन: अटमानिरभर पंचायत कार्यक्रम की प्रोत्साहन संरचना - केंद्र OSR के विकास के अनुपात में अतिरिक्त धन देता है - एक प्रदर्शन आधारित अनुदान मॉडल है; निश्चित अनुदान से बेहतर क्योंकि यह उन GPs को पुरस्कृत करता है जो अपने स्वयं के निवासियों से कर एकत्र करने के लिए राजनीतिक प्रयास करते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलना: इंडोनेशिया का गाँव फंड मॉडल (2015 से): प्रत्येक गाँव को बेस फंड मिलता है लेकिन अगर यह OSR एकत्र करता है तो बोनस फंड मिलता है; इंडोनेशिया ने 10 वर्षों में 300% OSR वृद्धि देखी है; Atmanirbhar पंचायत को इसी तरह के लॉजिक लॉजिक पर मॉडल किया गया है।
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था चुनौती: जीपी अध्यक्ष (सर्पंच) अपने स्वयं के मतदाताओं को कर देने के लिए अनिच्छुक हैं (जो उन्हें 5 साल में वोट देंगे); SAMARTH की डिजिटल मांग प्रणाली कर मांग को स्वचालित करके राजनीतिक संघर्ष को कम कर देती है - प्रणाली मांग भेजती है, सरपंच नहीं है।
- 15th वित्त आयोग: आवंटित रुपये 2.36 लाख करोड़ जीपी (2021-26); शर्तों के साथ - स्वच्छता और पानी की आपूर्ति के लिए अनुबंधित अनुदान; बेहतर OSR प्रदर्शन के साथ जीपी के लिए गैर-सहायता अनुदान; अमानिरभर पंचायत इस वित्त आयोग लॉजिक के साथ गठबंधन करती है

- शहरी तुलना: शहरी स्थानीय निकायों को 45,000-50,000 करोड़ रुपये OSR (property tax, water, पार्किंग); ग्रामीण जीपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र और आबादी के लिए 15,000-20,000 करोड़ रुपये एकत्र करते हैं - ग्रामीण क्षेत्र व्यवस्थित रूप से कम कर रहे हैं; SAMARTH का उद्देश्य इस को सही करना है

SOWA-RIGPA — SIXTH SCHEDULE AREAS, AYUSH, AND TRADITIONAL TIBETAN MEDICINE

मंत्रालय: आयुष मंत्रालय / जनजातीय मामलों मंत्रालय

PIB तिथि: 27 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

हिमालय में उच्च - लद्दाख, स्पीति, लाहुल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्रों में - पारंपरिक चिकित्सा की एक प्रणाली रहती है जो 2,500 से अधिक वर्षों तक आधुनिक फार्मास्यूटिकल्स की भविष्यवाणी करती है। सोवा-रिग्पा (तिब्बती में 'स्वच्छता' का अर्थ) तिब्बती, हिमालयन और मंगोलियाई संस्कृतियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। यह हर्बल दवाओं के संयोजन का उपयोग करता है (अधिकांश औषधीय पौधों से सोर्स किया जाता है जिसमें कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं), खनिज तैयारी, आहार चिकित्सा, व्यवहारिक संशोधन और बीमारी के इलाज के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं शामिल हैं। सोवा-रिग्पा आयुर्वेद से अलग है (हालांकि वे प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपराओं में कुछ जड़ें साझा करते हैं), टीसीएम (पारंपरिक चीनी चिकित्सा) से, और यूनानी से - यह आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा के साथ पांचवां मान्यता प्राप्त भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा (NISR) ने लेह, लद्दाख में भारत के समर्पित सोवा-रिग्पा अनुसंधान और शिक्षा संस्थान - इस सप्ताह मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग (MDNIY) के सहयोग से एक योग कल्याण प्रशिक्षक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया। यह संयोजन महत्त्वपूर्ण है: सोवा-रिग्पा मुख्य रूप से छठे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों (जहां स्वायत्त परिषद आदिवासी समुदायों को नियंत्रित करते हैं) और हिमालय के अनुसूचित जनजाति समुदायों में अभ्यास किया जाता है; इसे योग के साथ एकीकृत करने से उच्च ऊंचाई वाले समुदायों के लिए एक व्यापक पारंपरिक कल्याण की पेशकश होती है, जिन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा तक सीमित पहुंच हासिल की है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
सोवा-रिग्पा (Sowa-Rigpa)	तिब्बती, हिमालयी और मंगोलियाई संस्कृतियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली; आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध के साथ 5 वें भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त; हर्बल, खनिज, आहार और आध्यात्मिक चिकित्सा का उपयोग करता है।
राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा संस्थान (NISR)	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा-रिग्पा, लेह, लद्दाख; सोवा-रिग्पा अनुसंधान, शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के लिए शीर्ष संस्थान; AYUSH मंत्रालय के तहत स्थापित
मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (MDNIY)	मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली; योग पदोन्नति के लिए नोडल संस्थान; योग कल्याण प्रशिक्षक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एनआईएसआर के साथ सहयोग किया

छठी अनुसूची (Sixth Schedule)	असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के लिए संवैधानिक प्रावधान (आर्किल 244); विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषद बनाता है; अधिकांश सोवा-रिग्पा चिकित्सक आदिवासी हिमालयी क्षेत्रों में हैं।
उच्च ऊंचाई वाले औषधीय पौधे (High-altitude medicinal plants)	सोवा-रिग्पा पौधों का उपयोग 3,000 मीटर से ऊपर पाया जाता है - रोडियोला, हिप्पोफा (सिया बकथर्न), एकोनिटम, स्वार्टिया, जेनटिया; कई दुर्लभ / खतरे में हैं; जलवायु परिवर्तन उनकी उपलब्धता की धमकी देता है
AYUSH मान्यता (AYUSH recognition)	AYUSH = आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी; सोवा-रिग्पा को औपचारिक रूप से 2020 (Sowa-Rigpa Act 2020) में AYUSH फ्रेमवर्क में जोड़ा गया था; 5th पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली
सोवा-रिग्पा अधिनियम, 2020 (Sowa-Rigpa Act 2020)	विधान जो औपचारिक रूप से सोवा-रिग्पा चिकित्सकों को मान्यता देता है और उनकी शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करता है; राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सोवा-रिग्पा परिषद स्थापित किया गया; इसे भारत के औपचारिक स्वास्थ्य ढांचे के भीतर लाया गया।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- सोवा-रिग्पा अधिनियम 2020: भारत ने औपचारिक रूप से कानून के माध्यम से सोवा-रिग्पा को मान्यता दी; स्थापित सोवा-रिग्पा सेंट्रल काउंसिल; डिप्लोमा (D.Sow.R) और डिग्री स्तर की शिक्षा मानकीकृत; चिकित्सक अब औपचारिक पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं - उनके संबंधित अधिनियमों के तहत आयुष चिकित्सकों के समान
- छठे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र: अधिकांश सोवा-रिग्पा चिकित्सक लद्दाख (Union Territory, छठे अनुसूची नहीं बल्कि 73 वें संशोधन के तहत स्वायत्त जिला परिषदों के साथ), सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों - मुख्य रूप से आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्र जहां एलोपैथिक हेल्थकेयर सीमित है।
- औषधीय पौधे संरक्षण: सोवा-रिग्पा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से 300+ पौधों की प्रजातियों का उपयोग करता है; जलवायु परिवर्तन इन पौधों के वितरण को बदल रहा है (आमतौर पर तापमान बढ़ने के रूप में उच्च गति); एनआईएसआर के शोध में निवास स्थान मानचित्रण और खतरनाक औषधीय प्रजातियों के पूर्व-आध्यात्मिक संरक्षण शामिल है।
- ब्रिक्स टीसीआईएम कनेक्शन: ब्रिक्स 16 वें स्वास्थ्य मंत्रियों (Week 8) को विशेष रूप से पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के मानकीकरण के लिए बुलाया जाता है; सोवा-रिग्पा का एकीकरण AYUSH फ्रेमवर्क में और इस सप्ताह के योग-सोवा-रिग्पा कोर्स की स्थिति भारत हिमालयन पारंपरिक चिकित्सा के लिए टीसीआईएम मानकों का नेतृत्व करने के लिए है।
- सागर बकथॉर्न (हिप्पोफा rhamnoides): कुंजी सोवा-रिग्पा संयंत्र; लद्दाख में प्रचुर मात्रा में बढ़ता है; जामुन में नारंगी से 15x अधिक विटामिन सी होता है; विरोधी भड़काऊ गुण; सीएसआईआर और डीआरडीओ ने सोवा-रिग्पा के समुद्री बकथॉर्न ज्ञान को न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए व्याप्त किया है - वाणिज्यिक पाइपलाइन के लिए एक प्रत्यक्ष पारंपरिक ज्ञान
- सीमा क्षेत्र स्वास्थ्य: सोवा-रिग्पा चिकित्सक भारत के उच्चतम सैन्य पदों की सेवा करते हैं - आईटीबीपी और सोवा-रिग्पा क्लीनिक से सियाचिन, करगिल और पूर्वी लद्दाख लाभ में सेना के कार्मिक; सोवा-रिग्पा के साथ योग को एकीकृत करना अत्यधिक परिस्थितियों में सैनिकों के लिए व्यापक कल्याण पैदा करता है।
- टीकेडीएल कनेक्शन: सोवा-रिग्पा फॉर्मूलेशन्स सीएसआईआर-टीकेडीएल (Week 7) का हिस्सा हैं; पारंपरिक ज्ञान ने जैव-प्रशांति को रोकने के लिए दस्तावेज किया - चीन के टीसीएम प्रैक्टिशनर्स ने ऐतिहासिक रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तिब्बती/हिमालयन फॉर्मूलेशन पेटेंट करने की कोशिश की है; भारत का सोवा-रिग्पा मान्यता + टीकेडीएल दस्तावेज़ीकरण इससे रोकता है।

BHARAT MARITIME INSURANCE POOL (BMIP) — P&I INSURANCE PRODUCT LAUNCHED

मंत्रालय: वित्त मंत्रालय / आईआरडीएआई / शिपिंग मंत्रालय

PIB तिथि: 30 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

जब एक जहाज एक तेल फैल का कारण बनता है, तो एक चालक दल के सदस्य को चोट पहुंचाता है, या किसी अन्य पोत के साथ जुड़ जाता है, जो भुगतान करता है? उत्तर सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (P&I) बीमा है - समुद्री बीमा का एक विशेष रूप जो उनके पोत के कारण होने वाली घटनाओं के लिए तीसरे पक्ष (क्रू सदस्यों, कार्गो मालिकों, बंदरगाह अधिकारियों, तटीय राज्यों) के लिए एक जहाज के मालिक की देयता को कवर करता है। P&I बीमा नियमित कार्गो बीमा की तरह नहीं है - यह दायित्व को कवर करता है, कार्गो या पोत मूल्य का नुकसान नहीं। वैश्विक पी एंड आई बाजार ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में आधारित 13 पारस्परिक बीमा क्लबों द्वारा प्रभुत्व है - पी एंड आई क्लबों का अंतर्राष्ट्रीय समूह, सामूहिक रूप से दुनिया के महासागर जाने वाले टनेज के 90% को कवर करता है। भारतीय जहाजों को ऐतिहासिक रूप से इन विदेशी क्लबों से पी एंड आई बीमा खरीदना पड़ा है, जो भारत से बाहर निकलने वाले प्रीमियम का भुगतान करता है। जब भू-राजनीतिक तनाव उत्पन्न होता है (रूस स्वीकृतियां 2022, रेड सी संघर्ष 2024), विदेशी पी एंड आई क्लब कभी कभी कुछ मार्गों या झंडा राज्यों को कवर करने से इनकार करते हैं - भारतीय जहाजों को फंसने से रोकते हैं। इस सप्ताह वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने भारत के प्रथम घरेलू संरक्षण और क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद को भारत समुद्री बीमा पूल (BMIP) के तहत लॉन्च किया। BMIP को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं (न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस) और निजी बीमाकर्ताओं को एक पूलिंग व्यवस्था में एक साथ लाने के द्वारा बनाया गया था - प्रत्येक बीमाकर्ता जोखिम का हिस्सा लेता है, और साथ में उनके पास बड़े समुद्री देयता दावों को रेखांकित करने के लिए पूंजी आधार होता है। उत्पाद शुरू में भारतीय-चमकदार जहाजों को कवर करता है और भारतीय बंदरगाहों पर कॉल करने वाले विदेशी जहाजों को बढ़ाया जा सकता है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
भारत समुद्री बीमा पूल (Bharat Maritime Insurance Pool—BMIP)	भारत समुद्री बीमा पूल; भारतीय बीमा कंपनियों की पूल व्यवस्था; शुरू किया पी एंड आई बीमा उत्पाद जुलाई 30; तीसरे पक्ष के लिए जहाज के मालिक दायित्व को शामिल किया गया - चालक दल, कार्गो, प्रदूषण, टकराव
पी एंड आई बीमा (P&I Insurance)	संरक्षण और क्षतिपूर्ति बीमा; तीसरे पक्ष के लिए जहाज़ के मालिकों की देयता को कवर करता है; पतवार बीमा (शिप क्षति को कवर करता है) और कार्गो बीमा (कार्गो हानि को कवर करता है); अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए आवश्यक
इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पी एंड आई क्लब (International Group of P&I Clubs)	13 पारस्परिक बीमा क्लब (यूके, नॉर्वे, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) वैश्विक महासागर के टनेज के 90% को कवर करते हैं; 150+ वर्षों के लिए डोमिनिकन पी एंड आई बाजार; BMIP भारत का पहला घरेलू विकल्प है।

म्यूचुअल इंश्योरेंस क्लब (Mutual Insurance Club)	बीमा व्यवस्था जहां जहाज़ के मालिक अपने जोखिमों को पूल करते हैं; प्रत्येक सदस्य एक आम निधि में योगदान देता है; इस निधि से भुगतान किए गए बड़े दावे; लाभ (यदि कोई हो) सदस्यों को लौटा; ऐतिहासिक रूप से UK-domiciled
भू-राजनीतिक बीमा जोखिम (Geopolitical insurance risk)	रूस की मंजूरी 2022: पश्चिमी पी एंड आई क्लब ने रूसी तेल टैंकरों को कवर करने से इनकार कर दिया; लाल सागर संघर्ष 2024: क्लबों ने युद्ध जोखिम अधिभार को जोड़ा; भारत का BMIP बीमा प्रदान करता है जो पश्चिमी भू राजनीतिक दबावों के अधीन नहीं है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)	भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण; BMIP सहित सभी बीमा उत्पादों को नियंत्रित करता है; वित्त मंत्रालय के तहत पी एंड आई उत्पाद संरचना और मूल्य निर्धारण को मंजूरी दी; वित्त मंत्रालय के तहत
पूलिंग व्यवस्था (Pooling arrangement)	एकाधिक बीमाकर्ता समान रूप से जोखिम साझा करते हैं; प्रत्येक प्रीमियम और जोखिम का प्रतिशत लेता है; बहुत बड़े दावों (तेल की स्पिल देयता अरब डॉलर हो सकती है) की कवरेज को सक्षम बनाता है कि कोई भी भारतीय बीमाकर्ता अकेले अकेले ही संभाल सकता है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का शिपिंग संदर्भ: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीफ़र आपूर्तिकर्ता है (Week 8 संक्षिप्त); इसमें महत्त्वपूर्ण व्यापारी बेड़े (1,400+ जहाजों) हैं; लेकिन पीएंडआई बीमा का 95%+ विदेशी क्लबों से खरीदा गया था; BMIP घरेलू विकल्प शुरू करता है
- रूस स्वीकृति सबक: जब यूएसए / ईयू ने 2022 में रूस को मंजूरी दी, तो पश्चिमी पी एंड आई क्लबों ने रूसी तेल टैंकरों को कवर करना बंद कर दिया; रूस ने वैकल्पिक (अधिकतर रूसी और भारतीय बीमाकर्ताओं) की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष किया; भारत ने पहला हाथ देखा कि पश्चिमी बीमा पर निर्भरता भू राजनीतिक भेद्यता पैदा करती है।
- लाल सागर संघर्ष प्रभाव: लाल सागर (2024-2026) में हौथी हमलों ने पीएंडआई क्लबों को प्रति व्यंग्य के 0.2-0.5% जहाज मूल्य के 'गर्म जोखिम' अधिभार को जोड़ने के लिए मजबूर किया; 50 मिलियन डॉलर के जहाज के लिए, यह प्रति पारगमन $100,000-250,000 अतिरिक्त है; भारतीय शिपिंग कंपनियों ने इस लागत को बोर किया - BMIP प्रतिस्पर्धी विकल्प प्रदान कर सकता है।
- सागरमाला + BMIP: भारत के 6 लाख करोड़ रुपये बंदरगाह के नेतृत्व में विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम (समय पर सप्ताह 8 संक्षिप्त) को एक पूर्ण समुद्री वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है - जहाज निर्माण वित्त, बंदरगाह वित्त, और अब समुद्री बीमा; BMIP इस पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा करता है
- पुनर्जागरण चुनौती: पी एंड आई का दावा बहुत बड़ा हो सकता है (प्रेजिएग ऑयल स्पिल 2002: $1.6 बिलियन; एरिका 1999: $600 मिलियन); BMIP को अंतरराष्ट्रीय पुनर्जागरण की आवश्यकता होती है जो catastrophic दावों को कवर करने के लिए समर्थन करता है; शुरुआती व्यवस्था की संभावना Munich Re, स्विस Re, या Lloyd के लंदन के साथ
- क्रू लायबिलिटी: पी एंड आई बीमा में क्रू चोट, मृत्यु और प्रत्यावर्तन शामिल है; वर्तमान में विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारत के 2.4 लाख नाविकों के पास उनके नियोक्ताओं (विदेशी) पी एंड आई क्लबों के माध्यम से पी एंड आई कवरेज है; BMIP अंततः विदेशी जहाजों पर भारतीय समुद्री यात्रियों को कवर कर सकता है - एक प्रत्यक्ष कल्याण लाभ

- आईएफएससी जीआईएफटी सिटी: भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जीआईएफटी सिटी में, गुजरात एक समुद्री वित्त केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है; BMIP का पी एंड आई उत्पाद अंततः जीआईएफटी सिटी से पेश किया जा सकता है, जिससे ब्रिटेन या नॉर्वे के बजाय भारत को बीमा प्रीमियम आय मिलती है।

NBA ACCESS AND BENEFIT SHARING — Rs 24 LAKH TO COTTON FARMERS AND BIODIVERSITY BOARDS

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

हमने इस श्रृंखला के सप्ताह 4, 6 और 7 में एबीएस (एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग) को कवर किया है। यह सप्ताह एक विशिष्ट, ठोस कार्यान्वयन को लाता है जो अमूर्त अवधारणा को वास्तविक भुगतान में क्रिस्टलीकृत करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने किसानों, अनुसंधान संस्थानों और 11 कपास-बढ़ते राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्डों को लाभ साझा करने के रूप में 24 लाख रुपये जारी किए। यहाँ इस भुगतान के पीछे की कहानी है: कपास भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण गैर-खाद्य फसल है - भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और निर्यातक है। खेती कपास के जंगली रिश्तेदारों (जैसे गोसिपियम अर्बोरियम और जी. जड़ी बूटी - दोनों भारत के लिए स्वदेशी) आनुवंशिक लक्षण है कि वाणिज्यिक कपास चयनात्मक प्रजनन के शताब्दियों से अधिक खो गया है: विशिष्ट कीटों के लिए प्रतिरोध, सूखे के लिए सहिष्णुता, नमकीन मिट्टी में बढ़ने की क्षमता। जब जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों या बीज कंपनियों को इन आनुवंशिक लक्षणों का उपयोग करना चाहते हैं - व्यावसायिक किस्मों के साथ जंगली कपास किस्मों को पार करने के लिए नए कीट-प्रतिरोधी या सूखे-सहिष्णु कपास संकर विकसित करना - उन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 और नागोया प्रोटोकॉल के तहत, एनबीए से अनुमति लेनी चाहिए और उन लोगों के साथ व्यावसायिक लाभों का एक हिस्सा साझा करना चाहिए जो इन आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित और साझा करते हैं: जिनके क्षेत्रों में जंगली कपास की किस्में बढ़ती हैं, समुदाय जो पारंपरिक कपास किस्मों को बनाए रखते हैं, और राज्य जैव विविधता बोर्डों ने उन्हें दस्तावेज दिया। इस सप्ताह का 24 लाख रुपये भुगतान एनबीए का तिमाही एबीएस वितरण है - भारत के आनुवंशिक विरासत के संरक्षकों को भारत के जैव विविधता कानून से बहने वाला प्रत्यक्ष नकदी लाभ।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (National Biodiversity Authority—NBA)	जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत सांविधिक निकाय; चेन्नई; भारत के जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करता है; एबीएस समझौतों को मंजूरी देता है; लाभ बांटने भुगतान वितरित करता है
पहुँच एवं लाभ-साझाकरण (Access and Benefit Sharing—ABS)	नागोया प्रोटोकॉल (CBD) के तहत तंत्र: जो लोग व्यावसायिक उपयोग के लिए आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उन समुदायों के साथ लाभ साझा करना चाहिए जो उन संसाधनों को संरक्षित करते हैं; नकद भुगतान + प्रौद्योगिकी साझा + अनुसंधान सहयोग

नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)	जैविक विविधता (सीबीडी) पर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने 2010 को नागोया, जापान में अपनाया; एबीएस का संचालन; भारत ने 2012 को संशोधित किया; एनबीए ने नागोया प्रोटोकॉल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया।
गॉसिपियम आर्बोरियम/हर्बेसियम (Gossypium arboreum/herbaceum)	भारत के लिए स्वदेशी जंगली कपास प्रजातियों; सभी खेती कपास के पूर्वजों; व्यावसायिक किस्मों में 'खोज' होने वाले लक्षण (कीट प्रतिरोध, सूखे सहिष्णुता, फाइबर की गुणवत्ता) ले जाते हैं; आनुवंशिक सामग्री बीज कंपनियों द्वारा मांगी गई है।
राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) (State Biodiversity Boards (SBBs))	एनबीए के तहत राज्य स्तरीय निकायों; स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को बनाए रखने; पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) को बनाए रखने; एबीएस भुगतान का हिस्सा प्राप्त करें
जन जैव विविधता रजिस्टर (People's Biodiversity Register—PBR)	स्थानीय जैव विविधता - पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीवों का व्यापक दस्तावेज - प्रत्येक गांव में; बीएमसी द्वारा बनाए रखा; स्थानीय समुदायों द्वारा एबीएस दावों के लिए कानूनी आधार बनाता है
जैविक विविधता अधिनियम 2002 (Biological Diversity Act 2002)	भारत की कानून कार्यान्वयन सीबीडी; जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए एनबीए को पूर्व सूचना की आवश्यकता है; व्यावसायिक उपयोग या अनुसंधान के लिए पूर्व अनुमोदन; विदेशी संस्थाओं या भारतीय कंपनियों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए एबीएस समझौते अनिवार्य

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- संदर्भ में 24 लाख रुपये: अब छोटी राशि लेकिन बढ़ रही है; एनबीए ने सभी क्षेत्रों में 10+ करोड़ रुपये के एबीएस समझौतों को संसाधित किया है; नीम और हल्दी से संबंधित एबीएस के बाद कपास तीसरा क्षेत्र है; क्योंकि अधिक बीज कंपनियां भारतीय आनुवंशिक सामग्री तक पहुंचती हैं, एबीएस भुगतान काफी बढ़ेगा।
- 11 कपास राज्यों: महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, तमिलनाडु - सभी प्रमुख सूती उत्पादक; किसानों और बीएमसी इन राज्यों में 24 लाख रुपये लाभ शेयर प्राप्त
- कपास आनुवंशिक संसाधन महत्व: बीटी कपास (आमतौर पर बेसिलस थ्योरिनेसिस जीन के साथ संशोधित) अब भारत के कपास क्षेत्र के 95% को कवर करता है; लेकिन नए कीटों (गुलाबी बोलव) बीटी का विरोध कर रहे हैं; बीज कंपनियों को तत्काल जंगली कपास की प्राकृतिक कीट प्रतिरोध जीन की आवश्यकता होती है - इस शोध पहुंच से एबीएस भुगतान प्रवाह
- नागोया प्रोटोकॉल IRCC: भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत स्थापित ABS क्लीयरिंग-हाउस (ABSCH) प्रणाली का उपयोग करता है; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र (IRCC) प्रत्येक ABS समझौते के लिए जारी किया गया है - भारतीय संस्थानों को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि वैश्विक शोधकर्ताओं ने भारतीय कानून के अनुपालन में मदद की है।
- TKDL समांतर: TKDL अमान्य पेटेंट को रोकता है; NBA/ABS यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय आनुवंशिक संसाधनों का भी वैध उपयोग में लाभ साझा करना शामिल है; साथ में वे दोनों शोषण (TKDL) और uncompensated उपयोग (ABS) - पूरक सुरक्षा से भारत की जैविक विरासत की रक्षा करते हैं।

- BMC-PBR प्रणाली: 2.5 लाख+ BMC स्थापित; 3 लाख+ पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर पूरा हो गया; यह सामुदायिक स्तर का प्रलेखन ABS दावों के लिए कानूनी आधार बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ साझा करने से जैव विविधता के वास्तविक संरक्षक तक पहुंच जाता है - किसान और जनजातीय समुदाय
- वैश्विक तुलना: ब्राजील के एबीएस सिस्टम (विश्व में सबसे मजबूत) ने 2015 से 60+ मिलियन डॉलर का भुगतान किया; भारत का 10 करोड़ रुपये संचयी मामूली है - एनबीए के एबीएस प्रवर्तन को स्केल करना और भारत की पूर्ण एबीएस संभावित क्षमता को महसूस करने के लिए समझौता करने की क्षमता की आवश्यकता है।

VANDE BHARAT TRANSPORTS DONOR HEART — SURAT TO AHMEDABAD IN 26 MINUTES

मंत्रालय: रेल मंत्रालय / स्वास्थ्य मंत्रालय

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

31 जुलाई को सूरत में एक अस्पताल में एक दाता दिल काटा गया और अहमदाबाद में एक अस्पताल में एक प्रत्यारोपण रोगी तक पहुंचने की जरूरत थी - लगभग 265 किमी की दूरी। एक दाता दिल केवल आदर्श स्थितियों में 4-6 घंटे के लिए शरीर के बाहर जीवित रह सकता है (एक विशेष संरक्षण समाधान में 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थापित); इससे परे, अंग प्रत्यारोपण के लिए व्यवहार्य नहीं है। सड़क परिवहन एक पुलिस अनुरक्षण समाशोधन यातायात के साथ 2.5-3 घंटे का समय लगेगा। हेलीकाप्टर परिवहन पर विचार किया गया था लेकिन मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं थी। वंदे भारत एक्सप्रेस - भारत की हाई स्पीड सेमी-हाई स्पीड ट्रेन सूरत को अहमदाबाद से जोड़ती है - तैनात किया गया था। दिल, एक संरक्षण बॉक्स में, एक समर्पित डिब्बे में एक चिकित्सा टीम के साथ यात्रा की। वंदे भारत ने 26 मिनट में सूरत-अहमदाबाद खिंचाव को कवर किया - 160 किमी/h तक की गति पर। हृदय व्यवहार्य हो गया और प्रत्यारोपण सर्जरी सफलतापूर्वक की गई थी। यह एक नई योजना के बारे में एक नीति कहानी नहीं है - यह मौजूदा अवसंरचना के बारे में एक प्रदर्शन कहानी है जिसका इस्तेमाल नवोन्मेषी रूप से किया जा रहा है। वंदे भारत की गति (160 किमी / एच बनाम सड़क की 80-100 किमी / एच अधिकतम एस्कॉर्ट), विश्वसनीयता (कोई यातायात नहीं, स्पष्ट स्की पर कोई मौसम निर्भरता), और नेटवर्क कवरेज (गुजरात में अधिकांश प्रमुख शहरों को जोड़ता है) इसे संभावित रूप से सबसे विश्वसनीय आपातकालीन अंग परिवहन प्रणाली भारत है। रेलवे मंत्रालय अब वंदे भारत नेटवर्क पर आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन स्लॉट को नामित करने के लिए एक प्रोटोकॉल का अध्ययन कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express)	भारत की सेमी-हाई स्पीड ट्रेन; अधिकतम गति 160 किमी / एच; आईसीएफ चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित; स्व-चालित (कोई अलग लोकोमोटिव नहीं); 52 ट्रेनें 2026 तक भारत भर में परिचालन करती हैं।
अंग की प्रत्यारोपण-योग्य समयावधि (Organ viability window)	हार्ट: 4-6 घंटे; लीवर: 12-24 घंटे; किडनी: 24-36 घंटे; कॉर्निया: 14 दिन; अस्थि मज्जा: 24 घंटे; तंग व्यवहार्यता खिड़कियां परिवहन गति को अंग प्रत्यारोपण सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण बनाती हैं

शीत अरक्तता अवधि (Cold ischemia time)	अंग से प्राप्तकर्ता में रक्त आपूर्ति को हटाने का समय; परिवहन का समय भी शामिल है; कम ठंडी इस्केमिया = बेहतर ऑर्गन फंक्शन पोस्ट-ट्रांसप्लांट; वंदे भारत ने इसे छोटा कर दिया
राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO)	भारत का अपैक्स शरीर अंग दान और प्रत्यारोपण समन्वय के लिए; दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को पंजीकृत करता है; अंतर-अस्पताल अंग साझाकरण का समन्वय करता है; आईटीओ प्रोटोकॉल संभावित रूप से ऑर्गन ट्रांसपोर्ट में वंदे भारत की भूमिका को औपचारिक रूप देगा।
प्रत्यारोपण की दर (Transplant rate)	भारत 20,000+ ऑर्गन प्रत्यारोपण/वर्ष करता है; लेकिन मांग को पूरा करने के लिए 3 लाख प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है; केवल 1% आवश्यक गुर्दे, 2% आवश्यक दिल उपलब्ध हैं; वंदे भारत की गति उपलब्ध अंगों की सफलता दर में सुधार कर सकती है।
अहमदाबाद सूरत मेडिकल कॉरिडोर (Ahmedabad Surat medical corridor)	गुजरात ने एक मजबूत चिकित्सा-औद्योगिक गलियारा विकसित किया है (सूरत के प्रमुख अस्पताल हैं); अहमदाबाद में एम्स, एसएएल और अन्य तृतीयक अस्पताल हैं); वंदे भारत उन्हें 26 मिनट में जोड़ता है - एक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट सुपरहाईवे
प्रोटोकॉल विकास (Protocol development)	रेलवे मंत्रालय ने वंदे भारत पर आपातकालीन स्वास्थ्य परिवहन स्लॉट का अध्ययन किया; आपातकालीन चिकित्सा परिवहन के लिए चुनिंदा ट्रेनों पर एक विशिष्ट कोच नामित किया जाएगा; यूरोप में प्रीसीडेंट (नादरलैंड, जर्मनी में ट्रेन द्वारा ऑर्गन परिवहन)

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- क्यों वंदे भारत अंग परिवहन के लिए हेलीकाप्टर से बेहतर है: हेलीकाप्टर को मौसम से जमीन पर रखा जा सकता है, हवाई क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित; दोनों सिरों पर लैंडिंग पैड की आवश्यकता होती है; प्रति उड़ान 2-5 लाख रुपये खर्च; वंदे भारत की लागत 5,000-10,000 रुपये है, मौसम-स्वतंत्र है, और सभी प्रमुख अस्पतालों के पास स्टेशन नेटवर्क है।
- प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 (THOA): मानव अंग अधिनियम 1994 का प्रत्यारोपण भारत में अंग दान को नियंत्रित करता है; अनिवार्य मस्तिष्क मृत्यु प्रमाणन; पारिवारिक सहमति; आईटीओ और राज्य अंग प्रत्यारोपण संगठन समन्वय रसद - वंदे भारत इस रसद श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है
- 25 अमृत भारत स्टेशन: पीएम मोदी ने इस सप्ताह देश में 75 अमृत भारत स्टेशनों को समर्पित किया; इन उन्नत स्टेशनों को अस्पतालों और चिकित्सा अवसंरचना के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकसित किया जा रहा है - उसी हेल्थकेयर + रेलवे एकीकरण कहानी का हिस्सा
- ऑर्गन दान की दर: भारत की अंग दान दर 0.8 मिलियन आबादी है, जो स्पेन की 46 मिलियन प्रति मिलियन है; परिवहन रसद में सुधार (इसलिए कटाई वाले अंगों का उपयोग विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है) अंग दान कार्यक्रमों में सार्वजनिक विश्वास के निर्माण में एक कारक है।
- रेलवे आपातकालीन प्रोटोकॉल: वर्तमान प्रोटोकॉल के लिए आपातकालीन ट्रेन स्टॉप के लिए जिला मैजिस्ट्रेट अनुमति की आवश्यकता होती है; प्रस्तावित नया प्रोटोकॉल 30 मिनट की खिड़की के भीतर नामित स्टॉप पर वैनेड भारत ट्रेनों को बोर्ड करने के लिए आईटीओ-प्रमाणित ऑर्गन ट्रांसपोर्ट टीमों को अनुमति देगा।

- व्यापक प्रभाव: यह घटना दर्शाता है कि वंदे भारत का अवसंरचना मूल्य यात्री गतिशीलता से परे है - यह कई क्षेत्रों में उपलब्ध एक तेजी से परिवहन संसाधन है; आपातकालीन रक्त आपूर्ति, टीके (ठंडा श्रृंखला) और आपदा राहत उपकरण अन्य संभावित अनुप्रयोग हैं।
- 120 वंदे भारत लक्ष्य: भारत ने 2027 तक 120 वंदे भारत ट्रेनें की योजना बनाई; नेटवर्क घनत्व बढ़ने के रूप में, ऑर्गन-ट्रांसपोर्ट उपयोगिता समान रूप से बढ़ जाती है - 160 किमी/h से जुड़े अधिक शहर के जोड़े का मतलब है कि अधिक व्यवहार्य अंग समय पर मरीजों तक पहुंचते हैं।

TOY SECTOR TASK FORCE — 5% GLOBAL MARKET SHARE BY 2032

मंत्रालय:वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / डीपीआईआईटी

PIB तिथि: 27 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

2014-15 में, भारत ने खिलौने का 80% आयात किया - लगभग पूरी तरह से चीन से। भारतीय खिलौना निर्माता चीनी कारखानों के पैमाने, स्वचालन, कम श्रम लागत और आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। 2023-24 तक, इस तस्वीर को नाटकीय रूप से उलट दिया गया था: भारत अपने खिलौने का केवल 20% आयात कर रहा था और एक महत्त्वपूर्ण खिलौना निर्यातक बन गया था। इस बदलाव का एक संयोजन के कारण हुआ: आयातित खिलौने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश बीआईएस (भारतीय मानक के ब्यूरो) प्रमाणन (आयात करने के लिए उपमानक चीनी खिलौने अवैध बनाने), घरेलू खिलौने निर्माताओं के लिए पीएलएआई-प्रकार प्रोत्साहन, और भारतीय खिलौने खरीदने के लिए मन की बात (2020) में पीएम मोदी की स्पष्ट कॉल (स्थानीय के लिए वोकल)। भारत का खिलौना निर्यात वित्त वर्ष2025-26 में 89.1% तक बढ़ गया - इस वर्ष किसी भी प्रमुख निर्यात श्रेणी की सबसे तेजी से वृद्धि दर। इस सप्ताह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विशेष रूप से खिलौना क्षेत्र का समर्थन करने के लिए एक कार्यबल की घोषणा की, जिसमें भारत के वर्तमान ~ 1.5% तक 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार हिस्सेदारी का 5% कब्जा करने का लक्ष्य था। वैश्विक खिलौना बाजार सालाना 110 बिलियन डॉलर है; 5% का मतलब भारत की 1.4 बिलियन आबादी के लिए निर्यात और घरेलू उत्पादन में 5.5 बिलियन डॉलर होगा। टास्क फोर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा: डिजाइन क्षमता (भारत में विनिर्माण कौशल है लेकिन खिलौना डिजाइन विशेषज्ञता की कमी है); खिलौना पात्रों के लिए आईपीआर (भारतीय खिलौना आईपी बनाना जो वैश्विक स्तर पर लेगो या बार्बी की तरह लाइसेंस प्राप्त हो सकता है); गुणवत्ता प्रमाणन बुनियादी ढांचा (खिलौने परीक्षण के लिए अधिक बीआईएस प्रयोगशाला); और क्लस्टर विकास (राजकोट, बेंगलुरु, कांचीपुरम खिलौना क्लस्टर)।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
खिलौना क्षेत्र परिवर्तन (Toy sector transformation)	भारत का खिलौना आयात हिस्सा: 80% (2014) → 20% (2024); निर्यात FY2025-26 में 89.1% बढ़ गया; PLI + BIS गुणवत्ता आदेश + स्थानीय + क्लस्टर विकास के लिए वोकल इस उलटा
BIS खिलौना प्रमाणीकरण (BIS toy certification)	भारतीय मानक ब्यूरो सभी खिलौने (आयातित और घरेलू) के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण; IS 9873 मानकों की श्रृंखला; सुरक्षा के लिए परीक्षण (sharp किनारों, छोटे भागों, विषाक्त पेंट, ज्वलनशीलता); गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अवरुद्ध घटिया चीनी आयात

कार्य बल जनादेश (Task Force mandate)	2032 तक 5% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी; ध्यान क्षेत्र: डिजाइन क्षमता, खिलौना आईपी निर्माण, बीआईएस परीक्षण अवसंरचना, खिलौना क्लस्टर विकास, निर्यात बाजार विविधीकरण
खिलौना क्लस्टर (Toy clusters)	राजकोट (गुजरात): लकड़ी और प्लास्टिक के खिलौने; बेंगलुरु: शैक्षिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने; काँचीपुरम (TN): पारंपरिक कपड़ा गुड़िया और लकड़ी के खिलौने; चन्नापत्ना (कर्नाटक): यूनेस्को- मान्यता प्राप्त पारंपरिक लाहौर के खिलौने
चन्नपटना के खिलौने (Channapatna toys)	कर्नाटक के पारंपरिक lacquered लकड़ी के खिलौने; 800+ साल के लिए इस्तेमाल किया; aale लकड़ी और प्राकृतिक रंगों के साथ बनाया गया; जीआई टैग; केवीआईसी उन्हें बढ़ावा देता है; यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध - प्रीमियम निर्यात क्षमता
$110 बिलियन वैश्विक खिलौना बाजार ($110 billion global toy market)	संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी सबसे बड़ा बाज़ार है; चीन विनिर्माण पर हावी है; भारत का लक्ष्य: $5.5 बिलियन निर्यात + $10-15 बिलियन घरेलू by 2032; कुल भारत खिलौना उद्योग लक्ष्य ~ $20 बिलियन
PLI खिलौने के लिए (PLI for toys)	1,000 करोड़ रुपये PLI-type प्रोत्साहन (खिलौने सेक्टर 2021) को बढ़ावा देने के लिए योजना; पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने दोनों को शामिल किया गया; खिलौना विनिर्माण में कंपनियों को निवेश करना प्रोत्साहन देता है > 10 करोड़ रुपये

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 89.1% निर्यात वृद्धि: भारत की सबसे तेजी से बढ़ती निर्यात श्रेणी FY2025-26 में; $150 मिलियन (2014-15) से $326 मिलियन (2023-24) तक लगभग $620 मिलियन (2025-26) - अभी भी मामूली लेकिन प्रक्षेपवक्र परिवर्तनशील है
- डिजाइन अंतर: चीन खिलौना डिजाइन में जीतता है क्योंकि इसमें एक विशाल डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र (सीएडी विशेषज्ञों, उत्पाद डिजाइनरों, सामग्री इंजीनियरों) है; भारत का खिलौना उद्योग अभी भी चीनी डिजाइनों की प्रतिलिपि बना रहा है; कार्यबल विशेष रूप से एक राष्ट्रीय खिलौना डिजाइन संस्थान बनाता है इसकी पहली सिफारिश के रूप में
- खिलौना पात्रों के लिए आईपीआर: लेगो प्लास्टिक ईंटों की बिक्री से लाइसेंसिंग (मूवियां, खेल, थीम पार्क) से अधिक कमाई करता है; बार्बी का आईपी भौतिक गुड़िया से अधिक है; भारत को वैश्विक सांस्कृतिक अपील के साथ खिलौना वर्ण बनाना चाहिए जिसे लाइसेंस दिया जा सकता है - टास्क फोर्स में एक 'इंडियन आईपी निर्माण' जनादेश शामिल है
- स्थानीय प्रभाव के लिए वोकल: PM मोदी के 2020 मैन की बैट कॉल फॉर इंडियन टोय्स को उपभोक्ता वरीयता शिफ्ट को ट्रिगर करने के साथ श्रेय दिया गया था; बीआईएस गुणवत्ता आदेश (जो अलमारियों से घटिया चीनी खिलौने हटा दिया गया) के साथ संयुक्त, भारतीय खिलौने ने शेल्फ स्पेस पाया कि वे पहले नहीं कर सकते थे।
- पारंपरिक खिलौने पुनरुत्थान: कोंडापाली (AP), एटिकोप्पका (AP), चन्नापत्तन (कर्नाटक), किन्हल (कर्नाटक), वाराणसी (UP) पारंपरिक खिलौना समूहों को आईसन क्लस्टर + जीआई टैग संयोजन के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है; इनमें यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में निर्यात प्रीमियम क्षमता है जो 'authentic, टिकाऊ' खिलौने की तलाश में है।

- राष्ट्रमंडल खेलों के खेल के सामान: भारत जालंधर (पंजाब) में खेल के सामान के निर्माण को भी पुनर्जीवित कर रहा है; खेल के सामान तकनीकी रूप से व्यापार वर्गीकरण में 'खिलौने' की उप-श्रेणी हैं; 89.1% खिलौना निर्यात वृद्धि में खेल के सामान का विकास - व्यापक क्षेत्रीय पुनरुद्धार शामिल है।
- खिलौना उद्योग रोजगार: भारत का खिलौना उद्योग 28 लाख लोगों (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) को रोजगार देता है; यदि 5% वैश्विक शेयर 2032 तक हासिल किया जाता है, तो रोजगार 50 लाख तक पहुंच सकता है - श्रम-गहन विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण नौकरी निर्माण

INDIA'S FIGHT TO COMBAT HEPATITIS — PIB BACKGROUNDER, NVHCP 8 YEARS

मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / एनवीएचसीपी

PIB तिथि: 28 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई है - नोबेल पुरस्कार विजेता विरोलॉजिस्ट बारूच ब्लमबर्ग के जन्मदिन को चिह्नित करने के लिए चुना गया, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की। इस वर्ष 2018 में शुरू होने वाले भारत के राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम (एनवीएचसीपी) की 8 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। हेपेटाइटिस वास्तव में यकृत की सूजन का मतलब है। वायरल हेपेटाइटिस प्रकार ए, बी, सी, डी और ई बहुत अलग संचरण मार्गों, नैदानिक पाठ्यक्रमों और परिणामों के साथ पांच अलग वायरस के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और पानी के माध्यम से प्रेषित होते हैं - वे तीव्र बीमारी का कारण बनते हैं लेकिन शायद ही कभी पुरानी बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी और सी चुप हत्यारों हैं: रक्त (संदूषित सुई, रक्त आधान, बच्चे को मां) के माध्यम से प्रेषित, वे दशकों तक पुराने संक्रमण का कारण बन सकते हैं, जिससे सिरोसिस (लिवर स्कार्फिंग) और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा (लिवर कैंसर) हो सकता है। भारत में पुरानी हेपेटाइटिस बी और 1 करोड़ लोगों के साथ पुरानी हेपेटाइटिस सी के साथ अनुमानित 4 करोड़ लोग हैं - जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े बोझ वाले देशों में से एक बन गया है। डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य: 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना (90% तक नए संक्रमण और 65% तक मृत्यु दर को कम करना)। NVHCP का 8-year रिपोर्ट कार्ड: हेपेटाइटिस बी टीकाकरण को 2002 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) में एकीकृत किया गया; हेपेटाइटिस सी उपचार (Direct-Acting Antivirals, DAAs) ने 2018 से सरकारी सुविधाओं पर मुफ्त प्रदान की; 1.5 करोड़ लोगों का परीक्षण; 5 लाख + हेपेटाइटिस सी रोगियों का इलाज; न्यू हेपेटाइटिस सी संक्रमण declining। लेकिन अंतराल रहते हैं: हेपेटाइटिस बी के केवल 20% संक्रमित लोग अपनी स्थिति को जानते हैं; हेपेटाइटिस बी के लिए उपचार कवरेज मुश्किल से 10% है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (NVHCP)	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम; 2018 लॉन्च किया गया; HBV + HCV परीक्षण, उपचार और टीकाकरण को शामिल किया गया; लक्ष्य: डब्ल्यूएचओ 2030 हेपेटाइटिस उन्मूलन लक्ष्य
हेपेटाइटिस बी (HBV) (Hepatitis B (HBV))	डीएनए वायरस; रक्त जनित + यौन + मां-से-बच्चा संचरण; वयस्कों के 5-10% में पुरानी संक्रमण, जन्म से संक्रमित शिशुओं का 90%; टीका उपलब्ध (3-dose अनुसूची, जन्म + 6 + 14 सप्ताह UIP में)

हेपेटाइटिस सी (HCV) (Hepatitis C (HCV))	RNA वायरस; मुख्य रूप से रक्त जनित (sharing सुई, दूषित उपकरण); कोई टीका नहीं; DAAs (Direct-Acting Antivirals) इलाज 95%+ 12 सप्ताह में; सरकार NVHCP के तहत मुक्त DAA उपचार प्रदान करती है
प्रत्यक्ष-क्रियाशील विषाणुरोधी औषधियाँ (Direct-Acting Antivirals—DAAs)	चिकित्सा जो सीधे एचसीवी प्रतिकृति को लक्षित करती हैं; इलाज की दर 95%+; 12 सप्ताह का उपचार; पहले हेपेटाइटिस सी विकासशील देशों में इलाज योग्य था; भारत के सामान्य विनिर्माण के कारण लागत 80,000 डॉलर/कोर्स (2014) से 15,000 रुपये (2026) तक गिर गई है।
सिरोसिस (Cirrhosis)	क्रोनिक यकृत रोग जहां सामान्य यकृत ऊतक को निशान ऊतक (फाइब्रोसिस) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है; लंबे समय तक शराब के उपयोग के कारण, वायरल हेपेटाइटिस, फैटी यकृत रोग; यकृत की विफलता और यकृत कैंसर की ओर जाता है अगर इलाज नहीं किया जाता है
हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) (Hepatocellular Carcinoma (HCC))	प्राथमिक यकृत कैंसर; हेपेटाइटिस बी वैश्विक स्तर पर #1 का कारण है; हेपेटाइटिस सी #2 है; भारत में 25,000+ नए एचसीसी मामले/वर्ष हैं; एनवीएचसीपी के माध्यम से एचबीवी / एचसीवी संक्रमण को रोकने से एचसीसी को रोका जा सकता है - टीकाकरण कैंसर की रोकथाम है।
डब्ल्यूएचओ 2030 लक्ष्य (WHO 2030 targets)	वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में खत्म करें: 90% तक नए HBV / HCV संक्रमण को कम करें, 2015 बेसलाइन से 65% तक हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों को कम करें; भारत इस WHO लक्ष्य के लिए एक हस्ताक्षरकर्ता है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत का हेपेटाइटिस बोझ: 4 करोड़ क्रोनिक एचबीवी (चीन, नाइजीरिया के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा); 1 करोड़ क्रोनिक एचसीवी; 1.5 लाख मौत सालाना HBV + HCV से संबंधित यकृत रोग से; HBV भारत के जिगर के कैंसर के मामलों का 50%+ कारण बनता है।
- HBV टीकाकरण की सफलता: भारत ने 2002 में HBV वैक्सीन को UIP में जोड़ा (जन्म खुराक + 3- खुराक श्रृंखला); टीकाकरण कवरेज 85-90% तक पहुंच गया है; आज भारत में पैदा होने वाला एक बच्चा HBV के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा है - NVHCP की सबसे अधिक दिखाई देने वाली सफलता
- HCV उपचार क्रांति: भारत का जेनेरिक फार्मा उद्योग (नाटो, सिप्ला, मायलन) रिवर्स-इंजीनियर Sofosbuvir (की प्रमुख DAA) - $ 80,000 से लेकर 12 सप्ताह के इलाज तक की लागत को कम करना; यह भारत का 'दुनिया की फार्मेसी' है जो अपने नागरिकों पर प्रभाव डालती है।
- जागरूकता अंतर: हेपेटाइटिस बी रोगियों का केवल 20% पता है कि वे संक्रमित हैं (एचबीवी अक्सर दशकों तक स्पर्शोन्मुख है); हेपेटाइटिस सी रोगियों का केवल 30% पता है; एनवीएचसीपी के परीक्षण पैमाने (1.5 करोड़ परीक्षण) को 90% कमी लक्ष्य तक पहुंचने में तेजी लाना चाहिए।

- इंजेक्शन सुरक्षा: भारत के हेपेटाइटिस सी बोझ का 40-60% असुरक्षित इंजेक्शन प्रथाओं (छोटे क्लीनिकों में सिरिंजों का उपयोग) से है; एनवीएचसीपी के तहत इंजेक्शन सुरक्षा कार्यक्रम एकल उपयोग सिरिंजों को जनादेश देता है; एचसीवी ट्रांसमिशन मार्गों के रूप में टैटू और बर्बरता को भी संबोधित करता है।
- ड्रग यूज़र लिंक: जिन लोगों ने ड्रग्स (PWID) को इंजेक्शन दिया है, उनमें हेपेटाइटिस C की 40-60% की व्यापकता है; हर्म न्यूनीकरण कार्यक्रम (सुई विनिमय, OST — opioid प्रतिस्थापन चिकित्सा) इस आबादी में HCV उन्मूलन के लिए आवश्यक हैं; NVHCP में नुकसान में कमी के घटक शामिल हैं।
- लिवर प्रत्यारोपण की मांग: भारत 3,000+ यकृत प्रत्यारोपण / वर्ष करता है लेकिन 30,000+ की आवश्यकता होती है; अधिकांश यकृत विफलताएं एचबीवी / एचसीवी से संबंधित हैं; वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने से यकृत प्रत्यारोपण की मांग को 50-60% तक कम हो जाएगी - एनवीएचसीपी एक स्वास्थ्य देखभाल लागत रोकथाम रणनीति भी है।

INDIA LEADS THE WILDERNESS — TIGER CONSERVATION PIB BACKGROUNDER, GLOBAL TIGER DAY

मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे - 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया जहां 13 टाइगर रेंज देशों (Tx2 देशों) ने 2022 तक जंगली टाइगर आबादी को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध किया। भारत स्टार कलाकार था: 2006 में भारत में 1,411 टाइगर थे; 2022 तक, उस संख्या में 3,682 हो गया था। भारत न केवल Tx2 दोगुना लक्ष्य से मेल खाता है बल्कि इससे अधिक है - 3,682 2006 आबादी का 2.6 गुना है। भारत की सफलता - जो अब दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75%+ घर है - तीन स्तंभों पर निर्मित 50+ वर्षों की लगातार संरक्षण नीति का परिणाम है: निवास स्थान, शिकार और शिकार से सुरक्षा। प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में PM इंदिरा गांधी द्वारा दुनिया के पहले प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक के रूप में लॉन्च किया गया, ने कड़ाई से संरक्षित कोर जोनों (जहां कोई मानव निपटान या गतिविधि की अनुमति नहीं है) और बफर जोनों के साथ टाइगर रिजर्व की एक प्रणाली बनाई (जहां कुछ पारंपरिक गतिविधियों की अनुमति है लेकिन पर्यटन और व्यावसायिक शोषण को सख्ती से विनियमित किया जाता है)। सिस्टम को लगातार परिष्कृत कर दिया गया है: एनटीसीए (राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण) को 2005 में सांविधिक शक्तियों के साथ बनाया गया था; कैमरे के जाल (व्यक्तिगत बाघों की फोटोग्राफिक पहचान) ने पगमार्क-आधारित गिनती (जो गलत था); M-STRIPES (टाइगर्स के लिए निगरानी प्रणाली - गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति) वास्तविक समय के क्षेत्र की निगरानी के लिए विकसित किया गया था; और पशुधन हानि के लिए मुआवजा योजनाओं ने बाघों की ओर सामुदायिक शत्रुता को कम कर दिया। इस सप्ताह के पीआईबी बैकग्राउंडर ने यह भी खुलासा किया है: नए भंडारों (अल्वार कार्यशाला, सप्ताह 5 संक्षिप्त) के लिए टाइगर रिइंट्रोडक्शन पर चर्चा, एक 56 वें बाघ आरक्षित (छत्तीसगढ़ में संभवतः) की योजना बना रही है, और अगले ग्लोबल टाइगर फोरम की मेजबानी के लिए भारत का प्रस्ताव।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा

बाघ परियोजना (Project Tiger)	प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1973 का शुभारंभ किया गया; दुनिया का पहला प्रमुख बाघ संरक्षण कार्यक्रम; 18 राज्यों में 55 टाइगर रिजर्व; भारत के भूमि क्षेत्र का 2.9% कवर; बजट 1,000+ करोड़/वर्ष
वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य (Tx2)	2010 सेंट पीटर्सबर्ग की प्रतिबद्धता 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा 2022 तक जंगली टाइगर आबादी को दोगुना करने के लिए; भारत लक्ष्य से अधिक (1,411 में 2010 से 3,682 में 2022 = 2.6x वृद्धि); रूस, नेपाल भी सफल रहा।
टाइगर रिजर्व संरचना (Tiger Reserve structure)	कोर जोन (क्रिस्टिकल टाइगर हैबिटेट): सख्ती से संरक्षित, अनुमति के बिना कोई मानव प्रवेश नहीं; बफर जोन: स्थायी मानव गतिविधि की अनुमति; परिधीय क्षेत्र: मानव निपटान के साथ सह-अस्तित्व
बाघों की निगरानी हेतु एम-स्ट्राइप्स प्रणाली (M-STRIPES)	टाइगर्स के लिए निगरानी प्रणाली - गहन संरक्षण और पारिस्थितिक स्थिति; फील्ड स्टाफ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ऐप; जीपीएस-टैग्ड गश्ती डेटा; कैमरा जाल डेटा एकीकरण; कागज आधारित निगरानी की जगह
कैमरा-ट्रैप आधारित गणना (Camera trap census)	अद्वितीय धारी पैटर्न (जैसे मानव फिंगरप्रिंट) द्वारा पहचाने गए व्यक्तिगत बाघ; पानी के छेद और ट्रेल्स पर कैमरा जाल; भारत की 2022 जनगणना ने 90 परिदृश्यों में 26,000+ कैमरा स्टेशनों का उपयोग किया - दुनिया का सबसे कठोर वन्यजीव सर्वेक्षण
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण; डब्ल्यूपीए 1972 संशोधन 2006 के तहत सांविधिक निकाय; पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में; परियोजना टाइगर का प्रबंधन; बाघ भंडार को डी-नोटिफाइड कर सकता है; संरक्षण आश्वासन टाइगर स्टैंडर्ड (सीएए) निधि आवंटित करता है।
ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) (Global Tiger Forum (GTF))	बाघ संरक्षण के लिए अंतर सरकारी निकाय; भारत एक संस्थापक सदस्य है; हर 4 साल से मिलता है; भारत ने अगले GTF की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया - दुनिया के जंगली बाघों के 75%+ के साथ नेतृत्व की स्थिति को दर्शाता है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- ऐतिहासिक ट्रेजेक्टरी: प्री-1900: भारत में 1 लाख बाघ → 1947: 40,000 बाघ → 1972: 1,827 बाघ (निकट-विस्तार करने के लिए शिकार) → 1973 प्रोजेक्ट टाइगर → 2006: 1,411 (Census, पूर्व-कैमरा जाल विधि - संभावित undercounted) → 2022: 3,682 (कैमरा जनगणना जाल, सटीक) - 50 वर्षों के लगातार संरक्षण दिखा परिणाम
- कैमरा जाल पद्धति: 26,000+ कैमरा जाल स्टेशन; स्ट्रिप पैटर्न द्वारा व्यक्तिगत बाघ पहचान; 2022 जनगणना ने पूरे भारत में 90 बाघ परिदृश्यों का सर्वेक्षण किया; 3 साल पूरे हो गए; वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान में प्रकाशित - दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण
- 55 टाइगर रिजर्व: 18 राज्यों में वितरित; सबसे बड़ा: Nagarjunasagar-Srisailam (AP, 3,568 वर्ग किमी); सबसे tigers: कॉर्बेट (250+, उत्तराखंड); नवीनतम जोड़: गुरु Ghasidas-Tamor Pingla (Chhattisgarh, 2022), रामगढ़ विशाधारी (Rajasthan, 2022)

- Prey base Recovery: टाइगर रिकवरी को प्री रिकवरी की आवश्यकता होती है; भारत की chital (spotted deer), सांबर, गौर आबादी भी काफी ठीक हो गई है; संरक्षित क्षेत्र जो 1972 (WPA) के बाद से शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, पहले की आबादी को पलटने की अनुमति दी है - टाइगर्स के बाद उसके बाद
- सामुदायिक सह-अस्तित्व: बाघ हमले से मानव मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये पूर्व-ग्रैटिया; पशुधन हत्या के लिए 2-25 लाख रुपये; कोर जोन (स्वच्छता पैकेज के साथ) से गांव का स्थानांतरण मानव-टाइगर संघर्ष हॉटस्पॉट को हटा दिया गया है - 1,500+ परिवारों को स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित कर दिया गया।
- टाइगर कॉरिडोर नेटवर्क: भारत में 32 पहचाने गए टाइगर कॉरिडोर हैं जो भंडार को जोड़ते हैं; कॉर्बेट-राजाजी, कान्हा-पेन के बीच कनेक्टिविटी, नागहोल-बांडीपुर आनुवंशिक अलगाव को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण है; राजमार्ग अंडरपास और ऊंचा वर्गों को विखंडन से गलियारों की रक्षा करते हैं।
- 56th टाइगर रिजर्व प्रस्ताव: छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु Ghasidas-Tamor Pingla (पहले एक राष्ट्रीय उद्यान) को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा; कान्हा और Achanakmar में मौजूदा बाघ आबादी को जोड़ देगा - रणनीतिक गलियारे लिंकेज

INDIA AS A TOURISM HUB — PIB BACKGROUNDER

मंत्रालय:पर्यटन मंत्रालय

PIB तिथि: 31 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

पर्यटन विदेशी विनिमय आय, रोजगार सृजन (विशेष रूप से ग्रामीण और विरासत क्षेत्रों में) और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण के लिए भारत का सबसे तेज़ मार्ग है। लेकिन भारत का पर्यटन प्रदर्शन संभावित रूप से नीचे रहा है। भारत को 2023 में 10.9 मिलियन विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) प्राप्त हुआ - फ्रांस (100 मिलियन), स्पेन (85 मिलियन), और थाईलैंड (28 मिलियन) की तुलना में। भारत में यकीनन दुनिया का सबसे विविध पर्यटन प्रस्ताव है: हिमालयी साहसिक (लाद्दाख, सिक्किम, उत्तराखण्ड) से समुद्र तट स्वर्ग (गोवा, केरल, अंडमान, लक्षद्वीप), प्राचीन विरासत (350+ यूनेस्को-नामित स्थल, 43 अंकित), वन्यजीव (55 बाघ भंडार, 106 राष्ट्रीय उद्यान, 571 अभयारण्य), आध्यात्मिक सर्किट (चाड़ धाम, बौद्ध सर्किट,) जैन तीर्थयात्रा मार्गों, और चिकित्सा पर्यटन (तेजी से बाद में COVID)। भारत की पर्यटन क्षमता और प्रदर्शन के बीच का अंतर यह है कि पीआईबी पृष्ठभूमि वाले पते क्या हैं। Viksit Bharat 2047 पर्यटन दृष्टि लक्ष्य: 150 मिलियन FTAs by 2047 (15x वर्तमान), पर्यटन भारत का सबसे बड़ा विदेशी विनिमय कमाने वाला (वर्तमान में सॉफ्टवेयर, प्रेषण, व्यापार निर्यात, FDI) बना रहा है। सप्ताह के पीआईबी ने यह भी खुलासा किया: पर्यटन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को सहयोग देने के लिए एयर इंडिया (इस सप्ताह) और इंडिगो (इस सप्ताह) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; 'भारत में अविश्वसनीय' ब्रांड को एक युवा, साहसिक-देखने वाले वैश्विक यात्रियों के लिए फिर से डिजाइन किया जा रहा है; और एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2025 को एमआईसी (मेटिंग्स, इनसेंटिव्स, सम्मेलनों, बैठकों,) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदर्शनी, चिकित्सा पर्यटन, और क्रूज पर्यटन।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
विदेशी पर्यटक आगमन (Foreign Tourist Arrivals—FTA)	भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक; 2023 में 10.9 मिलियन; लक्ष्य 150 मिलियन 2047 तक; भारत का FTA अपनी पर्यटन संपत्ति को देने की क्षमता से बहुत कम है।

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पर्यटन (MICE Tourism)	बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनी; उच्च मूल्य व्यापार पर्यटन; भारत दिल्ली (IICC द्वारका), मुंबई, हैदराबाद (HICC), बेंगलुरु (BIEC) में सम्मेलन केंद्र का निर्माण कर रहा है; MICE आगंतुक अवकाश पर्यटक से 3-5x अधिक खर्च करते हैं।
चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism)	स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक देश का दौरा करना; भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चिकित्सा पर्यटन स्थल ($ 9 अरब); एम्स, मेडांटा, अपोलो, फोर्टिस 150+ देशों के रोगियों को आकर्षित करते हैं; लागत बराबर प्रक्रियाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका / यूके से 60-80% कम है।
अतुलनीय भारत (Incredible India)	2002 से भारत का पर्यटन ब्रांड; फिर से डिजाइन किया जा रहा है; नई स्थिति युवा वैश्विक यात्रियों के लिए साहसिक, कल्याण, विरासत और टिकाऊ पर्यटन पर जोर देती है।
क्रूज पर्यटन (Cruise Tourism)	भारत को मुंबई, कोचीन, गोवा, चेन्नई में 800,000 क्रूज यात्रियों / वर्ष प्राप्त हुआ; लक्ष्य 4 मिलियन से 2030 तक; क्रूज टर्मिनलों में बुनियादी निवेश; विज़िन्जाम (केराला) गहरे पानी का बंदरगाह भारत का पहला समर्पित क्रूज हब होगा
एयर इंडिया + इंडिगो मोउ (Air India + IndiGo MoUs)	दोनों एयरलाइनों ने इस सप्ताह पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; एयरलाइन्स भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय विपणन में एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगा; पारस्परिक रूप से, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन स्थलों को संरक्षित करने के लिए सीधे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया।
विक्सित भारत 2047 पर्यटन लक्ष्य (Viksit Bharat 2047 tourism target)	2047 तक 150 मिलियन FTA; $ 300 बिलियन पर्यटन GDP 2047 तक; भारत के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में पर्यटन (GDP बनाम वर्तमान 5% का 10% लक्ष्य); बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और वीज़ा नीति सुधार की आवश्यकता है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- क्यों भारत अंडरपरफॉर्म्स: इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतराल (अधिकांश विरासत स्थलों के लिए गरीब सड़कों, टायर-2 शहरों में सीमित आवास); वीजा प्रक्रिया जटिलता (e-Visa मौजूद है लेकिन सुधार किया जा सकता है); अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब विपणन (Incredible India underfund बनाम फ्रांस की Atout France); सुरक्षा धारणा; कई साइटों पर स्वच्छता की चिंता
- FTA तुलना: फ्रांस (100M FTAs, $74B राजस्व), स्पेन (85M FTAs, $80B राजस्व), भारत (10.9M FTAs, $20B राजस्व) - भारत स्पेन के $941 बनाम प्रति पर्यटक $ 1,835 कमाने; भारत कम मात्रा को आकर्षित करता है लेकिन उच्च खर्च आगंतुक - आला प्रीमियम स्थिति यथार्थवादी है
- आध्यात्मिक पर्यटन क्षमता: 300 मिलियन घरेलू तीर्थयात्री / वर्ष (चार धाम, शिरडी, वैष्णो देवी, तिरुपति, बोध गया, आदि); वाराणसी को 7+ करोड़ घरेलू आगंतुक / वर्ष प्राप्त होता है; काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार लाने में उन्नयन करता है।
- सरनाथ यूनेस्को (कला 1 इस सप्ताह): सरनाथ का शिलालेख सीधे बौद्ध सर्किट पर्यटन को बढ़ावा देता है; पर्यटन मंत्रालय बौद्ध सर्किट (Lumbini-Bodh Gaya-Sarnath-Kushinagar) को भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उत्पाद के रूप में विकसित कर रहा है 10 एशियाई देशों को लक्षित करना

- चिकित्सा पर्यटन विकास: भारत की चिकित्सा पर्यटन 2022-23 में 40% बढ़ी; पारंपरिक चिकित्सा (Ayurveda, Panchakarma) पर्यटन सबसे तेजी से बढ़ते खंड है; केरल के आयुर्वेद पर्यटन अकेले 5 लाख अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों / वर्ष को आकर्षित करता है; AYUSH ब्रांडेड कल्याण पर्यटन एक $5 बिलियन अवसर है।
- पर्यटन रोजगार: भारत का पर्यटन क्षेत्र सीधे 87 लाख लोगों को रोजगार देता है; अप्रत्यक्ष रूप से 3+ करोड़ का समर्थन करता है; पर्यटन में हर $1 बिलियन 75,000 नौकरियों का निर्माण करता है (vs $1 बिलियन विनिर्माण = 55,000 नौकरियों); पर्यटन भारत का सबसे श्रम-गहन औपचारिक क्षेत्र गतिविधि है।
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2025 (अंतिमीकृत किया जा रहा है): प्रमुख प्रस्ताव - ई-वीज़ा विस्तार से 170+ देश; 24 घंटे ई-वीज़ा प्रसंस्करण; शीर्ष 50 स्थलों में समर्पित पर्यटन पुलिस; पर्यटन अवसंरचना विकास निधि (टीआईडीएफ); गाइड की रेटिंग और मान्यता

PM VIDYALAXMI SCHEME — COLLATERAL-FREE HIGHER EDUCATION LOANS

मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय / शिक्षा विभाग

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत में एक अच्छा कॉलेज में हो रही है काफी प्रतिस्पर्धी है। लेकिन मध्यम वर्ग और निचले वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए - जिनके पास संपार्श्विक के रूप में पेश करने के लिए संपत्ति नहीं है - इसके लिए भुगतान करने के लिए एक बैंक ऋण प्राप्त करना एक और बाधा को जोड़ता है जो धनी परिवारों के छात्रों को बस सामना नहीं करना पड़ता है। एक छात्र जिसका माता-पिता एक घर का मालिक है, उसे शिक्षा ऋण के लिए बंधक सुरक्षा के रूप में उपयोग कर सकता है। एक छात्र जिसका परिवार अपने घर किराए पर लेता है, या जिसका माता-पिता किसानों को केवल कृषि भूमि (जो अक्सर बैंकों को संपार्श्विक के रूप में मना कर देता है) के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। PM Vidyalaxmi — इस योजना का विस्तार करने वाला एक पीआईबी पृष्ठभूमिर इस सप्ताह जारी किया गया था - सरकार का जवाब है। पीएम मोदी की घोषणा के तहत 2024 में लॉन्च किया गया, PM Vidyalaxmi प्रदान करता है: कोलैटरल-मुक्त शिक्षा ऋण सभी छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान (QHEIs - आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स और अन्य एनआईआरएफ-ranked संस्थानों सहित शीर्ष रैंक वाले संस्थानों की एक सरकारी नामित सूची); प्रति वर्ष 8 लाख रुपये से कम आयु के छात्रों के लिए 7.5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए 3% ब्याज की कमी; और एक केंद्रीय क्रेडिट गारंटी (सरकारी बैंक को ऋण की गारंटी देता है यदि छात्र डिफ़ॉल्ट हो) - बैंक के जोखिम को हटाकर और उन्हें बिना किसी संपार्श्विक के छात्रों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना एक एकीकृत पोर्टल (vidyalaxmi.gov.in) का उपयोग करती है जहां छात्र एक बार आवेदन करते हैं और कई बैंकों से ऑफर प्राप्त करते हैं - बैंक-by-bank जाने के बजाय बाज़ार दृष्टिकोण। इस सप्ताह के पीआईबी बैकग्राउंडर कार्यान्वयन की स्थिति देता है: 12 लाख एप्लिकेशन संसाधित; 8,500 करोड़ रुपये स्वीकृत; 38 बैंक भाग लेते हैं।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi)	संपार्श्विक मुक्त शिक्षा ऋण योजना; 10 लाख रुपये तक; गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए; आय के लिए 3% ब्याज अनुदान <Rs 8 लाख; केंद्रीय क्रेडिट गारंटी
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (QHEI)	विद्यालैक्समी के लिए पात्र शीर्ष संस्थानों की सरकारी नामित सूची; सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम आई एम एस, शीर्ष एनआईआरएफ-ranked निजी कॉलेज शामिल हैं; वर्तमान में ~860 संस्थानों ने नामित किया

एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) (NIRF (National Institutional Ranking Framework))	HEIs के लिए भारत की राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली; शिक्षा मंत्रालय; 5 पैरामीटर: शिक्षण / शिक्षा / संसाधन, अनुसंधान, आउटरीच, धारणा, स्नातक परिणाम; शीर्ष 200 संस्थानों को सालाना 14 श्रेणियों में रैंक किया गया।
सेंट्रल क्रेडिट गारंटी (Central Credit Guarantee)	यदि उधारकर्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो सरकार बैंक को पुनर्भुगतान की गारंटी देती है; बैंक से क्रेडिट जोखिम को हटा देती है; नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) इसे Vidyalaxmi के तहत शिक्षा ऋण के लिए प्रबंधित करती है।
3% ब्याज अनुदान (3% interest subvention)	7.5 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए; पारिवारिक आय <Rs 8 लाख; बैंक शुल्क बाजार दर (10-12%); सरकार द्वारा छात्र की ओर से मोरेटरियम अवधि के दौरान 3% का भुगतान किया जाता है (ग्रेडेशन के बाद 1 वर्ष)
विद्यालक्ष्मी पोर्टल (Vidyalaxmi portal)	एकल अनुप्रयोग पोर्टल; छात्र एक बार लागू होता है; एकाधिक बैंक ऋण उत्पाद प्रदान करते हैं; छात्र तुलना करते हैं और चयन करते हैं; सप्ताह से दिन तक समय कम कर देता है; दस्तावेज़ जमा करने के लिए DigiLocker के साथ एकीकृत करता है
पिछली योजनाओं (Previous schemes)	CSIS (मध्य क्षेत्र ब्याज सब्सिडी): समान लेकिन 7.5 लाख रुपये तक सीमित; Vidyalaxmi 10 लाख रुपये तक का अंतर-मुक्त विस्तार देता है और क्रेडिट गारंटी को जोड़ता है कि बैंकों को बिना किसी संपार्श्विक के उधार देने की आवश्यकता होती है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- शिक्षा ऋण अंतर: भारत में केवल 35 लाख शिक्षा ऋण बकाया (वर्ष में उच्च शिक्षा में 2 करोड़ छात्र); अधिकांश छात्र या तो स्वयं वित्त पोषित या बाहर निकल जाते हैं; संपार्श्विक आवश्यकता सबसे बड़ी बाधा है - PM Vidyalaxmi इसे शीर्ष संस्था के छात्रों के लिए हटा देता है
- 12 लाख आवेदनों की प्रक्रिया: कार्यान्वयन स्थिति मजबूत मांग को दर्शाता है; 8,500 करोड़ रुपये मंजूर (प्रत्येक अनुमोदित ऋण के अनुसार 70,833 रुपये); 38 बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस शामिल हैं; निजी बैंकों की भागीदारी एक नया विकास है - पहले निजी बैंकों को कोलैटरल-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए अनिच्छुक थे।
- आईआईटी-NIT संदर्भ: आईआईटी वार्षिक शुल्क 2-8 लाख रुपये है; एनआईटी 1-2 लाख रुपये है; जिन छात्रों को ऋण के बिना इन फीस का भुगतान नहीं किया जा सकता है, वे गैर-सौंदर्य परिवारों से योग्य छात्र हैं जो भारत वित्तीय बाधाओं को नहीं खो सकते हैं - पीएम विद्यालक्ष्मी एक मेरिकी-सुरक्षा योजना है।
- एनआईआरएफ रैंकिंग लिंक: QHEI पदनाम NIRF रैंक लिंक है; चूंकि एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार (एनआईआरएफ 2026 ने इस सप्ताह जारी किया), अधिक संस्थान विद्यालक्ष्मी के लिए पात्र हो गए; निजी कॉलेजों में एनआईआरएफ रैंकिंग में सुधार करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन है - विद्यालक्ष्मी गुणवत्ता सुधार के लिए मांग-साइड दबाव बनाता है
- लैंगिक आयाम: रूढ़िवादी परिवारों के महिला छात्रों को दोहरी बाधाओं का सामना करना पड़ता है - पारिवारिक reluctance दूरदराज के कॉलेजों को बेटी भेजने के लिए और बिना किसी संपार्श्विक के ऋण से इनकार करते हैं; Vidyalaxmi की संपार्श्विक-मुक्त गारंटी विशेष रूप से महिला उच्च शिक्षा को सक्षम करती है - मंत्रालय के डेटा से पता चलता है कि 40%+ आवेदक महिला हैं

- पुनर्भुगतान moratorium: ऋण पुनर्भुगतान एक नौकरी प्राप्त करने के 12 महीने बाद शुरू होता है; छात्रों को अध्ययन अवधि के दौरान पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता; इस योजना को सुनिश्चित करने के लिए अधिस्थगन महत्त्वपूर्ण है वास्तव में छात्रों को ऋण चुकाने के बजाय शिक्षा पूरी करने में मदद करता है।
- NEP 2020 लिंक: NEP 2020 उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को लक्ष्य करता है जो 2035 (वर्तमान में 28%) तक पहुंचता है; PM Vidyalaxmi वित्तीय एक्सेस इंस्ट्रूमेंट है जो इस विस्तार को सक्षम बनाता है - GER बिना शिक्षा ऋण सुलभता समस्या को हल किए 50% तक नहीं पहुंच सकता है।

START-UP VILLAGE ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME (SVEP) — RURAL MICRO-ENTERPRISE SUPPORT

मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय / DAY-NRLM

PIB तिथि: 25 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाखों माइक्रो-एंटरप्राइज हैं: एक महिला ने अचार बनाने और उन्हें स्थानीय बाजार में बेच दिया, एक आदमी ने अपने गांव में मोटरसाइकिल की मरम्मत की, एक परिवार ने एक छोटी किराने की दुकान चलाई, एक कारीगर बांस का फर्नीचर बनाया। ये सिलिकॉन वैली अर्थ में 'स्टार्टअप' नहीं हैं - वे उत्तरजीविता उद्यम हैं, अक्सर अनौपचारिक, कम-सहयोगी और विकसित होने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास व्यावसायिक कौशल, बाजार लिंकेज और वित्त तक पहुंच की कमी है। स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) - इस सप्ताह एक पीआईबी पृष्ठभूमिर ने जारी किया - यह डीनडेल एंटियोडा योजना है - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-NRLM) इन ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को व्यवस्थित रूप से समर्थन देने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है। SVEP उद्यम संवर्धन (CRPEPs) के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से काम करता है - प्रशिक्षित स्थानीय उद्यमियों (आमतौर पर SHG सदस्यों खुद) जो अपने स्वयं के गांवों में उद्यम सलाहकार बन जाते हैं, आकांक्षा उद्यमियों की पहचान करते हुए, अपने व्यवसाय के विचारों का आकलन करते हुए, कार्यशील पूंजी के लिए बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करते हैं, और 6-12 महीनों तक स्टार्ट-अप हैंडहोल्डिंग प्रदान करते हैं। यह सहकर्मी से सहकर्मी समर्थन मॉडल सरकारी रूप से डिजाइन किए गए एक-आकार-फिट-सभी प्रशिक्षण की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है क्योंकि CRPEP स्थानीय अर्थव्यवस्था को समझते हैं, स्थानीय भाषा बोलते हैं और समुदाय के सदस्यों पर भरोसा करते हैं। PIB पृष्ठभूमिer ने खुलासा किया: SVEP को 16 राज्यों में 246 ब्लॉकों में लागू किया गया है; 5 लाख+ ग्रामीण उद्यमों का समर्थन किया; 1.5 लाख+ नए उद्यमों की शुरुआत हुई; SVEP समर्थन के बाद औसत उद्यम आय 40-60% बढ़ गई।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)	स्टार्ट-अप गांव उद्यमिता कार्यक्रम; DAY-NRLM का घटक; प्रशिक्षित CRPEPs के माध्यम से ग्रामीण सूक्ष्म उद्यम का समर्थन करता है; 16 राज्यों में 246 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया।
दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; फ्लैगशिप ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम; 15,000+ करोड़ रुपये का बजट; SHG गठन, बैंक लिंकेज, आजीविका, SVEP, लाखपति दीदी को कवर करता है।

सामुदायिक संसाधन व्यक्ति—उद्यम संवर्धन (CRPEP)	उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति; प्रशिक्षित एसएचजी सदस्य जो अपने गांव में उद्यम सलाहकार बन जाते हैं; इच्छुक उद्यमियों की पहचान करता है, व्यावसायिक विचारों का आकलन करता है, वित्त की सुविधा देता है, स्टार्ट-अप समर्थन प्रदान करता है
ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) (Block Resource Centre (BRC))	DAY-NRLM अंतर्गत जिला/ब्लॉक-स्तर समर्थन संरचना; SVEP के तहत 246 BRC; CRPEP को प्रशिक्षण प्रदान करना, एंटरप्राइज़ योजनाओं के लिए तकनीकी सहायता, बैंक लिंकेज सुविधा प्रदान करना
लखपति दीदी (Lakhpati Didi)	DAY-NRLM का लक्ष्य: SHG महिलाओं को 1 लाख रुपये या उससे अधिक कमाई; SVEP लाखपति दीदी बनाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, जिससे उन्हें सूक्ष्म-प्रशिक्षण में मदद मिलती है; 2025 तक 1 करोड़ लाख लाख लाखपति दीदी लक्ष्य (partially मिले)
एसवीईपी के तहत एंटरप्राइज़ फाइनेंस (Enterprise Finance under SVEP)	SVEP सामुदायिक निवेश कोष (Cआईएफ) से रिवॉल्विंग फंड (Rs 15,000/enterprise प्रारंभिक) प्रदान करता है; बैंक ऋण SHG-बैंक लिंकेज के माध्यम से सुविधाजनक बनाता है; कुछ राज्यों में MFI ऋण; औसत ऋण का आकार 50,000-1,50,000 रुपये है।
PMEGP तुलना (PMEGP comparison)	PM रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): बड़े उद्यमों के लिए (Rs 25-50 लाख ऋण, 15-35% सब्सिडी); SVEP: सूक्ष्म उद्यम के लिए (<Rs 2 लाख); SVEP और PMEGP प्रपत्र भारत के ग्रामीण उद्यम समर्थन निरंतरता

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- SVEP के सहकर्मी से सहकर्मी मॉडल: CRPEPs को 5,000-7,000/माह के प्रदर्शन-आधारित स्टिपेंड का भुगतान किया जाता है; वे प्रत्येक 15-20 उद्यमों को संभालते हैं; 246 ब्लॉक x औसत 50 CRPEPs = 12,300 CRPEPs राष्ट्रीय स्तर पर; प्रत्येक CRPEP एक उद्यम सलाहकार, क्रेडिट फैसिलिटेटर और स्थानीय बाजार कनेक्टर है।
- 246 ब्लॉक कवरेज: SVEP अभी तक राष्ट्रीय नहीं है (डे-NRLM में 6,600+ ब्लॉक कुल है); 246 ब्लॉक एक पायलट-टू-स्केल चरण है; मूल्यांकन से पता चलता है कि SVEP ब्लॉकों में तुलनात्मक गैर-SVEP ब्लॉकों की तुलना में 35-40% उच्च उद्यम गठन दर है - राष्ट्रीय स्केल-अप ब्लॉकों के लिए सबूत
- एंटरप्राइज़ प्रकार समर्थित: कृषि प्रसंस्करण (फार्म उत्पादन के मूल्य के अलावा), विनिर्माण (पोटेरी, बुनाई, बांस), सेवाएं (मोबाइल मरम्मत, सिलाई, ड्राइविंग), व्यापार (छोटे दुकानें, इनपुट डीलर); SVEP क्षेत्र-न्यूट्रल है - किसी भी व्यवहार्य स्थानीय उद्यम का समर्थन हो जाता है
- पोस्ट-कोडित पुनरुत्थान: एसवीईपी एसएचजी महिलाओं को आजीविका के उद्यमों को पुनः आरंभ करने में मदद करने में महत्त्वपूर्ण था कि COVID-19 बाधित हो; सीआरपीईपी नेटवर्क ने COVID के माध्यम से काम करना जारी रखा क्योंकि वे गांव-आधारित हैं और शहरी-ग्रामीण प्रवास विघटन का सामना नहीं करते थे।
- लोकोसेस कनेक्शन: लोकोसेस (Week 6 संक्षिप्त) डिजिटल बाज़ार पहुंच परत प्रदान करता है; SVEP उद्यम समर्थन परत प्रदान करता है; साथ ही, एक SVEP समर्थित ग्रामीण उद्यमी अब लोकोसे के माध्यम से ONDC पर बेच सकते हैं - दो कार्यक्रम पूरक होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- भारत टेक्स 2026 से जुड़ता है: ग्रामीण महिला कारीगरों को हाथ से देखने और शिल्प में SVEP द्वारा समर्थित भारत टेक्स 2026 में 'लखपति दीदी' के तहत प्रदर्शित किया गया था; SVEP उत्पादन समर्थन कार्यक्रम है, भारत टेक्स एक ही महिला के लिए बाजार पहुंच मंच है।
- स्केल-अप योजना: एसवीईपी को अगले चरण में 246 से 1,000+ ब्लॉक तक विस्तारित किया जाना चाहिए; सीआरपीईपी को पेशेवर रूप से एनसीवीईटी (राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद) के माध्यम से प्रमाणित किया जाना चाहिए क्योंकि एंटरप्राइज डेवलपमेंट फैसिलिटेटर - औपचारिक व्यवसायिक क्रेडेंशियल

THE MAKING OF A SPORTING NATION — PIB BACKGROUNDER, CWG 2026

CONTEXT

मंत्रालय: युवा मामलों और खेल मंत्रालय

PIB तिथि: 28 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो असाधारण रूप से प्रदर्शन कर रहा है - भारोत्तोलन (मिराबाई चानू, शारिला) में स्वर्ण पदक, उच्च कूद (सरवेश कुश) में रजत, पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण और चांदी - पिछले दशक में भारत के व्यवस्थित खेल निवेश के परिणामों को दर्शाता है। पीआईबी पृष्ठभूमिर 'एक स्पोर्टिंग राष्ट्र का निर्माण' ने इस सप्ताह के निशान को जारी किया कि भारत का खेल पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बदल गया है। 2014 में, भारत ने सीडब्ल्यूजी (15 स्वर्ण सहित) में 64 पदक जीते। 2026 तक, ट्रेजेक्टरी शो ने मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। परिवर्तन में तीन स्तंभ होते हैं। फर्स्ट, खेलो इंडिया (लॉन्ड 2018) - एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें युवा एथलीटों को क्वालो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के माध्यम से जमीनी स्तर पर पहचानना शामिल है; 2,000+ युवा एथलीटों के लिए 5 लाख रुपये / वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करना; और सभी राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर (KIC) और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (KISCE) विकसित करना। दूसरा, TOPS (Target ओलम्पिक पोडियम योजना) - ओलंपिक पदकों को लक्षित करने वाले शीर्ष एथलीटों के लिए व्यक्तिगत समर्थन: कस्टम कोचिंग, विदेशी प्रशिक्षण एक्सपोजर, खेल विज्ञान समर्थन (फिजियोथेरेपी, मनोविज्ञान, पोषण) और 50,000 रुपये तक जीवित भत्ता। तीसरा, पुनरीक्षण एसएआई (Sports Authority of India) - विश्व स्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना के साथ SAI National Centers of एक्सीलेंस (SNICE) का उन्नयन किया। इस सप्ताह मंत्रिमंडल ने पुनः विकसित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दे दी जिसमें बढ़ी हुई परिव्यय - सिग्नलिंग निरंतर प्रतिबद्धता शामिल थी।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
खेलो इंडिया (Khelo India)	राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम; 2018 शुरू किया; खेलो इंडिया स्कूल / विश्वविद्यालय / शीतकालीन / परा खेल; 2,000+ वार्षिक छात्रवृत्ति; घास के मैदान के लिए खेलो इंडिया सेंटर; 6,000 करोड़ रुपये बढ़ी हुई योजना के तहत परिव्यय
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (TOPS)	लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना; अभिजात वर्ग एथलीट समर्थन कार्यक्रम; व्यक्तिगत कोचिंग, विदेशी एक्सपोजर, खेल विज्ञान समर्थन; 50,000 रुपये / माह का stipend; लक्ष्य ओलंपिक और पैरालंपिक पदक; मिशन ओलंपिक सेल ओवरसीज

भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India—SAI)	राष्ट्रीय खेल बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने वाले सरकारी निकाय; 24 SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र; कोच, प्रशिक्षण सुविधाएं, अभिजात वर्ग के एथलीटों के लिए छात्रावास; विश्व स्तरीय प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन से गुजरना
खेलो इंडिया सेंटर (KIC) (Khelo India Centre (KIC))	जिले/ब्लॉक स्तर पर ग्रासरूट खेल अवसंरचना; उपकरण, कोचिंग, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान; भारत भर में 1,000+ KIC; खेल पिरामिड के उच्च स्तर के लिए प्रतिभा फ़ीड
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एनएसएफ) (National Sports Federations (NSFs))	प्रत्येक खेल के लिए शासी निकाय (भारत के एथलीट्स फेडरेशन, बॉक्सिंग फेडरेशन, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन आदि); कैबिनेट ने इस सप्ताह NSF (ANSF) को सहायता प्रदान की; NSF शासन एक आवर्ती समस्या रही है।
CWG 2026 प्रदर्शन (CWG 2026 performance)	Glasgow, स्कॉटलैंड; भारत अच्छी तरह से प्रदर्शन - Mirabai Chanu सोने (भारोत्तोलन), Sharmila सोने (हॉट डाल F57), Sarvesh Kushare चांदी (उच्च कूद), 100 मीटर T47 में पैरा एथलीटों सोने; TOPS निवेश को दर्शाता है
खेल पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड (Sports ecosystem pyramid)	बेस: Khelo India (grasroot) → Middle: KISCE और SAI केंद्र (elite junior) → Top: TOPS (elite senior Olympic/Paralympic) → Capstone: NSF-organized अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता; संरचित पाइपलाइन बनाया जा रहा है

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- भारत के ओलंपिक ट्रेजेक्टरी: 2000 सिडनी - 1 पदक (कारनम Malleswari कांस्य); 2012 लंदन - 6 पदक; 2020 टोक्यो - 7 पदक (सर्वश्रेष्ठ कभी); 2024 पेरिस - 6 पदक; एक रैखिक सुधार नहीं लेकिन खेलो इंडिया पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है जिसे 2028 LA ओलंपिक में परिणाम दिखाना चाहिए।
- खेलो इंडिया छात्रवृत्ति प्रभाव: 2,000+ एथलीट 5 लाख रुपये / वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं; प्रशिक्षण, उपकरण, आहार, फिजियोथेरेपी को कवर करता है; एथलीट वित्तीय विचलन के बिना ट्रेन कर सकते हैं; प्रारंभिक सबूत छात्रवृत्ति एथलीट राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- नीरज चोपड़ा मॉडल: नीरज के ओलंपिक गोल्ड (टोक्यो 2020) को टॉप्स सपोर्ट (जर्मन कोच क्लॉस बार्टोनीट्ज़ के साथ विदेशी प्रशिक्षण, जर्मन सुविधाओं पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जवेलिन, बायोमैकेनिक्स विश्लेषण) द्वारा सक्षम किया गया था; सरकार नेराज की तैयारी पर 70 लाख रुपये खर्च किए - भारत के पहले एथलेटिक्स ओलंपिक गोल्ड के साथ लौटे
- एन एस एफ शासन सुधार: मंत्रिमंडल की बढ़ी हुई एएनएफएस शासन की स्थिति के साथ आती है - एन एस एफ एस को चुनावी सुधारों, कार्यालय वाहकों के लिए आयु सीमा, विरोधी डोपिंग अनुपालन को लागू करना चाहिए; स्पोर्ट्स कोड 2011 को मजबूत किया जा रहा है; एक आवर्ती यूपीएससी थीम
- पैरा स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन: खेलो इंडिया पैरा गेम्स (2023) भारत का पहला राष्ट्रीय बहु-खेल पैरा गेम्स है; पैरा एथलीट अब TOPS समर्थन के लिए पात्र हैं; ग्लासगो पैरा कॉमनवेल्थ में शारिला का सोना पैरा स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के शुरुआती परिणाम दिखाता है
- CWG 2026 भारोत्तोलन: भारत पारंपरिक रूप से नामित CWG भारोत्तोलन है; Mirabai Chanu भारत के सबसे सजाया भारोत्तोलन (CWG स्वर्ण, ओलंपिक रजत, विश्व चैम्पियनशिप पदक) है; 31 वर्षों में उनकी निरंतर सफलता लंबी अवधि के एथलीट समर्थन को दर्शाती है कि TOPS प्रदान करता है

- इंडिया LA 2028 ambition: भारत का लक्ष्य LA 2028 ओलंपिक में 10+ पदक हैं; एथलेटिक्स (Neeraj + उभरते फेंकने वालों) के लिए यथार्थवादी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन; खेलो इंडिया 2018 स्नातक 2028 में 18-22 होंगे - पाइपलाइन एथलीट

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR (AMENDMENT) BILL 2026

मंत्रालय: गृह मंत्रालय

PIB तिथि: 30 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के लिए अपमान की रोकथाम भारत के कम आरोपित लेकिन संवैधानिक रूप से महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक है। यह अपराध करता है: जलना, उत्परिवर्तन करना, डीफ़ैक्स करना, या अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के सामने असहनीय दिखाई देना; एक अपमानजनक तरीके से राष्ट्रीय एंथेम का उपयोग करना या इसे एक ऐसे तरीके से गाना जो पुनर्व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है; और भारत के संविधान के सामने असहनीय दिखा रहा है। अधिनियम मूल रूप से 1971 में पारित किया गया था ताकि कानून को राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ समेकित किया जा सके - पहले अलग-अलग विधियों में बिखरे हुए। 1971 अधिनियम ने इन अपराधों के लिए 3 साल तक कैद की सजा निर्धारित की। राष्ट्रीय सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपमानित करने की रोकथाम — एक पीआईबी पृष्ठभूमिर ने इस सप्ताह लोकसभा के एक मार्ग के साथ जारी किया - तीन महत्त्वपूर्ण बदलाव करता है: सबसे पहले, यह डिजिटल कार्य को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए 'राष्ट्रीय ध्वज के सामने दृष्टि' की परिभाषा को विस्तार करता है - सोशल मीडिया पर ध्वज की defaced छवियों को पोस्ट करना, डिजिटल सामग्री में परिवर्तित ध्वज इमेजरी का उपयोग करना और हेरफेर ध्वज छवियों को साझा करना। दूसरा, यह दोहराने वाले अपराधियों के लिए 3 साल से 7 साल तक की अधिकतम सजा को बढ़ा देता है या असंतुलन के कृत्यों का आयोजन करता है। तीसरा, यह झंडा और एंथेम अस्सीपटल मामलों के लिए एक तेज-ट्रैक एडज्यूडिक्शन तंत्र बनाता है - समर्पित सत्र अदालतें जो 1 साल के भीतर परीक्षणों को समाप्त करना चाहिए। संशोधन वास्तविकता को दर्शाता है कि अब राष्ट्रीय प्रतीकों के सामने अधिकांश कार्य डिजिटल स्पेस में होते हैं - 1971 अधिनियम को भौतिक विरोध के युग में तैयार किया गया था और इसमें सामाजिक मीडिया-era उल्लंघन की प्रत्याशित नहीं हो सका।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act 1971)	अपराधियों को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय एंथेम और भारत के संविधान से अवगत कराया गया है; अधिकतम सजा 3 साल; 2026 संशोधन दोहराने / व्यवस्थित अपराधियों के लिए 7 साल तक बढ़ जाता है।
राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 (National Flag Code of India 2002)	नेशनल फ्लैग का समुचित उपयोग और प्रदर्शन गवर्न्स; भाग III निजी नागरिकों के लिए नियमों को कवर करता है; फ्लैग कोड को 2022 में हर Ghar Tiranga (मशीन निर्मित झंडे की अनुमति) की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया था।
हर घर तिरंगा (Har Ghar Tiranga)	पीएम मोदी की पहल (अगस्त 2022); स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए हर घर; मशीन-निर्मित और पॉलिएस्टर झंडे की अनुमति देने के लिए ध्वज कोड में संशोधन किया - पहले केवल खादी झंडे की अनुमति दी गई थी।

डिजिटल माध्यम से अपमानजनक कृत्य (Digital acts of disrespect)	2026 संशोधन स्पष्ट रूप से कवर: सोशल मीडिया पर झंडा छवियों का सामना करना पड़ा, डिजिटल सामग्री में झंडा इमेजरी में हेरफेर किया, जो आपत्तिजनक सामग्री के लिए पृष्ठभूमि के रूप में झंडा का उपयोग करता है; 1971 अधिनियम में अंतर को संबोधित करता है
7 साल की सजा (repeat offenders) (7-year punishment (repeat offenders))	संशोधन करार सजा बनाता है: पहला अपराध - 3 साल तक; अपराधी या व्यवस्थित समूह अधिनियम को दोहराएं - 7 साल तक; राष्ट्रीय प्रतीकों को गंभीर अपराध के रूप में इलाज करने के लिए संगठित साजिश
फास्ट-ट्रैक कोर्ट (Fast-track courts)	समर्पित अदालत सत्रों को 1 वर्ष के भीतर ध्वज / एंथेम अस्सीप केस का समापन करना चाहिए; उसी सप्ताह, प्रधानमंत्री ने कागज लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का उपयोग करने का पैटर्न प्रवर्तन उपकरण के रूप में किया।
राजद्रोह कानून और इस अधिनियम में अंतर (Sedition law vs this Act)	Sedition (धारा 124A IPC, अब BNS सेक्शन 152) अलग है - यह सरकार के खिलाफ असंतुलन की उत्तेजना को अपराधी बनाता है; Insults Act की रोकथाम संकीर्ण है - विशेष रूप से राष्ट्रीय प्रतीक; छात्रों को अक्सर दो को भ्रमित करते हैं

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम इस अधिनियम: स्वतंत्रता भाषण (कला 19(1)(a))) एक मौलिक अधिकार है; यह अधिनियम इसे प्रतिबंधित करता है; लेकिन कला 19 (2) सार्वजनिक व्यवस्था, दशमलव और संप्रभुता के हित में मुफ्त भाषण पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है - Insults Act की रोकथाम कला 19 (2) के भीतर गिरती है और अदालतों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है।
- राष्ट्रीय ध्वज कोड संशोधन: फ्लैग कोड 2002 को 2022 (हार्हर तिरंगा) में काफी संशोधन किया गया था; प्रमुख 2022 संशोधन - मशीन निर्मित झंडे की अनुमति, पॉलिएस्टर झंडे की अनुमति, झंडे दिन और रात को प्रदर्शित किया जा सकता है (पहले केवल सूर्यास्त के लिए सूर्योदय); संशोधन विधेयक 2026 फ्लैग कोड के साथ काम करता है
- डिजिटल अधिकार क्षेत्र: सोशल मीडिया कृत्यों को कवर करने के लिए अधिनियम का विस्तार करना जटिल अधिकार क्षेत्र के प्रश्न उठाता है - पाकिस्तान में एक उपयोगकर्ता ने भारतीय ध्वज छवि को स्थगित कर दिया है: क्या भारत मुकदमा कर सकता है? संशोधन अधिनियमों पर केंद्रित है 'भारत में' और भारतीय नागरिकों द्वारा - संकीर्ण क्षेत्राधिकारी क्षेत्र
- संविधान के समावेश: संविधान के प्रति असंतुष्ट (बर्निंग प्रतियां, डिफैक्सिंग प्रीम्बल) को पहले से ही 1971 अधिनियम द्वारा कवर किया गया था; 2026 संशोधन इस को बनाए रखता है और संवैधानिक पाठ के प्रति डिजिटल असाइन्ट को बढ़ाता है - सोशल मीडिया पोस्ट की प्रासंगिक दी गई घटनाओं को चित्रित किया गया था जिसमें चित्रित किया गया था Preamble पृष्ठों
- BNS संदर्भ: भारतीय नायाय संहिता (BNS, 2023) ने IPC को प्रतिस्थापित किया; राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम को अपमान की रोकथाम एक स्टैंडअलोन क़ानूनी क़ानून है, IPC/BNS का हिस्सा नहीं; यह स्वतंत्र रूप से 2026 संशोधन के साथ जारी है।
- राजनीतिक संदर्भ: विधेयक ने लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी लाइनों में व्यापक समर्थन के साथ पारित किया (डिजिटल भाषण स्वतंत्रता पर बहस के बावजूद); विरोध ने राजनीतिक विरोधों के खिलाफ संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की जिसमें ध्वज प्रतीकवाद शामिल था - एक वैध नागरिक स्वतंत्रता बहस

KALPASAR PROJECT — GUJARAT'S ESTUARY DAM, TIDAL POWER, AND FRESHWATER RESERVOIR

मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय

PIB तिथि: 27 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

The Gulf of Khambhat (Cambay) दुनिया के सबसे असामान्य निकायों में से एक है। यह गुजरात के तट पर एक फ़नल के आकार का इनलेट है जहां ज्वारीय रेंज - उच्च ज्वार और कम ज्वार के बीच का अंतर - दुनिया के उच्चतम स्तर पर है, 12 मीटर तक पहुंच रहा है। यह असाधारण ज्वारीय ऊर्जा, जो ताजे पानी की नदियों (सबर्माती, मही, नर्मदा, भरूच) के साथ संयुक्त है जो खाड़ी में बहती है, ने भारतीय इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक को प्रेरित किया है: कलापासर परियोजना। कलपासर ने खंभात की खाड़ी के मुंह में 30 किमी की बांध बनाने का प्रस्ताव रखा, जो उत्तरी हिस्से को बनाने के लिए बंद कर दिया गया: (1) लगभग 10,000 मिलियन घन मीटर का एक ताजा जल जलाशय - दुनिया के सबसे बड़े कृत्रिम मीठे पानी के निकायों में से एक, दशकों तक सूखे-प्रवण गुजरात की जल कमी को हल करना; (2) 12 मीटर ज्वारीय रेंज का उपयोग करते हुए ज्वारीय विद्युत उत्पादन - बांध में टरबाइनों के माध्यम से ज्वार प्रवाह के रूप में उत्पन्न ऊर्जा - संभवतः 5,880 मेगावाट स्वच्छ, पूर्वानुमान योग्य (टाइडल ऊर्जा सौर या पवन की तुलना में अधिक अनुमानित है) ऊर्जा; (3) सौराष्ट्र प्रायद्वीप को जोड़ने वाली बांध में एक बहु लेन सड़क/रेल लिंक (वर्तमान में केवल खाड़ी के आसपास एक लंबे समय तक पहुंच गया) दक्षिण गुजरात और मुंबई तक - 200+ किमी तक की दूरी को कम करना। इस सप्ताह संसदीय प्रश्नों ने परियोजना की स्थिति को दर्शाया: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो गई है; परियोजना 70,000+ करोड़ रुपये (मूल 1995 का अनुमान 7,000 करोड़ रुपये था) के संशोधित लागत अनुमान के साथ कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है; और गुजरात सरकार ने औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्र से संपर्क किया है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
कलपासर परियोजना (Kalpasar Project)	खंभात की खाड़ी में 30 किमी बांध (कैम्बा); ताजे पानी के जलाशय (10,000 एमसीएम), ज्वारीय शक्ति (5,880 मेगावाट), सड़क-रेल लिंक बनाता है; लागत 70,000 + करोड़ रुपये; मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार करना
खंभात की खाड़ी (Gulf of Khambhat)	फ़नल के आकार का तटीय इनलेट, गुजरात; ज्वारीय रेंज 12 मीटर (दुनिया की सबसे ऊंची); नर्मदा, मही, सबरमती नदियों ने इसमें नाली; वर्तमान में एक सैलाइन estuary; परियोजना उत्तरी हिस्से को मीठे पानी में बदल देती है
ज्वारीय ऊर्जा (Tidal energy)	ज्वारीय प्रवाह से उत्पन्न बिजली; पूर्वानुमान योग्य (टाइडल चक्र चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं) सौर / पवन के विपरीत; कलपासर दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय शक्ति परियोजना होगा यदि बनाया गया हो; वर्तमान दुनिया का सबसे बड़ा: सिवा झील (दक्षिण कोरिया, 254 मेगावाट)
ज्वारनदमुख बाँध (Estuary dam)	बांध एक estuary भर में बनाया गया (जहां नदी समुद्र से मिलती है); सैलिन estuary को ताजे पानी के जलाशय में परिवर्तित करता है; फ्रांस का रेंस ज्वारीय पावर स्टेशन (1966, 240 मेगावाट) दुनिया का सबसे प्रसिद्ध estuary बांध है; Kalpasar 24x बड़ा होगा

10,000 MCM जलाशय (10,000 MCM reservoir)	ताजे पानी के भंडारण के 10,000 मिलियन क्यूबिक मीटर; गुजरात के सरदार सरोवर डैम स्टोर 9,500 एमसीएम; कलपासर गुजरात का सबसे बड़ा जल भंडारण होगा - सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में पुरानी पानी की कमी को हल करना
सौराष्ट्र कनेक्टिविटी (Saurashtra connectivity)	वर्तमान में, सौराष्ट्र प्रायद्वीप खाड़ी (अहमदाबाद-राजकोट-सौराष्ट्र: 230 किमी) के आसपास एक लंबे सड़क मार्ग से पहुँचा है; कालपासर बांध सड़क/रेल लिंक इसे 30 किमी तक घटा देंगे - परिवर्तनकारी रसद सुधार
पर्यावरणीय चिंताओं (Environmental concerns)	कलपासर बांध फँसाना होगा (गल्फ ने नर्मदा, साबरमती से भारी तलछट का भार रखता है); मछली प्रवासन पैटर्न को बाधित करता है; flamingo आवास (खामहाट की खाड़ी 1+ मिलियन flamingos होस्ट करती है); ईआईए ने महत्त्वपूर्ण चिंताओं को उठाया है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इतिहास: Kalpasar अवधारणा 1976 की तारीख; पहला DPR 1995; एकाधिक संशोधन; 2024 DPR पूरा होने नवीनतम मील का पत्थर चिह्नित करता है; अवधारणा से लेकर निकट-सरकारी तक 50 साल की यात्रा परियोजना के पैमाने और जटिलता को दर्शाती है।
- ज्वारीय ऊर्जा महत्व: ज्वारीय ऊर्जा एकमात्र अक्षय है जो पूरी तरह से पूर्वानुमानित है; ज्वार शून्य परिवर्तन के साथ चंद्र चक्र का पालन करते हैं; सौर (बंद दिनों) या हवा (कैल्म अवधि) के विपरीत, ज्वारीय शक्ति को थर्मल प्लांट की तरह निर्धारित किया जा सकता है - इससे ग्रिड स्थिरता के लिए अद्वितीय रूप से मूल्यवान हो जाता है।
- फ्लेमिंगो आवास: खंभात की खाड़ी भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण फ्लेमिंगो आवासों में से एक है (Lesser Flamingo, ग्रेटर फ्लेमिंगो); 5-15 लाख flamingos मौसम में मिट्टी के फ्लैट का उपयोग करते हैं; बांध महत्त्वपूर्ण निवास स्थान को नष्ट कर देगा; भारत के वन्यजीव संस्थान ने चिंताओं को बढ़ा दिया है; ईआईए को कैबिनेट क्लीयरेंस से पहले इसे संबोधित करना चाहिए।
- तलछट: नदियों खाड़ी में तलछट लाने के लिए; बंद खाड़ी इस तलछट को फँसाना होगा, संभावित रूप से 50-100 वर्षों के भीतर ताजे पानी के जलाशय को सिलेटेगा; इसी तरह की समस्याओं से मिस्र के आसवान हाई डैम (Nile डेल्टा अब लुप्त हो गया है क्योंकि बांध फँसा हुआ है); कालपासर के डिजाइन को इस तरह से संबोधित करना चाहिए
- रोड-रेल लिंक अर्थशास्त्र: वर्तमान में, भावनगर से मुंबई तक एक ट्रक अहमदाबाद के माध्यम से 650+ किमी की यात्रा करता है; कलपासार बांध सड़क के माध्यम से, यह 450 किमी - 200 किमी की बचत होगी; सौराष्ट्र (हजीरा, पिपावव, मुंद्रा बंदरगाह) में प्रमुख बंदरगाह-औद्योगिक गतिविधि वाले राज्य के लिए, यह एक बहु-तिहाई वार्षिक रसद बचत है।
- विश्व तुलना: फ्रांस की रेंस बांध (1966) सफलतापूर्वक 60 वर्षों तक काम कर रहा है; दक्षिण कोरिया का सिवा झील (254 मेगावाट, 2011) दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग ज्वारीय पौधा है; नीदरलैंड का पूर्वी शेल्ड (टाइडल पावर घटक के साथ तूफानी वृद्धि बाधा); कलासार किसी भी मौजूदा ज्वारीय परियोजना की तुलना में 20x बड़ा होगा - ऐतिहासिक अनुपात की इंजीनियरिंग चुनौती
- जल सुरक्षा आयाम: गुजरात जल-स्कार है - सौराष्ट्रन जिलों में वर्षा परिवर्तनशीलता होती है जो पुराने सूखे का कारण बनती है; 10,000 एमसीएम मीठे पानी का जलाशय 100+ वर्षों तक गुजरात जल सुरक्षा प्रदान करेगा; यह पर्यावरण चिंताओं के बावजूद परियोजना के लिए प्राथमिक ड्राइवर है।

GREEN HYDROGEN MISSION — 12 PILOT PROJECTS, 70 HYDROGEN VEHICLES ACROSS 21 ROUTES

मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

PIB तिथि: 29 जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (जनवरी 2023, 19744 करोड़ रुपये) एक व्यापक महत्वाकांक्षा है: 2030 तक हरित हाइड्रोजन के 5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) का उत्पादन करता है, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों और निर्यातकों में से एक बन जाता है। लेकिन प्रारंभिक प्रूफ-ऑफ-कंसेप्ट प्रोजेक्ट जोखिम के बिना एक मिशन भौतिक वास्तविकता के बिना एक नीति दस्तावेज बन गया है। इस सप्ताह, MNRE ने विशेष रूप से 21 मार्गों में 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों को तैनात करने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं का शुभारंभ किया - भारत में हाइड्रोजन गतिशीलता का पहला बड़ा पैमाने पर प्रदर्शन। 70 वाहन तीन श्रेणियों में फैले हैं: हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (H2 FCEVs - कारों और प्रकाश वाणिज्यिक वाहन जहां हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति देता है); हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन (HICE) वाहन (ट्रक और बस जहां हाइड्रोजन सीधे डीजल की तरह जलाया जाता है) लेकिन शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ); और चुनिंदा शहरी मार्गों में हाइड्रोजन संचालित तीन पहिया। 21 मार्ग 12 राज्यों में फैले - पुणे-मुंबई (महाराष्ट्र, राजमार्ग पर एच 2 बसों का परीक्षण), दिल्ली-गुरुग्राम-नोडा (एनसीआर, एच 2 यात्री कारों का परीक्षण), और कोच्चि-थारुवनंतपुरम (केराला, एच 2 तीन पहिया वाहनों का परीक्षण) सहित। पायलट का उद्देश्य: हाइड्रोजन वाहन प्रदर्शन, हाइड्रोजन स्टेशन अर्थशास्त्र और सार्वजनिक स्वीकृति पर वास्तविक दुनिया के डेटा उत्पन्न करना - राष्ट्रीय हाइड्रोजन गतिशीलता नीति को डिजाइन करने के लिए आवश्यक डेटा। भारत के हाइड्रोजन ट्रेन पायलट (Week 7 संक्षिप्त) और ये 70 सड़क वाहन एक साथ संकेत देते हैं कि हाइड्रोजन गतिशीलता प्रयोगशाला से सड़कों तक चल रही है।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission)	Rs 19,744 करोड़; जनवरी 2023 शुरू; लक्ष्य 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक; उत्पादन प्रोत्साहन (Sight scheme), पायलट परियोजनाओं, निर्यात अवसंरचना, प्रौद्योगिकी विकास को शामिल करता है।
हरित हाइड्रोजन संक्रमण हेतु रणनीतिक हस्तक्षेप योजना (SIGHT scheme)	ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण के लिए सामरिक हस्तक्षेप; दो घटक: इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण प्रोत्साहन + ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रोत्साहन; एनजीएचएम का मुख्य वित्तीय साधन
हाइड्रोजन ईंधन-सेल विद्युत वाहन (H2 FCEV)	हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन; टैंक में संग्रहीत हाइड्रोजन, ईंधन सेल के माध्यम से बिजली में परिवर्तित हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर चला गया; शून्य उत्सर्जन (केवल पानी वाष्प); टोयोटा मिराई, हुंडई नेक्सो वाणिज्यिक उदाहरण हैं; टाटा मोटर्स भारतीय एफसीईवी विकसित करते हैं
हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन वाहन (Hydrogen ICE—HICE)	हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन; एक पेट्रोल / डीजल इंजन की तरह हाइड्रोजन को जला देता है; ईंधन सेल की तुलना में सरल तकनीक; कुछ CO2 यदि ट्रेस हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं; FCEV से सस्ता; बसों, ट्रकों के लिए उपयुक्त;

ग्रीन हाइड्रोजन (Green hydrogen)	हाइड्रोजन अक्षय बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित; शून्य कार्बन; वर्तमान लागत 350-500/किलोग्राम (2030) तक 150/किलोग्राम; 'ग्रे' हाइड्रोजन (CO2 उत्सर्जन के साथ प्राकृतिक गैस से) वर्तमान प्रमुख उत्पादन विधि है।
विद्युत-अपघटक (Electrolyser)	डिवाइस जो पानी को हाइड्रोजन में विभाजित करता है और बिजली का उपयोग करके ऑक्सीजन को विभाजित करता है; ग्रीन हाइड्रोजन को अक्षय बिजली द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर्स की आवश्यकता होती है; भारत Sight योजना के तहत घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण का निर्माण करता है।
21 मार्गों का चयन मानदंड (21 routes selection criteria)	विभिन्न स्थितियों का परीक्षण करने के लिए चुने गए रूट: राजमार्ग (प्यून-मुंबई), शहरी (दिल्ली एनसीआर), पहाड़ी (शिमला), तटीय (कोच्चि); लद्दाख से केरल तक तापमान चरम सीमा भारत के विविध जलवायु पर मजबूती परीक्षण सुनिश्चित करती है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- 5 एमएमटी लक्ष्य संदर्भ: भारत वर्तमान में 'ग्रे' हाइड्रोजन (प्राकृतिक गैस से) के 6 एमएमटी का उत्पादन करता है; 2030 तक 5 एमएमटी अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन भारत की हाइड्रोजन क्षमता को दोगुना करेगा लेकिन पूरी तरह से नई क्षमता के कार्बन पदचिह्न को खत्म करेगा; कुल हरा + ग्रे 11 एमएमटी होगा।
- परिप्रेक्ष्य में 70 वाहन: टोयोटा ने दुनिया भर में 20,000 Mirais (FCEV) बेचा है; चीन में 10,000+ हाइड्रोजन बस हैं; भारत का 70 वाहन बहुत छोटा पायलट है; मूल्य डेटा जनरेशन और आपूर्ति श्रृंखला परीक्षण में है, पैमाने पर नहीं
- हाइड्रोजन स्टेशन अवसंरचना: प्रत्येक पायलट मार्ग को हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की आवश्यकता होती है; 21 मार्ग = 21 पायलट स्टेशन; स्टेशनों की लागत प्रत्येक में 15-20 करोड़ रुपये है; स्टेशन अर्थशास्त्र पर परिचालन डेटा (थ्रूपुट, रखरखाव, सुरक्षा) स्केल-अप से पहले आवश्यक है।
- भारत का ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात महत्वाकांक्षा: एनजीएचएम लक्ष्य जापान के लिए एक प्रमुख ग्रीन हाइड्रोजन निर्यातक बन गया है (जो 2030), दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ द्वारा 3 एमएमटी हाइड्रोजन आयात करने के लिए प्रतिबद्ध है; भारत का प्रतिस्पर्धी लाभ प्रचुर मात्रा में सस्ते सौर / पवन है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए; 70-वाहन पायलट प्रौद्योगिकी में घरेलू विश्वास का निर्माण करता है
- हाइड्रोजन ट्रेन + सड़क वाहन: RDSO की हाइड्रोजन ईंधन सेल ट्रेन (Week 7) + MNRE की 70 हाइड्रोजन सड़क वाहन = भारत सभी परिवहन मोडों में एक साथ हाइड्रोजन गतिशीलता का परीक्षण; रेल (1,000 किमी रेंज), सड़क (300-500 किमी रेंज), संभावित शिपिंग (पोर्ट उपकरण) - व्यापक पायलट रणनीति
- Sight योजना की स्थिति: इलेक्ट्रोलाइट्सर विनिर्माण प्रोत्साहन की पहली खाई को नष्ट कर दिया गया है; भारतीय कंपनियां (एनटीपीसी, एसीएमई, ग्रीनको, रीन्यू) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का निर्माण कर रही हैं; 70-वाहन पायलट Sight की आपूर्ति-साइड पुश करने के लिए मांग-साइड समकक्ष है।
- कॉस्ट ट्रेजेक्टरी: ग्रीन हाइड्रोजन 350-500/kg; डीजल बराबर लागत ~ Rs 180/kg; ग्रीन हाइड्रोजन 2-3x अधिक महंगा है; 150/kg (2030 लक्ष्य) पर, यह डीजल के साथ प्रतिस्पर्धी हो जाता है; पायलट मार्गों का परीक्षण है कि क्या हाइड्रोजन वाहन की ईंधन दक्षता उच्च ईंधन लागत को ऑफसेट करती है।

VIKSIT VIBRANT VILLAGE PROGRAMME 2026 — BORDER VILLAGE DEVELOPMENT

मंत्रालय: गृह मंत्रालय / ग्रामीण विकास मंत्रालय

PIB तिथि: 25th-26th जुलाई 2026

सरल व्याख्या

भारत का सीमा गाँव - चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के 50 किमी के भीतर - ऐतिहासिक रूप से भारत की विकास योजना में सबसे अधिक उपेक्षा में से एक रहा है। पैराडोक्स: ये गांव भारत की संप्रभुता की रणनीतिक फ्रंटलाइन पर हैं, फिर भी दशकों तक उन्हें सुरक्षा क्षेत्र के रूप में इलाज किया गया जहां आर्थिक विकास सीमित था, बुनियादी ढांचा कम था और जनसंख्या कम हो गई थी क्योंकि युवा लोग शहरों में चले गए थे। सीमावर्ती गांवों की आबादी ने एक डबल समस्या बनाई: रणनीतिक - चीन सीमा के पास छोड़े गए गांवों ने सुरक्षा voids का निर्माण किया है कि पीएलए (People's Liberation Army) ने बुनियादी ढांचे और दावा क्षेत्र के निर्माण का फायदा उठाया है (Galwan सीमा क्षेत्र की उपेक्षा सुरक्षा संकट कैसे बन जाती है); आर्थिक - ये समुदाय चरम मौसम के साथ कठिन इलाके में रहते हैं लेकिन अपर्याप्त समर्थन प्राप्त करते हैं। विब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) को 2023 में विशेष रूप से भारत की उत्तरी सीमा (चीन - अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख) पर गांवों के लिए लॉन्च किया गया था। विकसित जीवंत ग्राम प्रोग्राम 2026 भारत की पूरी सीमा परिधि को कवर करने वाला विस्तार, अधिक व्यापक संस्करण है और इसे 19 जिलों से 46 जिलों तक बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने इस सप्ताह विजय वीवीपी प्रतिभागियों के साथ सीधे बातचीत की - आदिवासी प्रतिनिधि, स्थानीय नेता और सीमावर्ती गांवों के युवा लोग। कार्यक्रम प्रदान करता है: 100% सड़क कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट, सौर प्रकाश, आजीविका केंद्र, स्वास्थ्य देखभाल उप-केंद्र, और विशेष रूप से - पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत पदोन्नति सामरिक देयताओं के बजाय सीमा गांवों को आर्थिक रूप से जीवंत गंतव्य बनाने के लिए।

महत्त्वपूर्ण शब्दावली:

शब्द	परिभाषा
विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम (Viksit Vibrant Village Programme—Viksit VVP)	विब्रेंट गांव कार्यक्रम का विस्तार 2026 संस्करण; 46 सीमा जिलों (19 तक) को कवर करता है; सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ; सीमा गांवों के लिए बुनियादी ढांचा, आजीविका और सांस्कृतिक/पर्यटन पदोन्नति प्रदान करता है।
जीवंत ग्राम कार्यक्रम, 2023 (Vibrant Villages Programme—VVP)	मूल कार्यक्रम; चीन सीमा (अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखण्ड, एचपी, लद्दाख); 19 जिलों; 2,967 गांवों; 4,800 करोड़ रुपये परिव्यय; 2023-2026; Viksit VVP उत्तराधिकारी है।
सीमावर्ती गाँवों से जनसंख्या का पलायन (Border villages depopulation)	चीन सीमा गाँव: 2001-2021 में 20-40% आबादी में गिरावट आई; युवा लोग शहरों में चले गए; परित्यक्त गाँव सुरक्षा अंतराल बनाते हैं; गैलवान संदर्भ - पीएलए ने विवादित क्षेत्रों में सड़कों और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया क्योंकि भारतीय सीमा क्षेत्र कम विकसित हुए थे।
सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation—BRO)	सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और रखरखाव; रक्षा मंत्रालय के तहत; विक्रय VVP का सड़क कनेक्टिविटी घटक BRO द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; BRO ने सालाना सीमावर्ती क्षेत्रों में 3,000+ किमी सड़कें बनाई हैं।

सामरिक महत्व (Strategic importance)	चीन का 'मॉडल गाँव' (ज़ियाओकांग गाँव) अरुणाचल प्रदेश के विपरीत विवादित क्षेत्र में निर्माण भारत का जागरण कॉल था; भारत की प्रतिक्रिया: चीनी निर्मित गाँवों के विकल्प के रूप में भारतीय सीमा गाँव विकसित करना - नागरिक अवसंरचना संप्रभुता के रूप में
सीमा पर्यटन (Border tourism)	विकीट VVP में सीमावर्ती गांवों में विरासत चलना, होमस्टे, सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल हैं; लद्दाखी संस्कृति, अरुणाचल जनजाति परंपराओं, सिक्किम बौद्ध मठ - घरेलू पर्यटकों के लिए सुलभ बना; आय लाता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी बनाए रखता है।
ऑप्टिकल फाइबर + सौर (Optical fibre + solar)	हर VVP गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट और सौर प्रकाश व्यवस्था होती है; डिजिटल कनेक्टिविटी ई-कॉमर्स, टेली-एडुकेशन और टेलीमेडिसिन को सक्षम करती है - शहरों में प्रवास के बिना आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहार्य सीमा गांव का जीवन बनाती है।

UPSC के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- चीन के Xiaokang गाँव: चीन ने तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में भारतीय सीमा के पास 600+ 'ज़ियाओकांग' (मध्यम समृद्ध) गांवों का निर्माण किया है; आधुनिक आवास, सड़कों, स्वास्थ्य देखभाल, इंटरनेट; कुछ क्षेत्रों में भारत का दावा; भारत का VVP सीधे चीन की रणनीति से प्रेरित है - भारतीय विकास के साथ मुकाबला
- गैलवान संदर्भ: जून 2020 गैलवान घाटी संघर्ष ने खुलासा किया कि लद्दाख में भारतीय अंडर-डेवलपमेंट के दशकों ने चीनी बुनियादी ढांचे को अनोटिक करने की अनुमति दी थी; विकीट वीवीपी विशेष रूप से लद्दाख को लक्षित करता है - लद्दाख में 663 सीमा गांव विकसित किए जा रहे हैं।
- 46 जिलों बनाम 19: विस्तार से 19 से 46 जिलों का मतलब है विक्सिट VVP अब भारत की सीमाओं को सभी 7 भूमि पड़ोसियों के साथ कवर करता है - चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहां तक कि श्रीलंका और मालदीव का सामना करने वाले तटीय सीमा जिले (समय पर आयाम)
- पर्यटन विकास उपकरण के रूप में: Spiti (HP), तावांग (अरुणाचल), Gurez घाटी (J&K), मन (उत्तराखंड - तिब्बत सीमा से पहले पिछले भारतीय गांव) पर्यटन स्थलों बन रहे हैं; इन गांवों का दौरा करने वाले पर्यटक स्थानीय रूप से पैसे खर्च करते हैं, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय रूप से पैसे खर्च करने का आर्थिक कारण बनता है।
- पीएम की प्रत्यक्ष बातचीत: पीएम मोदी की वीवीपी प्रतिभागियों (जुलाई 26) के साथ बातचीत राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुई थी - राजनीतिक संकेत कि सीमा गाँव प्राथमिकता है, फिर भी नहीं; सीमावर्ती समुदाय के सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री सगाई में सुरक्षा आयाम भी है - जमीन की स्थिति के बारे में खुफिया
- BRO प्रदर्शन: BRO 2019 से अभूतपूर्व गति पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कर रहा है; 2021 में सड़क द्वारा Umlingla Pass (world's high motorable road, 19,024 ft, Ladakh) से जुड़ा हुआ है; सीमा क्षेत्रों में 100+ सुरंगों और पुलों का निर्माण; Viksit VVP की सड़क कनेक्टिविटी इस BRO त्वरण पर निर्भर करती है।
- PMGSY + VVP अभिसरण: प्रधान मंत्री ग्राम सद्दाक योजना (ग्रामीण सड़कों) और BRO सीमा सड़कें एक साथ VVP कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं; सर्दियों में अब एक सीमा गांव में सभी मौसमी कनेक्टिविटी 2027 तक अभिसरण PMGSY-BRO योजना के तहत होना चाहिए

अभ्यास प्रश्न

10 प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न—UPSC प्रारूप

Q1. 'सारनाथ के क्षणिक बौद्ध स्थल', इस सप्ताह भारत के 43 वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्णित, निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए महत्त्वपूर्ण है?

1. यह वह स्थल है जहां बुद्ध ने बोधिवृक्ष के तहत प्रबुद्धि प्राप्त की।

2. यह अशोका की मूल शेर राजधानी है जिसका डिजाइन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बनाती है।

3. द हमेक स्तुपा ने बुद्ध के पहले उपदेश (धामाकप्पावताना सुत्त) का स्थान चिह्नित किया है।

4. यह चार प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, अन्य लोग लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर हैं।

उपरोक्त में से कौन-सा सही है?

(a) केवल 2, 3, 4

(b) केवल 1, 2, 3

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q2. समुद्रा मंथन (राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना) के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

1. भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का 2.02 मिलियन वर्ग किमी है, लेकिन इसकी अपतटीय अवसादी बेसिनों का केवल 10% ही पता लगाया गया है।

2. इस योजना में भूकंपीय सर्वेक्षणों, एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग और डेटा अधिग्रहण के लिए 10 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपये की देरी है।

3. भारत के ईईजेड में मीथेन हाइड्रेट को दुनिया के पारंपरिक गैस भंडार में कई बार शामिल होने का अनुमान है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

4. यह योजना विशेष रूप से मुंबई हाई और KG-D6 बेसिनों पर केंद्रित है जहां उत्पादन वर्तमान में उच्चतम है।

कितने सही हैं?

(a) केवल दो

(b) केवल तीन

(c) सभी चारो

(d) केवल एक

Q3. इस सप्ताह संसद में चर्चा करने वाले कलपासर परियोजना की योजना बनाई गई है:

(a) भारत और श्रीलंका के बीच मांर की खाड़ी, ज्वारीय शक्ति और मीठे पानी के जलाशय के लिए

(b) गुजरात में खंभात की खाड़ी, ताजे पानी के भंडारण, ज्वारीय शक्ति और सड़क-रेल कनेक्टिविटी के लिए

(c) तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक स्थायी सड़क-रेल पुल के लिए Palk Strait

(d) ओडिशा में चिलिका झील, ताजे पानी संरक्षण और जलीय कृषि विकास के लिए

Q4. सार्वजनिक परीक्षा (Unfair Means) संशोधन विधेयक, 2026 निम्नलिखित में से कौन-सा परिवर्तन 2024 अधिनियम में करता है?

1. सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल करने के लिए कवरेज को बढ़ाता है, न केवल केंद्रीय परीक्षाओं।

2. स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय परीक्षा की अखंडता के प्रति असहमति के डिजिटल कृत्यों को आपराधिक बनाती है।

3. एक स्थायी निरीक्षण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता बोर्ड (NEIB) बनाता है।

4. प्रतिरूपण (किसी और के नाम में प्रकट) बनाता है एक विशेष रूप से दंडनीय अलग अपराध।

उपरोक्त में से कौन-सा सही है?

(a) केवल 1, 3 और 4

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2, 3 और 4

(d) केवल 1 और 4

Q5. PM Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) के बारे में निम्नलिखित विचार करें:

1. यह केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के स्वामित्व वाले जलाशयों की जल सतहों पर फ्लोटिंग सौर पैनलों को तैनात करता है।

2. प्रत्येक परियोजना 24 घंटे की बिजली आपूर्ति के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएस) के साथ फ्लोटिंग सौर को जोड़ती है।

3. फ्लोटिंग सोलर पैनल 10-15% तक जल वाष्पीकरण को कम करते हैं, जिससे ऊर्जा और जल संरक्षण का दोहरे लाभ मिलता है।

4. इस योजना में 84,084 करोड़ रुपये की देरी है - समुद्र मंथन अपतटीय अन्वेषण योजना के समान।

कौन सही है?

(a) केवल 1, 2, 3

(b) केवल 2, 3, 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q6. सोवा-रिग्पा, जो इस सप्ताह पीआईबी में आए थे, को सबसे अच्छा बताया गया है:

(a) अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती बौद्ध समुदायों द्वारा आयोजित एक पारंपरिक कपड़ा बुनाई तकनीक

(b) तिब्बती, हिमालयी और मंगोलियाई संस्कृतियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली; AYUSH के तहत भारत की 5 वीं पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त

(c) उत्तर-पूर्व भारत के छठे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रयुक्त सामुदायिक आधारित जैव विविधता प्रलेखन अभ्यास

(d) उच्च ऊंचाई सिंचाई के लिए लद्दाखी किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली

Q7. इस सप्ताह एनआईसी द्वारा लॉन्च किया गया LGRAA एक एआई उपकरण है जो:

(a) ईकोर्ट्स में मामलों की स्वचालित फाइलिंग प्रदान करता है और यात्रियों के लिए मामले की प्रगति को ट्रैक करता है

(b) असिस्ट न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को कानूनी अनुसंधान में असिस्ट करता है, जो प्राकृतिक भाषा प्रश्नों के माध्यम से एससी/एचसी निर्णयों से प्रासंगिक पूर्वाग्रहों का संश्लेषण करता है।

(c) सरकारी विभागों द्वारा अदालत के आदेशों के अनुपालन की निगरानी करता है और स्वचालित अवमान नोटिस उत्पन्न करता है

(d) उच्च न्यायालयों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी तक वास्तविक समय में अदालत की कार्यवाही का अनुवाद करता है

Q8. BMIP (भारत समुद्री बीमा पूल) के तहत भारत का पहला घरेलू संरक्षण और क्षतिपूर्ति (P&I) बीमा उत्पाद शुरू किया गया था:

1. वैश्विक समुद्री बीमा पर हावी होने वाले 13 अंतर्राष्ट्रीय समूह पी एंड आई क्लबों का विकल्प प्रदान करें।

2. सुनिश्चित करें कि भारतीय शिपिंग पश्चिमी बीमा इनकार के भू-राजनीतिक जोखिमों के अधीन नहीं है (जैसा कि रूस मंजूरी 2022) के दौरान देखा गया है।

3. कई भारतीय बीमाकर्ताओं में पूल जोखिम बड़े समुद्री दायित्व को कवर करने के लिए दावा करता है कि कोई भी बीमाकर्ता संभाल सकता है।

4. सभी मौजूदा कार्गो और पतवार बीमा को भारतीय-चमकदार जहाजों के लिए बदलें।

कौन सही है?

(a) केवल 1, 2, 3

(b) केवल 2, 3, 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

Q9. विकसित जीवंत ग्राम प्रोग्राम 2026 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से मूल विब्रेंट विलेज प्रोग्राम (2023) से सही ढंग से अलग है?

(a) Viksit VVP केवल चीन सीमा को कवर करता है जबकि VVP 2023 ने सभी सीमाओं को कवर किया

(b) विक्सिट VVP केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है जबकि VVP 2023 में रक्षा किलेबंदी भी शामिल है।

(c) Viksit VVP को 19 से 46 सीमा जिलों तक विस्तारित किया गया है और भारत की पूरी सीमा परिधि को कवर करता है, न केवल उत्तरी सीमा

(d) विकिसिट VVP एक राज्य सरकार का कार्यक्रम है जबकि VVP 2023 एक केंद्रीय प्रायोजित योजना थी।

Q10. हाइड्रोजन वाहनों के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की 12 पायलट परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित विचार करें:

1. पायलट ने 12 राज्यों में 21 मार्गों में 70 हाइड्रोजन संचालित वाहनों को तैनात किया।

2. वाहनों में हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (H2 FCEVs), हाइड्रोजन ICE वाहन और हाइड्रोजन तीन पहिया वाहन शामिल हैं।

3. पायलट विशेष रूप से शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजमार्ग मार्गों को बाहर करते हैं।

4. मिशन लक्ष्य वार्षिक रूप से 2030 तक 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं।

कौन सही है?

(a) केवल 1, 2, 4

(b) केवल 2, 3, 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

आदर्श उत्तरों सहित 2 मुख्य परीक्षा प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न 1—150 शब्द:

समुद्रा मंथा, PM सूर्या सरोवर योजना, REPM योजना, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के वाहन पायलटों ने सभी एक ही सप्ताह में दिखाई दिए। एक आलोचक का तर्क है कि वे भारत की ऊर्जा नीति में विरोधाभासी आवेगों का प्रतिनिधित्व करते हैं - साथ ही जीवाश्म ईंधन विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का पीछा करते हुए। क्या आप सहमत हैं? इस सप्ताह भारत की ऊर्जा रणनीति का विश्लेषण एक सुसंगत संपूर्ण के रूप में किया जाता है।

आदर्श उत्तर—150 शब्द:

जब भारत के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे के माध्यम से शुद्ध पर्यावरण लेंस के बजाय भारत के ऊर्जा सुरक्षा ढांचे के माध्यम से देखा जाता है तो स्पष्ट विरोधाभास भंग हो जाता है। भारत अपने तेल का 87% आयात करता है ($100+ बिलियन/वर्ष) - ऊर्जा गरीबी वर्तमान संकट है, भविष्य में जोखिम नहीं है। समुद्र मंथन की अपतटीय अन्वेषण इस आयात निर्भरता को 10-15 साल के क्षितिज के भीतर कम कर देता है। यह क्षितिज ठीक उसी समय होता है जब भारत के स्वच्छ ऊर्जा स्टैक (पीएम-एसएसवाई फ्लोटिंग सोलर + बीईएस, ग्रीन हाइड्रोजन वाहन, 99.6%) में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जीवाश्म ईंधन की मांग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाएगा। अनुक्रमण को जानबूझकर माना जाता है: घरेलू जीवाश्म ईंधन (Samudra Manthan) के साथ आयात अंतर को पुल करें जबकि स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना (PM-SSY, REPM for EV मोटर्स, हाइड्रोजन पायलट) का निर्माण किया जाता है जो संक्रमण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है। REPM योजना ईवी विनिर्माण के लिए दुर्लभ पृथ्वी सुरक्षा को जोड़ता है - यह सुनिश्चित करता है कि जब ईवी स्केल भारत घरेलू रूप से चुंबक आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट 2030+ के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति को डिजाइन करने के लिए आवश्यक वास्तविक दुनिया के डेटा को उत्पन्न करते हैं। विरोधाभासी से दूर, ये चार पहल एक अनुक्रमिक ऊर्जा संप्रभुता रणनीति बनाती हैं: अल्पकालिक (घरेलू जीवाश्म), मध्यम अवधि (विद्युतीकरण और भंडारण), दीर्घकालिक (हाइड्रोजन) - साफ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए REPM के साथ घरेलू रूप से नियंत्रित किया जाता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न 2—250 शब्द:

'भारत के सीमा विकास और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अलग नीति डोमेन नहीं हैं - वे एक ही राष्ट्रीय सुरक्षा सिक्का के दो पक्ष हैं।' Viksit Vibrant गांव कार्यक्रम और Sarnath UNESCO शिलालेख का उपयोग करके अपने प्राथमिक उदाहरणों के रूप में, और इस सप्ताह के पीआईबी से किसी अन्य प्रासंगिक विकास पर ड्राइंग, इस दावे की आलोचनात्मक रूप से जांच करते हैं।

आदर्श उत्तर—250 शब्द:

यह दावा एक मूलभूत रणनीतिक अंतर्दृष्टि को कैप्चर करता है: क्षेत्रीय संप्रभुता सिर्फ सैन्य उपस्थिति से ही नहीं बल्कि नागरिक जीवन शक्ति और सांस्कृतिक निरंतरता से बनी रहती है। जब सीमा गाँवों को निर्विवादित किया जाता है और क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक संबंध गंभीर हो जाते हैं, तो क्षेत्रीय दावे कानूनी रूप से और जनसांख्यिक रूप से कमजोर होते हैं। विक्सित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य चीन के 'ज़ियाओकांग गांव' का मुकाबला करना है - चीन ने तिब्बती क्षेत्र में 600+ आधुनिक गांवों का निर्माण किया है, कुछ क्षेत्रों में भारत विवाद, ठीक से जमीन और नागरिक उपस्थिति पर भौतिक तथ्यों को बनाने के लिए जो चीनी दावों को मान्य करते हैं। 19 से 46 जिलों तक भारत का VVP विस्तार उसी तर्क के साथ जवाब देता है: 500 निवासियों, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, एक Khelo इंडिया सेंटर, और एक पर्यटन गृहस्था अकेले एक सैन्य पोस्ट की तुलना में एक बहुत मजबूत संप्रभुता दावेदार है। जब युवा लोग गुवाहाटी में प्रवास करने के बजाय तवांग में रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में रहता है - मानवशास्त्रीय और रणनीतिक रूप से सुरक्षित। सरनाथ का यूनेस्को शिलालेख एक अलग लेकिन समान रूप से रणनीतिक स्तर पर चल रहा है। भारत की बौद्ध विरासत इसे एशिया - थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान में हर बौद्ध-प्रमुखता देश से जोड़ती है। ये ऐसे देश हैं जो चीन एक साथ अदालती हैं। जब भारत सरनाथ की प्रशंसा करता है - जहां बौद्ध धर्म शुरू हुआ - विश्व विरासत सूची में, यह एक सभ्य परंपरा पर सांस्कृतिक नेतृत्व पर जोर देता है कि 600 मिलियन एशियाई इसके साथ पहचानते हैं। यह सामरिक गहराई के रूप में नरम शक्ति है: देश जो भारत को अपने आधारिक धर्म के जन्मस्थान और संरक्षक के रूप में देखते हैं, उनके पास एक सांस्कृतिक बंधन है जो उन्हें चीनी प्रभाव के लिए कम संवेदनशील बनाता है। इस सप्ताह पर्यटन हब पृष्ठभूमिer भारत की विदेशी नीति आउटरीच के लिए बौद्ध सर्किट पर्यटन विकास (सरनाथ + बोध गया + कुशीनगर + लुम्बिनी तीर्थयात्रा गलियारे) को स्पष्ट रूप से जोड़ता है - श्रीलंका, थाईलैंड और जापान के प्रधानमंत्री इन साइटों पर जाते हैं; ये यात्राएं केवल राजनयिक संबंधों के बजाय सभ्य सभ्यता को मजबूत करती हैं। इस रणनीति में संरचनात्मक अंतर: सीमांत विकास और न ही विरासत राजनयिकता जल्दी परिणाम देती है। VVP गांवों को वास्तविक रूप से जीवंत होने के लिए 10-15 साल की आवश्यकता होती है; बौद्ध पर्यटन को भारत के कथा से मेल खाने के लिए दशकों के बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता होती है। चीन सीमा क्षेत्रों में 3x भारत की गति पर अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। सांस्कृतिक और विकास उपकरण सही हैं लेकिन उनकी समयरेखा चीन की निर्माण गति के साथ विषम हैं - यह केंद्रीय चुनौती भारत की सीमा विकास-संस्कृति नेक्सस को ईमानदारी से सामना करना पड़ता है।

प्रारंभिक परीक्षा—उत्तर एवं व्याख्या

Q1. उत्तर: (a) 2, 3 और 4

स्पष्टीकरण: कथन 1 गलत है - सरनाथ नहीं है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्ध ने बोधिवृक्ष के तहत बोधगया (बिहार) में ज्ञान प्राप्त किया। सरनाथ जहां उन्होंने अपने पांच शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध तीर्थ स्थल के सवालों में यह सबसे आम भ्रम है। कथन 2 (लियन कैपिटल, नेशनल प्रतीक), 3 (Dhamek Stupa = First Sermon site), और 4 (चार तीर्थ स्थलों: Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath, Kushinagar) सभी सही हैं।

Q2. उत्तर: (b) केवल तीन

स्पष्टीकरण: कथन 4 गलत है - समुद्र मंथन अल्प-अन्वेषित बेसिनों पर केंद्रित है (19 कुल 26 में से 19 अपर्याप्त रूप से अन्वेषित), मुंबई हाई या केजी-D6 पर नहीं, जो पहले से ही अच्छी तरह से विकसित और उत्पादन कर रहे हैं। मुंबई हाई का निर्माण 1976 से हुआ है; इस योजना का

उद्देश्य इन दो ज्ञात उत्पादन बेसिनों की तुलना में अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए है। कथन 1 (EEZ 2.02 मिलियन वर्ग किमी, 10% पर्याप्त रूप से पता लगाया गया), 2 (Rs 84,084 करोड़, 10 साल), और 3 (methane hydrates, अभी तक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं) सही हैं।

Q3. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण: कलपासार परियोजना को गुजरात में खाम्बहट की खाड़ी (जिसे कैमबे की खाड़ी भी कहा जाता है) में नियोजित किया गया है - एक 30 किमी बांध जो ताजे पानी के जलाशय (10,000 एमसीएम) का निर्माण करेगा, ज्वारीय शक्ति उत्पन्न करेगा (5,880 मेगावाट 12 मीटर ज्वारीय रेंज का उपयोग करके), और दक्षिण गुजरात के सौराष्ट्र को जोड़ने वाली सड़क-रेल लिंक प्रदान करता है। Mannar की खाड़ी नहीं (भारत और श्रीलंका के बीच - यह कोरल रीफ्स के साथ एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है)। Palk Strait (प्रस्तावित सड़क-रेल पुल) नहीं। नहीं चिलिका झील (ओडिशा के तटीय झील, रामसर स्थल)।

Q4. उत्तर: (a) 1, 3 और 4

स्पष्टीकरण: कथन 2 गलत है - संशोधन 'राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता के लिए डिजिटल माध्यम से अपमानजनक कृत्यों' का अपराध नहीं करता है; यह वाक्यांश के रूप में समझ नहीं आता है। संशोधन डिजिटल धोखाधड़ी का अपराध करता है और परीक्षाओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक 2026 (इस संक्षिप्त के अनुच्छेद 27) को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजिटल अवरोही का अपराध करता है - छात्र आम तौर पर दो बिलों को उसी सप्ताह पेश करते हैं। कथन 1 (स्टेट एग्जाम शामिल), 3 (NEIB बनाया गया), और 4 (व्यक्तिगत रूप से दंडनीय) परीक्षा संशोधन विधेयक के तहत सभी सही बदलाव हैं।

Q5. उत्तर: (a) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण: कथन 4 गलत है - PM-SSY परिव्यय 5,070 करोड़ रुपये है, 84,084 करोड़ रुपये नहीं है। 84,084 करोड़ रुपये समुद्र मंथन की परिव्यय है। दो कैबिनेट निर्णयों की परिव्यय को स्वीकार करते हुए उसी दिन घोषणा की गई (जुलाई 31) एक क्लासिक MCQ जाल है। कथन 1 (केंद्रीय सरकारी जलाशय सतहों पर फ्लोटिंग सोलर), 2 (BESS + फ्लोटिंग सोलर = 24-घंटे डिस्पैचेबल पावर) और 3 (10-15% वाष्पीकरण में कमी) सभी सही हैं।

Q6. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण: सोवा-रिग्पा तिब्बती, हिमालयी और मंगोलियाई संस्कृतियों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है - सोवा-रिग्पा अधिनियम 2020 के तहत आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्धा के साथ भारत की 5 वीं पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है। कपड़ा तकनीक नहीं। एक जैव विविधता प्रलेखन अभ्यास नहीं है (जो एनबीए के तहत पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर है)। पानी की कटाई प्रणाली नहीं (लाधारा पारंपरिक जल प्रणालियों को 'कुल' या 'zing' कहा जाता है)।

Q7. उत्तर: (b)

स्पष्टीकरण: LegRAA (Legal Research Analysis Assistant) विशेष रूप से एक कानूनी अनुसंधान उपकरण है जो प्राकृतिक भाषा प्रश्नों का उपयोग करके SC/HC निर्णयों से संबंधित पूर्वनिर्धारणों की खोज और संश्लेषण में मदद करता है - जैसे एक बहुत ही जानकार कानूनी सहायक को एक सवाल पूछने और उद्धरण के साथ एक संश्लेषित जवाब प्राप्त करना। यह मामला नहीं दायर करता है (जो eFiling प्रणाली है)। यह अनुपालन की निगरानी नहीं करता है (अलग सिस्टम)। यह वास्तविक समय का अनुवाद नहीं करता है (जो BHASHINI का डोमेन है, अलग से अदालतों में एकीकृत किया जा रहा है)।

Q8. उत्तर: (a) 1, 2 और 3

स्पष्टीकरण: कथन 4 गलत है - BMIP की P&I बीमा कार्गो या पतवार बीमा की जगह नहीं लेता है। पी एंड आई (प्रोटेक्शन एंड क्षतिपूर्ति) ने तीसरे पक्ष को दायित्व (चालक-दल की चोटें, प्रदूषण, अन्य जहाजों को टकराव क्षति); कार्गो बीमा कार्गो के नुकसान को कवर किया; पोत-कवच बीमा (Hull insurance) जहाज को नुकसान पहुंचाता है - ये तीन पूरी तरह से अलग बीमा उत्पाद हैं। BMIP केवल P&I करता है। 1, 2, 3, 3 और 3, BMIP के लॉन्च के लिए सभी सही कारण हैं।

Q9. उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण: Viksit Vibrant गांव कार्यक्रम 2026 को 19 से 46 सीमा जिलों तक विस्तारित किया गया है और अब भारत के संपूर्ण सीमा परिधि को कवर करता है - सभी 7 भूमि सीमाएँ (चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार) प्लस तटीय सीमा जिले - न सिर्फ उत्तरी (चीन) सीमा मूल VVP 2023 के रूप में केंद्रित है। विकल्प (a) इसे उलट देता है - VVP 2023 उत्तर (चीन सीमा) पर केंद्रित है; विक्सित VVP ने सभी को विस्तार दिया। विकल्प (b) और (d) वास्तव में गलत हैं।

Q10. उत्तर: (a) 1, 2 और 4

स्पष्टीकरण: कथन 3 गलत है - पायलटों को राजमार्ग मार्गों को बाहर नहीं करना है। स्पष्ट रूप से उल्लिखित पायलट मार्गों में से एक है पुणे-मुंबई राजमार्ग हाइड्रोजन बसों के लिए - राजमार्गों को विशेष रूप से लंबी दूरी के मार्गों पर परीक्षण रेंज और ईंधन भरने के बुनियादी ढांचे के लिए शामिल किया गया है। अकेले शहरी मार्ग एक व्यापक हाइड्रोजन गतिशीलता नीति के लिए आवश्यक डेटा उत्पन्न नहीं करेगा। विवरण 1 (70 वाहन, 21 मार्ग, 12 राज्यों), 2 (एच 2 एफसीईवी + एचआईसीई + तीन पहिया) और 4 (5 एमएमटी लक्ष्य 2030) सभी सही हैं।